

मुख्य संरक्षक Chief Patron



ए. मणिमेखलै A. Manimekhalai
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO

संरक्षक Patrons



नितेश रंजन
कार्यपालक निदेशक
Nitesh Ranjan
Executive Director



रामसुब्रमणियन एस
कार्यपालक निदेशक
Ramsubramanian S.
Executive Director



संजय रुद्र
कार्यपालक निदेशक
Sanjay Rudra
Executive Director



पंकज द्विवेदी
कार्यपालक निदेशक
Pankaj Dwivedi
Executive Director

मुख्य संपादक Chief Editor



चन्द्र मोहन मिनोचा
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं.)
Chander Mohan Minocha
CGM (HR)



ए. के. विनोद
मुख्य महाप्रबंधक
A.K. Vinod
CGM



अरुण कुमार
मुख्य महाप्रबंधक
Arun Kumar
CGM



विठ्ठल बनशंकरी
महाप्रबंधक
Vithal Banashankari
GM

संपादकीय सलाहकार Editorial Advisors

संपादकीय सलाहकार Editorial Advisors



अम्बरीष कुमार सिंह
उप महाप्रबंधक (मा.सं.)
Ambarish Kumar Singh
DGM (HR)



विवेकानंद
सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.)
Vivekanand
AGM (OL)

संपादक Editor



गायत्री रवि किरण
मुख्य प्रबंधक (रा.भा.)
Gayathri Ravi Kiran
CM (OL)

संपादकीय सहयोग Editorial Support



जागृति उपाध्याय
सहा. प्रबंधक (रा.भा.)
Jagriti Upadhyay
Asst. Manager (OL)



एम. एस. ठाकुर
सहा. प्रबंधक (रा.भा.)
Mohit Singh Thakur
Asst. Manager (OL)

परिदृश्य PERSPECTIVE



प्रिय यूनियनाइट्स,

मुझे प्रसन्नता है कि 'यूनियन धारा' का यह नवीनतम अंक अनर्जक आस्ति (एनपीए) प्रबंधन के महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित है। बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए एक मजबूत एनपीए प्रबंधन कार्यनीति की आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करने के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में, भारत की बैंकिंग प्रणाली ने संरचनात्मक सुधारों, मजबूत ऋण निगरानी और सक्रिय समाधान तंत्रों से समर्थन प्राप्त कर एनपीए में उल्लेखनीय कमी देखी है। मजबूत आस्ति गुणवत्ता और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन से निर्मित एक सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली, संवहनीय विकास और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की कुंजी है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, हमने अपने एनपीए प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरुआती पहचान, रणनीतिक वसूली प्रयासों और प्रभावी समाधान तंत्र के माध्यम से निर्णायक कदम उठाए हैं। समर्पित आस्ति वसूली और दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएँ खोली गई हैं, जिनमें तैनात विशेष वसूली कार्यबल वसूली पहलों को कारगर बनाते हैं। हमारे क्षेत्रीय और अंचलीय वसूली केंद्र दबावग्रस्त आस्तियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि कॉल सेंटर संचालन उधारकर्ताओं के साथ निरंतर जुड़ाव सुनिश्चित करते हैं। हामीदारी मानकों में सुधार के उद्देश्य से हमने केंद्रित ऋण निगरानी के केंद्रीकरण और वर्टिकलाइजेशन को मजबूत किया है, खुदरा, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों के लिए समर्पित प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किए हैं, और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन आदि की निगरानी के लिए एक लेनदेन निगरानी वर्टिकल प्रारंभ किया है।

'यूनियन धारा' का यह अंक एनपीए प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं, चुनौतियों और सफलता की कहानियों पर विचार करने के लिए एक मूल्यवान मंच प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि यहाँ साझा की गई अंतर्दृष्टि यूनियनाइट्स को मजबूत आस्ति गुणवत्ता बनाए रखने और बैंक की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता में योगदान देने के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सशक्त बनाएगी। मैं इस व्यावहारिक विशेषांक के प्रकाशन हेतु यूनियन धारा टीम के समर्पण की सराहना करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह विशेषांक सभी हितधारकों के लिए एक उत्कृष्ट संदर्भ के रूप में उपयोगी होगा।

शुभकामनाओं सहित,

ए. मणिमेखलै
एमडी एवं सीईओ

Dear Unionites,

I am pleased to note that the latest issue of 'Union Dhara' focuses on the critical topic of Non-Performing Asset (NPA) management. A robust NPA management strategy is essential for the stability and growth of the banking sector, ensuring that financial resources are effectively deployed to drive economic progress. Over the years, India's banking system has witnessed a significant reduction in NPAs, supported by structural reforms, strengthened credit monitoring, and proactive resolution mechanisms. A resilient financial system, built on strong asset quality and prudent risk management, is key to fostering sustainable growth and financial inclusion.

At Union Bank of India, we have taken decisive steps to reinforce our NPA management framework through early detection, strategic recovery efforts, and effective resolution mechanisms. Dedicated Asset Recovery and Stressed Asset Management branches have been set up to streamline recovery initiatives, supported by a specialized Recovery Action Force to accelerate resolution. Our Regional and Zonal Collection Centres play a crucial role in reducing stressed assets, while call centre operations ensure continuous engagement with borrowers. To further enhance underwriting standards, we have strengthened centralization and verticalization for focused credit monitoring, established dedicated processing centres for Retail, MSME, and Agri sectors, and introduced a Transaction Monitoring Vertical to oversee early warning signals, fraud risk management etc.

This issue of 'Union Dhara' provides a valuable platform to reflect on best practices, challenges, and success stories in NPA management. I am confident that the insights shared here will empower Unionites to reinforce their efforts in maintaining a strong asset quality and contributing to the Bank's long-term financial stability. I appreciate the *Union Dhara* team for their dedication in bringing out such an insightful special issue and hope it serves as an excellent reference for all stakeholders.

With best regards,

A. Manimekhalai
MD & CEO

अवलोकन Overview



प्रिय यूनियनाइट्स,

'यूनियन धारा' के इस अंक के माध्यम से आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 'यूनियन धारा' का यह अंक एनपीए प्रबंधन एवं वसूली पर केंद्रित है। एनपीए प्रबंधन अवश्य ही बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू है और हमारे बैंक के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। आस्ति गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण वित्तीय सूचकांक है। हम अपने वित्तीय कार्यनिष्पादन को प्रभावित करने में एनपीए के महत्व को पहचानते हैं और इस चुनौती का सामना करने के लिए समर्पित हैं।

ऋण पोर्टफोलियो में एमएसएमई अत्यंत महत्वपूर्ण है। एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, और यह आवश्यक है कि हम उनकी प्रगति और विस्तार के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करें। हमारे बैंक ने एमएसएमई को ऋण सुपुर्दगी के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण से यूएमएफबी शाखाएं खोली हैं। मैं सभी यूएमएफबी शाखा प्रमुखों से आग्रह करता हूँ कि एमएसएमई ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करें और उनके विकास का समर्थन करने के लिए नए अवसरों की खोज करें।

आज के डिजिटल युग में, सूचना सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। एक बैंकर के रूप में, अपने ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी के संरक्षण और हमारे सिस्टम और प्रक्रियाओं को अवांछित तत्वों से सुरक्षित रखना सभी स्टाफ सदस्यों की जिम्मेदारी है।

यह ज़रूरी है कि हम सभी मानकों के अंतर्गत अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित रखें। आइए, हम अथक प्रयासों से अपने लक्ष्यों को पूरा करें और उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन दर्ज करें।

एक बार फिर, मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और बैंक को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए साथ मिलकर काम करें।

Dear Unionites,

I am delighted to address all of you through this issue of 'Union Dhara'.

I am pleased to note that this issue of 'Union Dhara' is focussed on NPA Management and Recovery. NPA management is definitely a very significant aspect of Banking and a top priority for our Bank. Asset Quality is one of the important Financial Indicators. We recognize the significance of NPAs in affecting our financial performance and are dedicated to addressing this challenge head-on.

MSME sector is a significant part of the Credit portfolio. MSMEs are the backbone of our economy, and it is essential that we provide them with the necessary financial support to grow and thrive. Our bank has opened UMFb branches to have focussed approach towards credit delivery to MSMEs. I urge the UMFb Branch heads to provide exceptional service to MSME customers and to explore new opportunities to support their growth.

In today's digital age, information security is of paramount importance. As a banker, all staff members have a responsibility to protect our customers' sensitive information and secure our systems and processes from unscrupulous elements.

It is essential that we remain focused on achieving our targets under all parameters. Let us work tirelessly to ensure that we meet our targets and register excellent performance.

Once again, I urge one and all to come together to achieve our goals and elevate our Bank to Excellence.

शुभकामनाओं सहित, With best regards,

नितेश रंजन Nitesh Ranjan
कार्यपालक निदेशक Executive Director

अवलोकन Overview



प्रिय यूनियनाइट्स,

‘एनपीए प्रबंधन एवं वसूली’ विशेषांक के माध्यम से आप सभी के साथ मेरे विचार साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में बैंक ने उल्लेखनीय उपलब्धि और प्रगति दर्ज करते हुए महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया है। तथापि, हम अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट होकर रुक नहीं सकते हैं। हमें नई चुनौतियों के समाधान और नए अवसरों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ना है। यह ज़रूरी है कि हम अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखें।

इस तिमाही के दौरान हमें एकाग्रता से अपने कारोबारी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान देना होगा। हमें जमा खासकर कासा, अग्रिम और लाभ में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना होगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने काम में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें, नवाचार करें और नए दृष्टिकोण से सोचें, तथा बैंक के ग्राहकों को अद्वितीय सेवा प्रदान करें।

बैंकिंग उद्योग के समक्ष अनर्जक आस्तियां (एनपीए) एक प्रमुख चुनौती बनी हुई हैं। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में बैंकों को उनकी वसूली क्षमता के आधार पर पहचाना जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि ‘यूनियन धारा’ का यह अंक ‘एनपीए प्रबंधन एवं वसूली’ विशेषांक के रूप में तैयार की गई है। एक स्वस्थ बैलेंस शीट बनाए रखने और कारोबार वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए प्रभावी एनपीए प्रबंधन और वसूली महत्वपूर्ण है। हमारी टीम एनपीए की पहचान, प्रबंधन और वसूली के लिए मजबूत रणनीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ मिलकर, हम एनपीए के प्रभाव को कम कर सकते हैं और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से हम बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और अपने बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

Dear Unionites,

I am thrilled to share my thoughts with all of you through the special issue on ‘NPA Management and Recovery’.

The first three quarters of the financial year has been a remarkable journey for our bank, marked by significant achievements and growth. However, we cannot rest on our laurels. We should manage new challenges and leverage new opportunities. It is essential that we stay focused on our goals and objectives.

Our only focus during this quarter should be on achieving our business targets. We must exceed the targets for growth in deposits especially CASA, advances, and profits, and it is essential that we work together to achieve these targets. I urge every one of you to strive for excellence in your work, to innovate and think outside the box, and to provide exceptional service to our bank’s customers.

Non-Performing Assets (NPAs) remain a key challenge faced by the banking industry. According to me, in the coming days, banks will be differentiated on the basis of their collection efficiency. I am pleased to note that this issue of ‘Union Dhara’ is being printed as a special issue on ‘NPA Management and Recovery.’ Effective NPA management and recovery are crucial to maintaining a healthy balance sheet and driving business growth. Our team is committed to implementing robust strategies to identify, manage, and recover NPAs. Together, we can mitigate the impact of NPAs and drive long-term success.

I am confident that with our collective efforts, we can achieve great things and take our bank to new heights.

शुभकामनाओं सहित, With best regards,

राम
राम

रामसुब्रमणियन एस. Ramasubramanian S
कार्यपालक निदेशक Executive Director

अवलोकन Overview



प्रिय यूनियनाइट्स,

मुझे प्रसन्नता है कि 'यूनियन धारा' के इस अंक को 'एनपीए प्रबंधन एवं वसूली' विशेषांक के रूप में तैयार किया गया है. बैंकिंग के महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषांक तैयार करने हेतु मैं यूनियन धारा टीम के प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ.

हमें अनर्जक आस्तियों को कम करने और अपने ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में सुधार करने को प्राथमिकता देनी होगी. हमारे बैंक ने वसूली प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और स्वचालन के लिए 'यूनियन सरस' का शुभारंभ किया है. इस सॉफ्टवेयर से ऋण वसूली प्रयास व्यवस्थित होती है और संभावित वसूली माध्यमों को पहचानने तथा चुनौतियों को कम करने के लिए अनुकूल तंत्र उपलब्ध होता है.

आज के गतिशील बैंकिंग परिवेश में, अनर्जक आस्तियां (एनपीए) बैंक की वित्तीय स्थिरता, चलनिधि और लाभप्रदता के लिए बड़ी चुनौती है. एनपीए न केवल बैंक के कार्य-निष्पादन में बाधक हैं, बल्कि पूंजी के उत्पादक प्रवाह को बाधित करके व्यापक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं. मजबूत बैलेंस शीट बनाए रखने, निवेशकों का विश्वास बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी एनपीए वसूली महत्वपूर्ण है. इसे समझते हुए बैंक ने व्यापक वसूली तंत्र को अपनाया है.

फिर भी, इन तंत्रों की सफलता केवल नीतियों और प्रक्रियाओं पर ही नहीं बल्कि बैंक की सबसे मूल्यवान संपत्ति- यानी आप सभी की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है. चुनौतीपूर्ण समय में भी, फ्रंटलाइन कर्मचारी, रिकवरी विशेषज्ञ और सहायता दल, वसूली कार्यनीतियों को लागू करने, लगातार फॉलो-अप सुनिश्चित करने और ग्राहक जुड़ाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. संभावित नुकसान को नए वित्तीय मजबूती के अवसरों में बदलने के लिए आपकी प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता और सक्रिय दृष्टिकोण आवश्यक है.

आइए, हम अपनी उपलब्धियों पर मनन करें, नए लक्ष्य निर्धारित करें तथा अपने प्रयासों में और अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लें.

Dear Unionites,

I am pleased to note that this issue of 'Union Dhara' is brought forth as a special issue on NPA Management and Recovery. I appreciate the efforts of 'Union Dhara' Team in bringing out special issues on important banking topics.

We need to prioritize reducing our non-performing assets and enhancing the overall quality of our loan portfolio. Our bank has introduced 'Union SARAS' for digitizing and automation of Recovery process. This software enables streamlining of our recovery processes and creation of an ecosystem for tapping potential recovery channels and mitigation of challenges.

In today's dynamic banking environment, Non-Performing Assets (NPAs) continue to pose significant challenges to financial stability, liquidity, and profitability of the bank. NPAs not only hinder individual banks' performance but also impact the broader economy by impeding the productive flow of capital. Recognizing that effective NPA recovery is vital to maintain robust balance sheets, enhance investor confidence, and foster economic growth, bank has adopted comprehensive recovery mechanisms.

Yet, the success of these mechanisms hinges not merely on policies and processes but on the active engagement of the bank's most valuable asset-that's You. Frontline employees, recovery specialists, and support teams are pivotal in implementing recovery strategies, ensuring diligent follow-up, and customer engagement even in challenging times. Your commitment, expertise, and proactive approach are essential in transforming potential losses into opportunities for renewed financial strength.

Let us reflect on our accomplishments, re-evaluate our goals, and move forward with drive and motivation.

शुभकामनाओं सहित, With best regards,

संजय रुद्र

संजय रुद्र Sanjay Rudra

कार्यपालक निदेशक Executive Director

अवलोकन Overview



प्रिय यूनियनाइट्स,

आप सभी को मेरा नमस्कार. आशा है कि आप स्वस्थ तथा प्रसन्नचित्त होंगे.

मुझे बैंक की प्रतिष्ठित कांफ़ेरेट गृह-पत्रिका 'यूनियन धारा' के इस अंक के माध्यम से अपने विचार साझा करते हुए खुशी हो रही है.

एनपीए प्रबंधन तथा वसूली के महत्व को रेखांकित करते हुए 'यूनियन धारा' के अद्यतन अंक को एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है. वित्तीय वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान आस्ति गुणवत्ता की निगरानी तथा प्रभावी वसूली कार्यनीति के कारण बैंक की अनर्जक आस्तियों में काफी कमी आई है. हमें इस गति को बनाए रखने और एनपीए के स्तर को और घटाने के लिए लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए.

साथ ही, ऋण पोर्टफोलियो की विविधता और आस्ति गुणवत्ता में सुधार से बैंक की लाभप्रदता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.

ग्राहक केंद्रितता बैंक के प्रमुख मूल्यों में से एक है. ग्राहक के साथ किया गया प्रत्येक परस्पर संवाद हमें सकारात्मक प्रभाव डालने का अवसर प्रदान करता है. वर्तमान में, तेजी से विकसित हो रहे बैंकिंग परिदृश्य में, ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है.

जमा राशियों में बढ़ोत्तरी के लिए ग्राहक आधार को मजबूत बनाने की ज़रूरत है. इसके लिए हमें अपने जमा उत्पादों की आकर्षक विशेषताओं का प्रचार और जमा संग्रहण के ठोस प्रयास करने चाहिए.

हमें थर्ड-पार्टी उत्पादों के विपणन में तेजी लाने और ब्याजेतर आय बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता है. जब हम अपने कॉर्पोरेट लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो अनुपालन प्रथाओं को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए. 'रेगुलेशन-प्लस' दृष्टिकोण को अपनाने से अनुपालन केवल विनियामक अपेक्षाओं का पालन नहीं होगा बल्कि विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करके उनसे भी आगे निकल जाएगा. इससे हम अपनी अनुपालन संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं और अपने सभी हितधारकों का विश्वास अर्जित कर सकते हैं.

मुझे आशा है कि यह पत्रिका सभी कर्मचारियों के लिए एक मूल्यवान स्रोत के रूप में कार्य करेगी और हमारे बैंक को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी.

शुभकामनाओं सहित,

Dear Unionites,

My Greetings to all. I hope this message finds you well and in good spirits.

It gives me immense pleasure to share my views through this issue of the Bank's esteemed in-house Magazine 'Union Dhara'.

The present issue of 'Union Dhara' is printed as a Special issue by highlighting the importance of NPA Management and Recovery. During the first 3 quarters of the current financial year, NPAs have significantly reduced because of monitoring of asset quality and effective recovery. We should maintain this tempo while continuing our efforts to further reduce NPA levels.

Further, diversification of the credit portfolio and improvement in Asset quality will have a positive impact on the Bank's profitability.

Customer centricity is one of the core values of the Bank. Each interaction with a customer is an opportunity to make a positive impact. In today's rapidly evolving banking landscape, meeting customer expectations is vital than ever before.

We need to strengthen and deepen our customer franchise for increase in Deposits. To this end, we must publicise the attractive features of our deposit schemes and make efficient efforts for Deposit Mobilization.

We need to accelerate marketing of third-party products and make all out efforts for increasing non-interest income. While we strive to achieve our corporate targets, compliance practices shall also be given due importance. Adopting a 'Regulation-Plus' approach, whereby compliance shall go beyond mere adherence to regulatory requirements, thus shall not only meet but exceed regulatory expectations. With this, we can strengthen our compliance culture and earn the trust of all our stakeholders.

I hope that this magazine serves as a valuable resource for all employees and take our Bank to greater heights.

With best regards,

पंकज द्विवेदी Pankaj Dwivedi

कार्यपालक निदेशक Executive Director

संपादकीय EDITORIAL

प्रिय पाठकगण,

हम 'एनपीए प्रबंधन एवं वसूली' पर विशेष रूप से केंद्रित 'यूनियन धारा' का यह विशेषांक सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

इस अंक से हम 'अवलोकन' शीर्षक के अंतर्गत हमारे कार्यपालक निदेशकों के विचार और राय अपने पाठकों के साथ साझा कर रहे हैं। यह हमारे लिए सम्मान का विषय है। इस बहुमूल्य खंड से हमारी गृह पत्रिका का मूल्यवर्धन हुआ है।

इस अंक में आस्ति गुणवत्ता बनाए रखना, स्लिपेज का निवारण, एनपीए का अपग्रेडेशन, बैंकों को उपलब्ध विभिन्न वसूली उपाय और कानूनी अधिकारों के संबंध में हमारे स्टाफ सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रोचक लेखों की शृंखला के माध्यम से विस्तार में चर्चा की गई है। एनपीए का प्रभाव, चूककर्ता पक्ष से निपटान हेतु अपनाई गई प्रक्रिया में बदलते ट्रेंड और एनपीए निवारण उपायों को उचित महत्व देते हुए एनपीए प्रबंधन के इन पहलुओं को विशेषांक के लेखों में विस्तार से कवर किया गया है।

एनपीए प्रबंधन एवं वसूली पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समग्र अंक प्रकाशित करने के प्रयास के साथ-साथ हमने सामान्य रुचि के लेख और स्थायी स्तंभ भी इस अंक में प्रकाशित किए हैं।

इस अंक के सेंटर स्प्रेड में शहीद द्वीप के स्वच्छ समुद्री तट की झलक दी गई है। प्रतियोगिता का विचारोत्तेजक चित्र स्टाफ के सृजनात्मक आवेग को प्रेरित करते हुए उस पल के लिए उचित शीर्षक लेखन आमंत्रित करता है। फेस इन यूबीआई क्राउड के अंतर्गत हमारे स्टाफ सदस्यों द्वारा अपने निजी आकांक्षाओं के अनुसरण में हासिल उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं तो 'हमें गर्व है' स्टाफ तथा उनके बच्चों की उपलब्धियों का अभिनंदन करता है। हम अपने सेवानिवृत्त स्टाफ की रचनाओं को 'सेवानिवृत्त जीवन से' के विशेष खंड के अंतर्गत प्रकाशित करते हुए उनकी सृजनात्मकता को सलाम करते हैं।

विशेषांक से संबंधित लेख तथा सामान्य रुचि के अन्य लेख हमें प्रेषित कर इस यात्रा में हमारा समर्थन करने हेतु हमारे लेखकों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। हमें बड़ी संख्या में प्राप्त लेखों में से चयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु हम श्री दीपक सक्सेन, उप महाप्रबंधक, एसएएमवी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। इस अंक के रूप और शैली को निखारने में हमारे संपादकीय सलाहकारों के प्रभावपूर्ण समर्थन और मार्गदर्शन हेतु हम कृतज्ञ हैं।

हमें आशा है कि 'एनपीए प्रबंधन एवं वसूली' का यह विशेषांक आपको रुचिकर लगेगा। हम इस अंक के बारे में आपकी राय तथा मूल्यवर्धन हेतु आपके सुझाव का लाभ पाने की इच्छा रखते हैं, अतः हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें।

भवदीया, Yours sincerely,

(गायत्री रवि किरण) (Gayathri Ravi Kiran)

Dear Readers,

We are happy to present the latest issue of 'Union Dhara' with special focus on 'NPA Management and Recovery'.

Starting with this issue, we are extremely honoured to incorporate 'Overview', wherein our Executive Directors share their thoughts and views with our readers. This invaluable feature enhances the value of our house magazine.

Maintaining asset quality, prevention of slippage, upgradation of NPAs, various recovery measures and legal recourse available to banks are discussed in this issue through an array of compelling articles presented by our staff members. These aspects of NPA Management have been extensively covered in the articles duly highlighting the impact of NPAs, changing trends in the approach adopted for dealing with defaulting parties and preventive measures.

We have attempted to bring forth a holistic issue focussing on the topic of NPA Management and recovery. Simultaneously, we have also incorporated articles of general interest and regular features.

This issue's Center Spread features the pristine beaches of Shahid Dweep. The intriguing Contest Photo caters to the creative spurt of our staff and invites captions which best capture the moment. 'Face in UBI Crowd' celebrates the achievements of our staff members in pursuit of their personal passion, while 'Hamein garv hai' commemorates the achievements of staff as well as their wards. We honour the creative spirit of our retired staff by publishing their contributions under a special feature titled 'Sevanivritt Jeevan se'.

We thank our writers for supporting us in this journey by sending entries on the topics of the special issue as well as various other topics of general interest. We express our gratitude to Shri Deepak Saxena, DGM, SAMV for providing guidance in selection of articles from the multitude of entries received. We are grateful for the vital support and guidance of the editorial advisors in shaping the form and style of this issue.

We hope that this Special issue on "NPA Management and Recovery" makes for an interesting read. We wish to benefit from your opinion regarding this issue and suggestions for further improvement. So kindly do send us your response.

अनुक्रमणिका Contents

▶ विदाई, शुभमस्तु, शिखर की ओर	1
▶ पुरस्कार और सम्मान	2
▶ एनपीए वसूली और प्रबंधन में वार्ता कौशल की भूमिका	3
▶ एनपीए प्रबंधन में डिजिटल तकनीक का प्रयोग	5
▶ सरफेसिया-वसूली का रामबाण उपाय	7
▶ एनपीए प्रबंधन के लिए बाहरी एजेंसियों का प्रभावी उपयोग	9
▶ कविता: बैंकर और रिक्वरी	10
▶ सीएसआर तथा एम्पावर हर गतिविधियां	11
▶ Navigating the Choppy Waters	13
▶ Role of NPA Recovery in Bank's Profitability	16
▶ NPA Management in Banks	19
▶ Challenges faced by Banks in Dept Recovery Through DRTs	21
▶ अंचल कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 106वां स्थापना दिवस समारोह	23
▶ Impact of NPA's on Indian Economy	25
▶ हमें गर्व है- शहीद द्वीप	27
▶ Alternate Dispute Resolution Mechanism	28
▶ Impact of IBC on Resolving Corporate Insolvency	31
▶ सेंटर स्प्रेड	33
▶ Tackling Wilful Defaulters - from Default to Public Accountability	35
▶ कविता: नव वर्ष	37
▶ Tools and Techniques for NPA Management & Recovery	38
▶ POEM: In the Eye of Hurricane	40
▶ Enhancing Loan Portfolio Health with SMA	41
▶ यूनियन धारा एवं यूनियन सृजन संवाददाता समीक्षा बैठक सह सम्मेलन- 2024	43
▶ SARFAESIA-A Panacea for Recovery	45
▶ Data Integrity & Adequacy in Prevention & Recovery of NPAs	47
▶ Bad Bank and NARCL	49
▶ POEM: A Beautiful Life, A Secret life	51
▶ प्रतियोगिता Contest- 172	52
▶ उद्घाटन	53
▶ समय प्रबंधन: सफलता का मूल मंत्र	56
▶ कविता: एनपीए एक छिपा हुआ दर्द	58
▶ फेस इन यूबीआई क्राउड: सेलिग चैंपियन- अनिरुद्ध	59
▶ कविता: कुछ बातें	60
▶ सेवानिवृत्त जीवन से – Impact of Technology in Banking	61
▶ कविता: समुद्र को प्याले में भर कर लाया आप के लिए	62
▶ समाचार	63
▶ आपकी पाती	73

ई-मेल E-mail: uniondhara@unionbankofindia.bank | gayathri.ravikiran@unionbankofindia.bank

Tel.: 022-41829288 | Mob.: 9849615496

यूनियन धारा में प्रकाशित लेख आदि में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं और प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है.

The views expressed in the articles published in Union Dhara are solely that of the author and do not necessarily reflect the views of the management.

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आंतरिक परिचालन हेतु प्रकाशित.

Published by Union Bank of India for internal circulation

विदाई



श्री सूरज श्रीवास्तव 21, दिसंबर 2021 से 20, दिसंबर 2024 तक बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के पद पर कार्यरत रहे. आपको कराधान एवं लेखा परीक्षा में सनदी लेखाकार (सीए) के रूप में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान श्री श्रीवास्तव बैंक की लेखा परीक्षण समिति के अध्यक्ष भी रहे. दिनांक 20.12.2024 को कार्यावधि की समाप्ति पर श्री श्रीवास्तव को सम्मानित करती हुई सुश्री ए. मणिमेखलै, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ.

शिखर की ओर...

उप महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नति पर हार्दिक बधाई



जयदेव नागर



ऋषिकेश कुमार



सी. वी. सुधीर

हम आपके नेतृत्व में बैंक के उज्वल भविष्य की कामना करते हैं.

शुभमस्तु...



सुशील कुमार पाणिग्रही
उप महाप्रबंधक



ए. रवि कुमार
उप महाप्रबंधक



एन श्रीनिवास राव
उप महाप्रबंधक

हम आपके सुखद एवं सक्रिय सेवानिवृत्त जीवन की कामना करते हैं.

पुरस्कार एवं सम्मान



दिनांक 16.10.2025 को ओरस इंफोसिस फिनेकल बैंकिंग अवार्ड 2024 द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यूनियन एक्सेस, जोकि इंकलूसिव बैंकिंग सोल्यूशंस सहित दिव्यांग तथा वृद्ध जनों को इम्पार करता है, के लिए कांस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री अनिल कुरिल, सीटीओ.



दिनांक 22.10.2025 को एशियन लीडरशिप अवार्ड 2024 द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को अपने विजन और नवोन्मेषन हेतु दो श्रेणी यथा ऑर्गनाइजेशन विथ इनोवेटिव एचआर प्रेक्टिस तथा एक्जेम्प्लेरी लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया. पुरस्कार प्राप्त करते हुए श्री के. एस. डी. शिव वर प्रसाद, महाप्रबंधक.



दिनांक 25.11.2024 को अपेक्स इंडिया अवार्ड 2024 द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को एचआर एक्सिलेन्स हेतु प्लेटिनम पुरस्कार तथा ट्रेनिंग एक्सिलेन्स हेतु स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया.



दिनांक 09.11.2024 को पब्लिक रिलेशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा 14वें एक्सिलेन्स अवार्ड्स के अंतर्गत बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका 'यूनियन सृजन' को रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया. श्री ए.के. विनोद, मुख्य महाप्रबंधक तथा श्रीमती गायत्री रविकिरण, संपादक ने बैंक की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया.



नवंबर, 2024 में सेविवो हॉकी फ़ाउंडेशन द्वारा आयोजित सेविवो सुपर 05-2024 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की महिला हॉकी टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ.

एनपीए वसूली और प्रबंधन में वार्ता कौशल की भूमिका

बैंकिंग क्षेत्र किसी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसे एनपीए प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एनपीए ऐसे ऋण या अग्रिम हैं जो उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान न किए जाने के कारण बैंकों के लिए आय उत्पन्न नहीं करते हैं। वित्तीय स्थिरता और लाभप्रदता बनाए रखने के लिए इन आस्तियों की प्रभावी वसूली आवश्यक है। एनपीए वसूली प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक बातचीत कौशल है। एनपीए वसूली प्रयासों में शामिल बैंक अधिकारियों के लिए बातचीत कौशल आवश्यक है। प्रभावी बातचीत से बैंक और उधारकर्ता दोनों के लिए बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कारण दिए गए हैं कि बातचीत कौशल क्यों महत्वपूर्ण है:

♦ **संबंध निर्माण:** बातचीत का मतलब सिर्फ सहमति बनाना नहीं है; इसका मतलब संबंध बनाना भी है। प्रभावी वार्ताकार सद्भावना और मूल्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे उधारकर्ताओं के साथ दीर्घकालिक साझेदारी हो सकती है। संबंध बनाने का यह पहलू एनपीए वसूली में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां विश्वास बैंकों और उधारकर्ताओं के बीच बेहतर संचार और सहयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है।

♦ **अनुकूलित समाधान विकसित करना:** अच्छे बातचीत कौशल से बैंक अधिकारी ऐसे समाधान तैयार कर सकते हैं जो दोनों पक्षों के लिए संतोषजनक हों। उदाहरण के लिए, वे नई पुनर्भुगतान शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाना या ब्याज दरों को कम करना, जिससे उधारकर्ताओं के लिए अपने दायित्वों को पूरा करना आसान हो जाता है। यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण आगे की चूक को रोक सकता है और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है।

♦ **आगामी विवादों का समाधान करना:** बातचीत के ज़रिए परस्पर सहमत समाधान तक

पहुँचकर, बैंक उधारकर्ताओं के साथ भविष्य में होने वाले विवादों की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। जब दोनों पक्षों को लगता है कि बातचीत के दौरान उनकी बात सुनी और समझी गई है, तो वे सहमत शर्तों का पालन करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण एक स्वस्थ ऋण पोर्टफोलियो बनाए रखने में मदद करता है।

♦ **रिकवरी दर में सुधार और वृद्धि करना:** प्रभावी बातचीत से एनपीए पर वसूली की दर बढ़ सकती है। उधारकर्ताओं से बातचीत करके और उनकी परिस्थितियों को समझकर, बैंक पुनर्भुगतान के लिए व्यवहार्य विकल्पों की पहचान कर सकते हैं, जिन पर शुरू में विचार नहीं किया गया होगा। इस लचीलेपन के परिणामस्वरूप बकाया ऋण का एक बड़ा हिस्सा वसूला जा सकता है।

एनपीए वसूली में बातचीत कौशल की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए, बैंकों को कई रणनीतियों को लागू करना चाहिए:

♦ **पूर्व तैयारी:** बातचीत शुरू करने से पहले, बैंक अधिकारियों को अपने उद्देश्यों और उधारकर्ता की स्थिति को समझकर पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। इस तैयारी में शामिल हैं:

- उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण
- समझौते के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान
- वार्ता प्रक्रिया के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित

♦ **ध्यानपूर्वक सुनना:** सक्रिय रूप से सुनना प्रभावी बातचीत का एक महत्वपूर्ण घटक है। बैंक अधिकारियों को उधारकर्ता के दृष्टिकोण और चिंताओं को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल सद्भावना को बढ़ावा देता है बल्कि संभावित समाधानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी प्रदान करता है जो दोनों पक्षों के लिए काम कर सकते हैं।

♦ **लचीलापन और रचनात्मकता:** वार्ताकारों को लचीला होना चाहिए और रचनात्मक समाधानों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसमें विभिन्न पुनर्भुगतान विकल्पों की खोज करना या ऋण को ऐसे तरीकों से पुनर्गठित करना शामिल हो सकता है जो उधारकर्ता की क्षमताओं के साथ संरेखित हों और साथ ही बैंक के हितों की रक्षा भी करें। शुरुआत में ही कई समाधान पेश करने से बातचीत में तेज़ी आ सकती है और किसी समझौते पर पहुँचने की संभावना बढ़ सकती है।

♦ **स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करना:** बातचीत के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करने से चर्चा को केंद्रित और उत्पादक बनाए रखने में मदद मिलती है। समय-सीमा निर्धारित करने से, दोनों पक्षों को तुरंत समाधान पर पहुँचने के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे लंबे समय तक अनिश्चितता को रोका जा सकता है जो एनपीए की स्थिति को और खराब कर सकता है।

♦ **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** बैंकों को अपनी बातचीत प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स टूल जोखिम वाले खातों को पहले से पहचानने में मदद कर सकते हैं, जिससे बैंक अधिकारी अनर्जक होने से पहले उधारकर्ताओं से सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म बातचीत के दौरान संचार को सुविधाजनक बना सकते हैं और प्रलेखीकरण को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।

एनपीए वसूली वार्ता में चुनौतियाँ

♦ **कानूनी बाधाएं:** एनपीए से संबंधित कानूनी ढांचा बातचीत को जटिल बना सकता है। बैंकों को दिवालियापन और दिवालियापन संहिता जैसे कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ऋण वसूली से संबंधित विनियमों को समझना चाहिए। प्रभावी बातचीत के लिए इन कानूनी पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है।

♦ **भावनात्मक कारक:** एनपीए से जुड़ी बातचीत में अक्सर भावनात्मक तत्व शामिल होते हैं, खासकर तब जब उधारकर्ता वित्तीय संकट का सामना करते हैं. बैंक अधिकारियों को अपने उद्देश्यों पर दृढ़ रहते हुए इन चर्चाओं को सहानुभूति के साथ करना चाहिए. सफल परिणामों के लिए व्यावसायिक कौशल के साथ करुणा का संतुलन आवश्यक है.

♦ **उधारकर्ताओं का प्रतिरोध:** उधारकर्ता अपने विकल्पों के बारे में डर या गलतफहमी के कारण बातचीत का विरोध कर सकते हैं. इन चिंताओं को दूर करने और बातचीत प्रक्रिया के दौरान सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है.

एनपीए वसूली प्रबंधन में बैंकों के लिए उत्तम अभ्यास

बातचीत कौशल के माध्यम से एनपीए को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, बैंकों को सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना चाहिए जो उनके वसूली प्रयासों को बढ़ाएँ:

♦ **समय से पहले हस्तक्षेप:** प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लागू करने से बैंकों को संभावित एनपीए की पहचान करने में मदद मिलती है, इससे पहले कि वे बढ़ जाएँ. इस स्तर पर उधारकर्ताओं के साथ बातचीत करने से ऋणों के पुनर्गठन या सहायता की पेशकश करने के उद्देश्य से सक्रिय बातचीत करने में मदद मिलती है.

♦ **स्टाफ प्रशिक्षण:** एनपीए वसूली में शामिल कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना आवश्यक है. इन कार्यक्रमों में बातचीत कौशल विकसित करने, उधारकर्ता के मनोविज्ञान को समझने और संचार क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए. अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारियों को बातचीत के दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त करने की अधिक संभावना है.

♦ **सहयोगात्मक दृष्टिकोण:** बैंकों को बाहरी हितधारकों, जैसे कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) और विनियामक निकायों के साथ सहयोगात्मक संबंध विकसित करने चाहिए. सर्वोत्तम प्रथाओं और अंतर्दृष्टि को साझा करने से एनपीए को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बेहतर रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं.

♦ **सतत निगरानी:** बातचीत के बाद उधारकर्ता के कार्य-निष्पादन की नियमित निगरानी करना सहमत शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है. बैंकों को पुनर्भुगतान पर नज़र रखने और किसी भी मुद्दे को तुरंत हल करने के लिए सिस्टम स्थापित करना चाहिए

समझौते का सर्वोत्तम विकल्प और वार्ता में इसकी भूमिका

समझौते का सर्वश्रेष्ठ विकल्प, BATNA सबसे लाभदायक विकल्प है जिसे वार्ताकार तब अपना सकता है जब वार्ता के दौरान कोई समझौता न हो. यह अनिवार्य रूप से एक सुरक्षा जाल है, जो एक ऐसा विकल्प प्रदान करता है जो वार्ताकारों को केवल समझौते तक पहुँचने के लिए प्रतिकूल शर्तों को स्वीकार करने से बचने में मदद करता है. समझौते के सर्वश्रेष्ठ विकल्प को जानकर, वार्ताकार इस बारे में सूचित निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें टेबल पर मौजूद प्रस्तावों को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है.

समझौते के सर्वश्रेष्ठ विकल्प को समझने के मुख्य लाभ

• **वार्ता क्षमता में वृद्धि:** एक मजबूत सर्वश्रेष्ठ विकल्प वार्ताकार की क्षमता को बढ़ाता है. जब एक पक्ष के पास व्यवहार्य विकल्प होता है, तो वे विश्वास के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर मौजूदा वार्ता संतोषजनक परिणाम नहीं देती है, तो उनके पास विकल्प मौजूद हैं.

• **बेहतर निर्णय लेना:** किसी के सर्वश्रेष्ठ विकल्प को समझने से वार्ताकार प्रस्तावों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं. यदि मेज पर रखा गया प्रस्ताव उनके सर्वश्रेष्ठ विकल्प से भी खराब है, तो वे किसी कमतर सौदे के लिए समझौता करने के बजाय उससे दूर चले जाने के लिए सशक्त होते हैं.

• **जोखिम प्रबंधन :** प्रतिकूल समझौतों में फंसने का जोखिम कम हो जाता है. यह वार्ताकारों को अपनी शर्तों पर दृढ़ रहने और खराब प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए दबाव महसूस न करने के लिए प्रोत्साहित करता है.

• **प्रभावी वार्ता रणनीति:** अपने और अपने

समकक्ष के सर्वश्रेष्ठ विकल्प को जानने से बातचीत की रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है. यह जानकारी वार्ताकारों को अपने प्रस्तावों और तर्कों को अधिक प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करती है, जिससे संभावित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं.

वार्ता में सर्वश्रेष्ठ विकल्प का प्रभावी उपयोग करने के लिए, पक्षों को इन चरणों का पालन करना चाहिए:

- ♦ विकल्पों का आकलन करें
- ♦ प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करें
- ♦ अपना सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनें
- ♦ बातचीत के लिए तैयारी करें
- ♦ अपने समकक्ष के सर्वश्रेष्ठ विकल्प पर विचार करें
- ♦ बातचीत के दौरान सर्वश्रेष्ठ विकल्प का उपयोग

एक बार जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ विकल्प स्थापित कर लेते हैं, तो यह बातचीत प्रक्रिया के दौरान कई भूमिकाएँ निभाता है:

- ♦ आरक्षण मूल्य निर्धारित करना
- ♦ प्रस्तावों का मूल्यांकन
- ♦ उत्तोलन बनाए रखना

सर्वश्रेष्ठ विकल्प बातचीत में एक आवश्यक अवधारणा है जो पार्टियों को विकल्पों पर स्पष्टता प्रदान करके सशक्त बनाती है जब समझौते पर नहीं पहुँचा जा सकता है. अपने BATNA को समझकर और प्रभावी ढंग से उपयोग करके, वार्ताकार अपनी सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, सूचित निर्णय ले सकते हैं और अंततः बातचीत में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

संभावित समझौता क्षेत्र : संभावित समझौता क्षेत्र बातचीत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है. संभावित समझौता क्षेत्र को समझना पक्षकारों को समझना पार्टियों को ऐसे समझौतों की ओर निर्देशित करके बातचीत के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करते हैं.

समझौता संभावित क्षेत्र: उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहाँ प्रत्येक पक्ष की न्यूनतम स्वीकार्य

शर्तें मेल खाती हैं। यह एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक वैचारिक स्थान है जो तब मौजूद होता है जब बातचीत करने वाले पक्षों के हित किसी समझौते के लिए पर्याप्त रूप से संरेखित होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक पक्ष किसी वस्तु को कम से कम 5,000 में बेचने को तैयार है और दूसरा पक्ष 6,000 तक का भुगतान करने को तैयार है, तो समझौता संभावित क्षेत्र इन दोनों आंकड़ों के बीच मौजूद होता है। समझौता संभावित क्षेत्र वार्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है:

♦ **समझौते की संभावना का मूल्यांकन:** समझौता संभावित क्षेत्र की मदद से पक्ष यह मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या समझौता संभव है या नहीं।

♦ **वार्ता की दिशा तय करना:** समझौता संभावित क्षेत्र की जानकारी से पक्ष यह तय कर सकते हैं कि वार्ता को किस दिशा में ले जाना है।

♦ **समझौते के विकल्पों की पहचान:** समझौता संभावित क्षेत्र की मदद से पक्ष समझौते के विभिन्न विकल्पों की पहचान कर सकते हैं।

♦ **वार्ता के परिणाम को प्रभावित करना:** समझौता संभावित क्षेत्र की जानकारी से पक्ष वार्ता के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं।

इन तरीकों से, समझौता संभावित क्षेत्र वार्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पक्षों को समझौते तक पहुँचने में मदद करता है।

निष्कर्ष: वार्ता कौशल बैंकों में प्रभावी एनपीए रिक्वरी प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका

निभाते हैं। संबंधों को बढ़ावा देने, अनुकूलित समाधान तैयार करने, भविष्य के संघर्षों को कम करने और कुशल वार्ता प्रथाओं के माध्यम से रिक्वरी दर में सुधार करके, बैंक एनपीए से उत्पन्न चुनौतियों के बीच अपने वित्तीय स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं। तैयारी, सक्रिय सुनवाई, लचीलापन, स्पष्ट समयसीमा और प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसी रणनीतियों को लागू करके, बैंक अधिकारी जटिल वार्ताओं को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं।



सुनील कुमार
अं.ज्ञा.के., गुरुग्राम

एनपीए प्रबंधन में डिजिटल तकनीक का प्रयोग

बैंकों के लिए एनपीए प्रबंधित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जो न केवल उनके वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। एनपीए का अर्थ है अनर्जक आस्तियां, यानि ऐसे ऋण जिनका पुनर्भुगतान बैंक को समय पर नहीं किया गया है, सामान्यतः जब किसी ऋण की चुकौती 90 दिनों तक नहीं होती, तो वह एनपीए के तहत आता है। यानी जिन पर चुकौती नहीं हो रही है। इस स्थिति का समाधान खोजना बैंकों के लिए कठिन हो सकता है, क्योंकि यह उनकी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करता है और बैंक के समग्र लाभ को कम करता है।

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक ने एनपीए प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया है। नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके बैंक इस समस्या का समाधान अधिक प्रभावी और तेजी से कर पा रहे हैं। अब डिजिटल उपकरण जैसे डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, और ब्लॉकचेन तकनीकें बैंकों को एनपीए

मामलों का पहले ही अनुमान लगाने, उनका जल्दी समाधान करने और ऋण चुकौती में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद कर रही हैं।

एनपीए प्रबंधन की आवश्यकता:

- 1. बैंक की वित्तीय सेहत:** एनपीए का बढ़ना बैंक की वित्तीय सेहत को प्रभावित करता है, जिससे उसकी स्थिरता और विकास की गति रुक सकती है।
- 2. ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखना:** जब बैंकों को एनपीए का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता, तो यह ग्राहकों का विश्वास तोड़ सकता है। एक सुरक्षित और पारदर्शी एनपीए प्रबंधन से ग्राहकों का विश्वास बना रहता है।
- 3. बैंक की विकास क्षमता:** एनपीए को ठीक से प्रबंधित करने से बैंक को नए और अच्छे ऋण देने की क्षमता मिलती है, जिससे वह अधिक लाभ कमा सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान बढ़ा सकता है।

डिजिटल तकनीक का परिचय और इसकी भूमिका: डिजिटल प्रौद्योगिकी ने बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक और गहरा बदलाव लाया है। पहले जहां बैंक एनपीए को समझने और संभालने के लिए पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे, वहीं अब नई तकनीकों की मदद से एनपीए प्रबंधन अधिक सटीक, प्रभावी और तेज हो गया है। विशेष रूप से डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और रियल-टाइम डेटा प्रोसेसिंग जैसी तकनीकें एनपीए के मामलों का पूर्वानुमान करने और उन्हें जल्दी हल करने में मदद कर रही हैं। इन तकनीकों की मदद से बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और ग्राहकों को अधिक संतुलित और सुरक्षित ऋण प्रदान कर सकते हैं।

1. डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग: डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग तकनीकें एनपीए प्रबंधन में बैंकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रही हैं। बैंकों के पास ग्राहकों से संबंधित डेटा विशाल मात्रा में होता है, जैसे कि

ऋण चुकाने का इतिहास, क्रेडिट स्कोर, ग्राहकों की आर्थिक स्थिति और उनके पिछले लेन-देन का रिकॉर्ड. इस डेटा का सही तरीके से विश्लेषण करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है.

मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बैंकों को यह पूर्वानुमान करने में मदद करते हैं कि कौन से ग्राहक समय पर ऋण चुकता नहीं कर पाएंगे. यह एल्गोरिदम संभावित एनपीए मामलों का पहले ही पता लगाकर बैंकों को सावधान कर सकते हैं, जिससे वे समय रहते समाधान ढूँढ सकते हैं.

इसके अलावा, मशीन लर्निंग निम्नलिखित कार्यों में सहायक होती है:

- **पूर्वानुमान:** बैंकों को यह पहचानने में मदद मिलती है कि कौन से ग्राहक समय पर ऋण चुकाने में असमर्थ हो सकते हैं.
- **ग्राहक वर्गीकरण:** बैंकों को अपने ग्राहक आधार को विभिन्न वर्गों में विभाजित करने की सुविधा मिलती है, ताकि वे प्रत्येक वर्ग के लिए उपयुक्त समाधान प्रदान कर सकें.

• **स्वचालित निर्णय-निर्माण:** डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए बैंक स्वचालित निर्णय-निर्माण प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं, जैसे ऋण पुनर्निर्धारण और समाधान विकल्प तैयार करना.

2. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चैटबॉट्स: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और चैटबॉट्स का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा को सुधारने और एनपीए प्रबंधन में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है. ए.आई. का उपयोग बैंकों में ग्राहक के साथ संवाद स्थापित करने, उनकी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने, और एनपीए से जुड़े मामलों का समाधान करने में किया जाता है.

ए.आई. का मुख्य लाभ इस प्रकार है:

- **सक्रिय अनुस्मारक (प्रोएक्टिव रिमाइंडर):** ए.आई. बॉट्स ग्राहकों को समय-समय पर उनके ऋण की स्थिति के बारे में सूचित करते हैं, ताकि वे ऋण चुकता करने में देरी से बच सकें.
- **पुनः भुगतान नियत समय:** ए.आई. ग्राहक की वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋण पुनर्भुगतान नियत समय को स्वचालित रूप से तैयार कर सकता है.
- **जवाबदारी का प्रबंधन:** ए.आई. एनपीए मामलों की निगरानी करता है और उन पर

कार्रवाई करता है, जिससे बैंक को अपने जोखिम को कम करने में मदद मिलती है.

3. ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स: ब्लॉकचेन तकनीक एनपीए प्रबंधन में एक अत्यधिक प्रभावी समाधान के रूप में उभरी है. यह तकनीक बैंकों को ऋण अनुबंधों को डिजिटल रूप से सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रखने की सुविधा देती है. इसके अलावा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से ऋण शर्तों को स्वचालित रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है.

ब्लॉकचेन तकनीक से संबंधित लाभ:

- **सुरक्षित डेटा प्रबंधन:** ब्लॉकचेन तकनीक ऋण की जानकारी और भुगतान शर्तों को सुरक्षित रूप से स्टोर करने में मदद करती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावना कम होती है.
- **स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स:** स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के माध्यम से ऋण की शर्तों को स्वचालित रूप से लागू किया जा सकता है, जिससे लेन-देन में पारदर्शिता और स्वचालन बढ़ता है.

4. रियल-टाइम (वास्तविक समय) में डेटा प्रोसेसिंग: रियल-टाइम डेटा प्रोसेसिंग एनपीए प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. बैंक को अपने ग्राहकों के वित्तीय लेन-देन, भुगतान की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण डेटा को समय रहते ट्रैक करने की आवश्यकता होती है. रियल-टाइम डेटा प्रोसेसिंग तकनीक से बैंक डेटा को तुरंत प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे वे त्वरित निर्णय ले सकते हैं और एनपीए मामलों को जल्दी हल कर सकते हैं.

रियल-टाइम डेटा प्रोसेसिंग के प्रमुख लाभ:

- **त्वरित निर्णय:** बैंक ऋण पुनर्निर्धारण, वसूली प्रक्रिया और अन्य कार्यों के लिए तत्काल निर्णय ले सकते हैं.
 - **जोखिम की पहचान:** रियल-टाइम डेटा से बैंकों को संभावित जोखिम की पहचान जल्दी होती है, और वे इसे समय रहते संभाल सकते हैं.
- 5. क्लाउड कंप्यूटिंग:** क्लाउड कंप्यूटिंग भी एनपीए प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण तकनीक साबित हो रही है. बैंकों को अपने डेटा को कहीं भी और कभी भी सुरक्षित रूप से स्टोर करने की आवश्यकता होती है, और क्लाउड कंप्यूटिंग इन जरूरतों को पूरा करता है. क्लाउड प्लेटफॉर्म पर आधारित एनपीए प्रबंधन प्रणाली बैंक डेटा को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने, विश्लेषण करने और स्टोर करने में मदद करते हैं.

क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ:

- **विस्तार क्षमता (स्केलेबिलिटी):** बैंक अपने एनपीए प्रबंधन सॉफ्टवेयर को क्लाउड पर होस्ट करके आसानी से विस्तार कर सकते हैं, यानी जरूरत के अनुसार सिस्टम को बढ़ा सकते हैं.
- **कॉस्ट इफेक्टिवनेस (प्रभावी लागत):** क्लाउड कंप्यूटिंग बैंकों को लागत बचाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए कम निवेश की आवश्यकता होती है.

निष्कर्ष: डिजिटल प्रौद्योगिकी ने एनपीए प्रबंधन को एक नई दिशा दी है जिससे यह पहले से कहीं अधिक प्रभावी और कुशल हो गया है. आज के बैंकिंग क्षेत्र में तकनीकी उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग बैंकों को अपने एनपीए की संख्या को कम करने में मदद कर रहा है. जैसे-जैसे बैंकों को बेहतर डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का लाभ मिल रहा है, वैसे-वैसे वे एनपीए मामलों को जल्दी पहचानने और उनके समाधान के लिए प्रभावी कदम उठा पा रहे हैं. डिजिटल प्रौद्योगिकी के सही उपयोग से न केवल बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिल रही है, बल्कि इससे ग्राहकों के लिए भी बेहतर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं. उदाहरण के तौर पर, ऋण की चुकौती में पारदर्शिता और स्वचालन के कारण ग्राहकों को समय पर सूचना मिल रही है, जिससे उनका अनुभव सुधर रहा है और बैंकों के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ रहा है. भविष्य में, तकनीकी उन्नति के साथ, इन उपकरणों का उपयोग और अधिक प्रभावशाली होगा, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में नए अवसरों का जन्म होगा. एनपीए प्रबंधन के नए तरीके बैंक को न केवल अपनी वित्तीय सेहत को बनाए रखने में मदद करेंगे, बल्कि वे ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की सेवा भी प्रदान करेंगे.

अंततः डिजिटल तकनीकों का सही तरीके से इस्तेमाल बैंकों के लिए न सिर्फ वित्तीय स्थिरता, बल्कि समग्र रूप से देश की आर्थिक विकास की गति को तेज करने में भी सहायक होगा. इन तकनीकों के विकास से बैंकों को भविष्य में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार मिलेगा.



सुमित रॉय
यू.एल.ए., पवई मुंबई

सरफेसिया : वसूली का रामबाण उपाय

संपत्ति में सुरक्षा हित के निर्माण को सरफेसिया अधिनियम के प्रावधानों के माध्यम से महत्व प्राप्त हुई है। इसने ऋणदाता को विभिन्न शक्तियाँ प्रदान की हैं। संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियाँ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक अलग प्रकृति के लेन-देन करेंगी। इसलिए, इन दोनों को एक प्रामाणिक पंजीकरण की आवश्यकता है। केंद्रीय रजिस्ट्री के बारे में प्रावधानों को वर्णित लेनदेन और सुरक्षा पर शुल्क के निर्माण को पंजीकृत करना आवश्यक होगा।

2002 में स्थापना के बाद से इस कानून में कई बार संशोधन किया गया है, जैसे 2004, 2013, 2016 और 2021 में (वित्त अधिनियम द्वारा)। वर्ष 2020 में कुछ प्रावधान यानी 2016 के संशोधन अधिनियम की धारा 17, 18 और 19 को 26.12.2019 की अधिसूचना जारी करके 24 जनवरी 2020 से लागू किया गया।

सरफेसी अधिनियम की धारा 20 के तहत एक केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना का प्रावधान है।

◆ केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जिसे वह ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के सृजन के लेन-देन के पंजीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनी स्वयं की मुहर के साथ केंद्रीय रजिस्ट्री के रूप में ज्ञात एक रजिस्ट्री स्थापित कर सकेगी या स्थापित करवा सकेगी।

◆ केंद्रीय रजिस्ट्री का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे और उपधारा (1) में निर्दिष्ट संव्यवहारों के रजिस्ट्रीकरण को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य स्थानों पर केंद्रीय रजिस्ट्री के शाखा कार्यालय स्थापित किए जा सकेंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार ठीक समझे।

◆ केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा,

प्रादेशिक सीमाएं निर्धारित कर सकेगी, जिनके भीतर केंद्रीय रजिस्ट्री का कोई कार्यालय अपने कार्य कर सकेगा।

◆ केंद्रीय रजिस्ट्री से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16), कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44), पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39), मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 49) और डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) या शुल्कों के पंजीकरण की आवश्यकता वाले किसी अन्य कानून में निहित किसी भी प्रावधान के अतिरिक्त होंगे और उन अधिनियमों या कानूनों के तहत शुल्कों की प्राथमिकता या उनकी वैधता को प्रभावित नहीं करेंगे।

अधिनियम वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की दिशा में भी एक बड़ा कदम था। इसने ऋण बाजार में निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है:

◆ वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण।

◆ वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण।

◆ ऋण की उचित चुकौती के लिए प्रतिभूति में सृजित किसी 'हित' को 'प्रतिभूति हित' के रूप में मान्यता देना, चाहे उसका स्वरूप और प्रकृति कुछ भी हो, किन्तु जब वह ऋणदाता के कब्जे में न हो।

◆ चूक की स्थिति में न्यायालयों के हस्तक्षेप के बिना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय धन की वसूली के लिए ऐसी प्रतिभूति को लागू करने की शक्ति।

◆ प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित के सृजन के लेनदेन के पंजीकरण के उद्देश्य से एक केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना के लिए प्रावधान करना।

सुरक्षा हित के प्रवर्तन से संबंधित अधिनियम के प्रावधान उन मामलों पर लागू होते हैं जिनमें वित्तीय सहायता के उचित पुनर्भुगतान

के लिए सुरक्षा हित बनाए जाते हैं। अधिनियम ने एक सरल बात को पूर्व निर्धारित किया है, कि उधारकर्ताओं की ओर से ऋण चुकाने का दायित्व है और यदि वे चुकाने में असमर्थ हैं, तो ऋण की वसूली के लिए अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में दिए गए प्रक्रिया का पालन करके, न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना ऋण के लिए प्रतिभूतियों को बेचा जा सकता है।

यह अधिनियम उन मामलों पर लागू होता है जहां किसी वित्तीय आस्ति के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए प्रतिभूति 1 लाख रुपए से अधिक है और देय राशि मूल राशि और उस पर ब्याज का 20% या उससे अधिक है।

सरफेसिया अधिनियम के अनुसार, 'ऋण वसूली न्यायाधिकरण' द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अपील की स्थिरता के अधीन अपील नामक प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इन न्यायाधिकरणों का गठन केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

अधिनियम में एआरसी की स्थापना का भी प्रावधान है जो बैंकों/वित्तीय संस्थानों से एनपीए प्राप्त करते हैं, इसके लिए वे सुरक्षा रसीदे (जैसा कि अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है) जारी करके योग्य खरीदारों से धन जुटाते हैं, जो ऐसी वित्तीय आस्तियों में अविभाजित हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरल शब्दों में, यह वसूली के उद्देश्य से बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण या अग्रिम का अधिग्रहण है।

ऋणदाता किसी तीसरे पक्ष से भी ऋणी को देय राशि की मांग कर सकता है। आस्तियों की बिक्री के बाद शेष बकाया राशि के लिए, क्षेत्राधिकार के अनुसार सिविल कोर्ट या डीआरटी में उपाय खुला है। अधिनियम के तहत विभिन्न कार्रवाइयों को शुरू करने के लिए एक अधिकृत व्यक्ति की आवश्यकता

होती है। संपत्ति का कब्जा लेते समय, विभिन्न सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। कब्जा लेने के लिए, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी की मदद ली जा सकती है। ऐसी स्थिति में ऐसे अधिकारियों द्वारा कब्जा लिया जाता है और ऋणदाता को सौंप दिया जाता है। कब्जे के नोटिस के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन निर्धारित राशि का भुगतान करने पर। यदि कब्जा गलत तरीके से लिया गया है, तो ऋणदाता को ऋणी को मुआवजा देना होगा। न्यायाधिकरण में अपील करने के लिए ऋण राशि का पचास प्रतिशत जमा करना आवश्यक है।

सरफेसिया अधिनियम ने प्रतिभूति हित की एक नई अवधारणा को सामने लाया, और प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन को सरफेसिया अनुच्छेद में, सुरक्षा पर प्रभार को अंततः प्रभारों के होने के बाद बनाया जाना चाहिए, हालांकि उन संपत्तियों के खिलाफ सुरक्षित लेनदारों के पक्ष में जिन्हें अंततः लागू किया जाना चाहिए, बनाए गए प्रभारों को किसी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत/नोट किया जाना चाहिए। यह नोटिंग कंपनी की संपत्ति के खिलाफ बनाए गए प्रभारों के मामले में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ प्रभार के पंजीकरण की तरह है। यह इकाई सरफेसिया अधिनियम के तहत बनाई गई केंद्रीय रजिस्ट्री से संबंधित है।

दंड लगाने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास उपलब्ध शक्तियों के संबंध में धारा 30ए के अनुसार

1. जहां कोई आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी या चूककर्ता व्यक्ति पर एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना या ऐसी विफलता में शामिल राशि का दोगुना, जहां ऐसी राशि मात्रात्मक है, जो भी अधिक हो, लगा सकता है और जहां ऐसी विफलता जारी है, वहां एक अतिरिक्त जुर्माना जो पहली विफलता के बाद प्रत्येक दिन के लिए एक लाख रुपये तक हो

सकता है, जिसके दौरान ऐसी विफलता जारी रहती है।

2. उपधारा (1) के अधीन जुर्माना लगाने के प्रयोजन के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी या चूककर्ता व्यक्ति को नोटिस देगा जिसमें ऐसी कंपनी या व्यक्ति से कारण बताने को कहा जाएगा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि जुर्माना के रूप में क्यों न लगाई जाए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

3. इस धारा के अधीन लगाया गया कोई जुर्माना उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर देय होगा।

4. जहां आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी उपधारा (3) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर जुर्माना का भुगतान करने में विफल रहती है, न्यायाधिकरण एक आदेश द्वारा, उसका पंजीकरण रद्द कर देगा।

सरफेसिया अधिनियम के प्रावधान उन अधिनियमों के प्रावधानों को दरकिनार करते हुए लागू होंगे। (धारा 35) 2013 में एसएआरएफएएसआई अधिनियम 2002 में संशोधन (धारा 26 ए-अध्याय IV) के तहत केंद्र सरकार को संशोधन और शुल्क की संतुष्टि दाखिल करने में त्रुटियों/चूक को सुधारने की शक्तियां दी गई हैं।

निष्कर्ष: 2013 और 2016 में सरफेसिया अधिनियम में किए गए संशोधनों पर चर्चा की है, जो समय के साथ इसके कार्यान्वयन के दौरान महसूस की गई कमियों को दूर करते हैं। ये संशोधन धारा 26 के अतिरिक्त शामिल किए गए हैं, लेकिन पंजीकरण के दौरान त्रुटियों को सुधारने, सुरक्षित ऋणदाता को प्राथमिकता देने, केंद्रीय रजिस्ट्री में सुरक्षा हित का पंजीकरण उन मामलों में भी जहाँ कोई जमानती लेनदार नहीं है, सुरक्षित ऋणदाता द्वारा प्रवर्तन अधिकारों के प्रयोग की शर्तें आदि जैसे विभिन्न मुद्दों से निपटते हैं।

अधिनियम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण को विनियमित करना और वित्तीय

आस्तियों के संबंध में बनाए गए सुरक्षा हितों को लागू करना था ताकि ऐसी आस्तियों की प्राप्ति को सक्षम बनाया जा सके। सरफेसिया अधिनियम न्यायालय या न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना किसी जमानती लेनदार द्वारा सुरक्षा हितों को लागू करने के तरीके के बारे में बताता है।

बैंक और वित्तीय संस्थाएँ जमानत प्राप्त करके पैसा उधार देती हैं। प्राप्त की गई जमानत अग्रिम राशि के लिए सुरक्षा के रूप में कार्य करती है और आवश्यकता पड़ने पर प्रतिभूतियों की बिक्री से धन प्राप्त किया जा सकता है। अग्रिम राशि की वसूली के लिए चल और अचल दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों पर ऋणदाता के अधिकार सीमित और कम प्रभावी थे, क्योंकि उन्हें कानूनी प्रणाली की मदद लेनी पड़ती थी, जिसे सरफेसिया अधिनियम, 2002 के पारित होने से पहले पूरा होने में अनावश्यक रूप से लंबा समय लग रहा था। इस अधिनियम ने प्रतिभूतियों पर हाथ डालकर बकाया राशि की वसूली के लिए कानूनी ढांचे में बड़े बदलाव किए।

सरफेसिया अधिनियम द्वारा नए परिवर्तन लाए गए हैं। इस अधिनियम को बैंकिंग क्षेत्र को अपने बढ़ते एनपीए स्टॉक के प्रबंधन के लिए एक संरचित मंच प्रदान करने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को प्रतिभूतियों पर कब्जा करने और उन्हें बेचने की अनुमति देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। इस अधिनियम को बड़े पैमाने पर आस्ति वसूली और पुनर्निर्माण की सुविधा के रूप में माना जाता है। अधिनियम से पहले, वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित कानूनी ढांचा तेजी से बदलती वाणिज्यिक प्रथाओं और वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से पिछड़ गया था, जिसके कारण चूक वाले ऋणों की वसूली धीमी हो गई और बैंकों के एनपीए का स्तर बढ़ गया। ऋणदाता को अपने पैसे वापस मिलने की सुविधा से उसे ऋण देने के लिए आत्मविश्वास मिलेगा।



स्मिता राहुल डावे
अकोला शाखा,
क्षे.का., अमरावती

एनपीए प्रबंधन के लिए बाहरी एजेंसियों का प्रभावी उपयोग

बैंकिंग क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और दशकों से अनर्जक आस्तियों की समस्या से जूझ रहा है। यह चुनौती केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक चिंता है जो बैंकिंग स्थिरता और आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। एनपीए, मूल रूप से वे ऋण हैं जो बैंकों के लिए आय उत्पन्न करना बंद कर देते हैं, जिससे वित्तीय संस्थानों की चलनिधि और लाभप्रदता पर ही नहीं परंतु व्यापक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनपीए बहुआयामी है, जो मैक्रोइकॉनॉमिक (समष्टि अर्थ.) कारकों और क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों दोनों के कारण होता है। 1990 के दशक की आर्थिक उदारीकरण ने, जबकि देश को अभूतपूर्व विकास की ओर अग्रसर किया, बैंकिंग क्षेत्र को नए जोखिमों और प्रतिस्पर्धा के लिए भी उजागर किया। इसके बाद के वर्षों में, अक्सर क्रेडिट गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिए बिना, तेजी से लोन विस्तार देखा गया, जिससे एनपीए में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

अधिक एनपीए बैंक के ऋण देने की क्षमता को सीमित करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को मिलने वाले क्रेडिट / लोन की उपलब्धता प्रभावित होती है और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार पर भी असर पड़ता है। इसके अलावा, एनपीए का समाधान बैंकिंग क्षेत्र में निवेशकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो घरेलू और विदेशी दोनों निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है।

सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एनपीए प्रबंधन हेतु कई ऐसी कार्यनीति पर काम कर रहे हैं जिससे पिछले पाँच वर्षों में एनपीए में कमी आई है। यदि हम अपने बैंक की बात करें तो सितंबर, 2022 से सितंबर, 2024 के अंतराल में हमारे सकल एनपीए को ₹.24892 करोड़, नेट एनपीए को ₹.10434 करोड़ से कम करा है।

एनपीए को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, लगभग सभी बैंक रिक्वरी एजेंट्स, प्रवर्तन एजेंट्स, बोली सफलता एजेंट्स और जांच एजेंट्स जैसी विशेष बाहरी एजेंसियों का सहारा लेते हैं।

1. रिक्वरी एजेंट्स की भूमिका

परिभाषा और महत्व: रिक्वरी एजेंट्स वे पेशेवर होते हैं जो उधारकर्ताओं से बकाया भुगतान की वसूली का कार्य करते हैं। एनपीए की मात्रा को कम करने और बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रिक्वरी एजेंट्स का उपयोग करके अपने एनपीए स्तरों को कम करने में सफलता प्राप्त की है।

चयन मानदंड: सक्षम रिक्वरी एजेंट्स का चयन उनके ट्रैक रिकॉर्ड, विशेषज्ञता और नियामक मानकों के अनुपालन का मूल्यांकन करके किया जाता है।

उत्तम प्रथाएं:

- **प्रशिक्षण:** कानूनी और नैतिक वसूली प्रथाओं पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करें। यह सुनिश्चित करता है कि एजेंट्स न केवल प्रभावी ढंग से वसूली कर सकें, बल्कि कानूनी जटिलताओं से भी बच सकें।

- **अनुपालन:** एजेंट्स को कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए नियामक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करें। यह न केवल बैंक की प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, बल्कि कानूनी समस्याओं से भी बचाता है।

- **कार्य-निष्पादन की निगरानी:** प्रमुख कार्य-निष्पादन संकेतकों (KPIs) का उपयोग करके एजेंट्स के कार्य-निष्पादन का नियमित रूप से आकलन करें।

2. प्रवर्तन एजेंट्स की भूमिका

परिभाषा और महत्व: प्रवर्तन एजेंट्स बकाया राशि की कानूनी प्रवर्तन, जिसमें संपत्ति की जब्ती और बिक्री शामिल है, के लिए जिम्मेदार होते हैं। कानूनी कार्यवाइयों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

कानूनी ढांचा: प्रवर्तन एजेंट्स एक सख्त कानूनी ढांचे के भीतर काम करते हैं जो उनके कार्यों को नियंत्रित करता है। इस ढांचे को समझना उनके प्रभावी उपयोग के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रवर्तन एजेंट्स के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।

प्रभावी उपयोग:

- **स्पष्ट संचार:** प्रवर्तन एजेंट्स के साथ स्पष्ट और सुसंगत संचार बनाए रखें ताकि संगठनात्मक लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित हो सके। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष एक ही पृष्ठ पर हैं और किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके।

- **नियमित ऑडिट:** कानूनी मानकों और संगठनात्मक नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट करें।

3. बोली सफलता एजेंट्स की भूमिका

परिभाषा और महत्व: बोली सफलता एजेंट्स संपत्तियों की नीलामी और बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे बैंकों को एनपीए से धन की वसूली में मदद मिलती है। सफल नीलामी प्रबंधन और बोली प्राप्त करने में उनकी विशेषज्ञता महत्वपूर्ण होती है।

चयन और प्रशिक्षण: नीलामी और संपत्ति बिक्री में मजबूत पृष्ठभूमि वाले एजेंट्स का चयन करें। अपने बैंक की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करें।

कार्य-निष्पादन मेट्रिक्स: नीलामी की सफलता दर, वसूली गई राशि और समय-सीमा के

पालन के आधार पर बोली सफलता एजेंट्स का मूल्यांकन करें। यह सुनिश्चित करता है कि एजेंट्स अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं और सुधार के क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं।

4. जांच एजेंट्स की भूमिका

परिभाषा और महत्व: जांच एजेंट्स एनपीए में योगदान देने वाले धोखाधड़ी और अनियमितताओं का पता लगाते हैं। उनकी जांच कौशल डिफॉल्ट के मूल कारणों की पहचान करने और भविष्य की घटनाओं को रोकने में मदद करती है।

कौशल और विशेषज्ञता: प्रभावी जांच एजेंट्स में मजबूत विश्लेषणात्मक कौशल, विवरण पर ध्यान और फॉरेंसिक लेखांकन और धोखाधड़ी का पता लगाने का अनुभव होता है। उदाहरण के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जांच एजेंट्स के चयन में इन कौशलों को प्राथमिकता दी है।

आंतरिक टीमों के साथ एकीकरण: व्यापक जांच और निष्कर्षों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक टीमों के साथ

निकट सहयोग करें। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष एक ही पृष्ठ पर हैं और किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके।

5. प्रभावी उपयोग के लिए रणनीतियां

स्पष्ट उद्देश्य और दायरा: प्रत्येक प्रकार के एजेंट के लिए स्पष्ट उद्देश्य और दायरा परिभाषित करें ताकि वे अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को समझ सकें। यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्ष एक ही पृष्ठ पर हैं और किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके।

प्रौद्योगिकी एकीकरण: संचार और रिपोर्टिंग को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। निर्बाध इंटरैक्शन के लिए सीआरएम सिस्टम और स्वचालित रिपोर्टिंग टूल्स को लागू करें।

प्रोत्साहन संरचनाएं: एजेंट्स के लक्ष्यों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ संरेखित करने वाली प्रोत्साहन संरचनाएं विकसित करें, जिससे उन्हें बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

नियमित ऑडिट और फीडबैक: सुधार के

क्षेत्रों की पहचान करने और एजेंट प्रदर्शन की निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट और फीडबैक एकात्र करें।

निष्कर्ष: भारतीय बैंकों में एनपीए की चुनौती से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें न केवल कठोर क्रेडिट मूल्यांकन और निगरानी तंत्र शामिल हैं, बल्कि नवाचारी वसूली रणनीतियाँ (जैसे बाहरी एजेंसियों का प्रभावी उपयोग) निरंतर सतर्कता और अनुकूलनशील नीतिगत उपाय भी शामिल हैं।

बाहरी एजेंसियों का प्रभावी उपयोग एनपीए प्रबंधन और बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। सही एजेंट्स का चयन, उचित प्रशिक्षण प्रदान करना, और मजबूत निगरानी और प्रोत्साहन प्रणालियों को लागू करके, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने एनपीए प्रबंधन रणनीतियों में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं।



विशाल मेहंदीस्ता
यू.एल.ए., विशाखपट्टणम

बैंकर और रिकवरी

कर्ज की दुनिया, सपनों का संसार,
हर ऋण में छिपा है भविष्य का आकार।
बैंकर की कोशिश, उम्मीदों को बढ़ाना,
पर वसूली में है अनुशासन निभाना।

ग्राहक के साथ पहली बात,
समझे उसकी मजबूरी और हालात।
सहानुभूति के साथ मिले समाधान,
हर किस्त से जुड़े बैंक के अरमान।

कभी पुनर्गठन, कभी नया सहारा,
ग्राहक के भले में दिखे उजियारा।
पर जब वादा टूटे, न बने सहमति,
कानूनी राहें फिर बनें वास्तविकता की कड़ी।

रिकवरी केवल धन की मांग नहीं,
यह रिश्तों की डोर और विश्वास की जमीं।
संतुलन साधे बैंकर हर बार,
नीति और संबंध दोनों का करें विचार।

सख्ती भी हो, पर गरिमा के साथ,
पेशेवरता दिखे हर बात में अपार।
अंततः सफलता की यही पहचान,
जहां बैंक और ग्राहक दोनों का हो सम्मान।



आशुतोष पांडे
यू.एल.ए., गुरुग्राम

सीएसआर तथा एम्पावर हर गतिविधियां



दिनांक 09.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूर में सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत वायनाड भूखलन से प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों हेतु मुख्यमंत्री राहत निधि को रु.5.59 करोड़ की राशि प्रदान की गई. केरल के माननीय वित्त मंत्री श्री के. एन. बालगोपाल को चेक सौंपते हुए सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ, श्रीमती रेणु के नायर, अंचल प्रमुख, मंगलूर साथ हैं श्री सुजीत एस तारीवाळ, क्षेत्र प्रमुख, तिरुवनंतपुरम एवं श्री जी नितिन, बीआरएम.



दिनांक 28.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूर द्वारा सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज, हारोहल्ली में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन तथा डिस्पोज़ल मशीन वितरित किया. इस अवसर पर माननीय श्री एच.ए. इकबाल हुसैन, विधायक, बेंगलूर (ग्रामीण) सहित श्री सुनील वी पाटिल, क्षेत्र प्रमुख, सुश्री सिनिबा वी कुमार, बीआरएम एवं श्री प्रेम प्रकाश वर्मा, शाखा प्रमुख, हारोहल्ली उपस्थित रहे.



दिनांक 08.10.2024 को सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ, की अध्यक्षता में मेलुर, सेंगोट्टई, तमिलनाडु में 03 सरकारी विद्यालयों के विकास हेतु अनुदान दिया गया. इस अवसर पर श्री प्रवीण शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक, श्री विकास कुमार, महाप्रबंधक तथा श्री जी.एन. दास, महाप्रबंधक, केंका. भी उपस्थित रहे.



दिनांक 02.10.2024 को सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत अडयार कैंसर संस्था, चेन्नै शोध संस्था, तमिलनाडु को मैग्नेटम सेम्प्रा 1.5 टन एमआरआई स्कैनर हेतु रु. 5.30 करोड़ की राशि प्रदान की गई. डॉ. कल्पना बालकृष्णन, निदेशक, अडयार कैंसर संस्था, चेन्नै को चेक सौंपते हुए सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ, श्री रामसुब्रमणियम एस., कार्यपालक निदेशक, साथ हैं श्री वी. कामत, मुख्य कार्यपालक, यूबीएसएफटी, श्री जीवी मिश्रा, महाप्रबंधक, श्री अभिजीत बसाक, अंचल प्रमुख, मुंबई.



दिनांक 25.11.2024 को सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, खम्मम द्वारा सरकारी जनरल अस्पताल, खम्मम को एंबुलेंस प्रदान किया गया. इस अवसर पर श्री ए हर्षमंत रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख, श्री मुजम्मिल खान, जिला कलेक्टर, खम्मम, श्री किरण कुमार, अस्पताल अधीक्षक उपस्थित रहे.



दिनांक 09.09.2024 को अंचल कार्यालय, विजयवाडा द्वारा विजयवाडा क्षेत्र में बाढ़ प्रस्त लोगों को राहत सामाग्री दी गई. इस अवसर पर श्री सी. वी.एन. भास्कर राव, अंचल प्रमुख, विजयवाडा, श्रीमती ए. शारदा मूर्ती, उप अंचल प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.



दिनांक 16.11.2024 को केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में फ्री फूड प्रोग्राम की शुरुआत सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ, द्वारा की गई. इस अवसर पर केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में ज़रूरतमन्द लोगों के लिए मुफ्त भोजन एवं फलों के रखरखाव हेतु फ्रिज इन्स्टाल किया गया.



दिनांक 07.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूर में सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ द्वारा अजिता नेले, अनाथाश्रम को रु.25000/- का चेक प्रदान किया गया. इस अवसर पर श्री नवनीत कुमार, महाप्रबंधक, श्री सुनिल वी पाटिल, क्षेत्र प्रमुख मैसूर सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे.



दिनांक 30.11.2024 को अंचल कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम में सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत अनाथालय के स्कूली बच्चों को दैनिक उपयोग की सामग्री देते हुए श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख तथा श्री आर. नरसिम्हा कुमार, क्षेत्र प्रमुख.



दिनांक 09.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय मैसूर द्वारा सीएसआर गतिविधि के अंतर्गत श्री चामुण्डेश्वरी मंदिर परिसर के मल्टी लेवल पार्किंग सिस्टम के लिए स्वचालित बूम बैरियर एवं डिजिटल निगरानी (निर्बाध फास्टैग एकीकरण) की स्थापना की गई. इस अवसर पर श्री सी.वी.सुधीर, उप अंचल प्रमुख, बेंगलूरु, श्री सुनील वी पाटिल, क्षेत्र प्रमुख, श्री आर शिवकुमार, उप क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य कार्यपालक तथा स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.



दिनांक 21.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा द्वारा एम्पावर हर के अंतर्गत सरदार राणा सिंह प्राइमरी स्कूल, बड़ौदा में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन प्रदान की गयी. इस अवसर पर श्री अंकुर सर्राफ, क्षेत्र प्रमुख, श्रीमती मीनल दोषी एवं शिल्पी तांतिया, सदस्य, एम्पावर हर समिति सहित सुश्री प्रीतिबेन, प्रिंसिपल के साथ बैंक तथा विद्यालय के अन्य स्टाफ उपस्थित रहे.



Navigating the Choppy Waters

A Deep Dive Into NPA Management in India

Non-Performing Assets (NPAs) are loans or advances for which the principal or interest payment remained overdue for a period of 90 days, thus, impeding bank's income on the one hand, and the need to provide for such loans as per regulatory guidelines, on the other hand. Hence, it is double whammy on the financial health of any bank. Effective management of NPAs, thus, is crucial for the health of the banking sector in India and has emerged as a significant drag on the Indian banking sector, hindering its ability to effectively channel credit to the economy. Let us delve into the multifaceted nature of the NPA problem, critically analyse the existing legal and regulatory framework and explore potential avenues for improvement, drawing insights from relevant academic research and market observations.

THE NPA CONUNDRUM: A MULTI-FACETED CHALLENGE

The surge in NPAs is a complex phenomenon with interconnected roots which can be summarized as under:

➤ **Economic Downturns:** Cyclical economic slowdowns, coupled with sector-specific challenges, can significantly impact borrower repayment capacity. The recent COVID-19 pandemic, for instance, severely impacted sectors like tourism, hospitality and retail, leading to a sharp rise in NPAs.

➤ **Changing Economic Landscape:** Rapid technological advancements, globalization and increasing competition have led to increased economic volatility and uncertainty, making it more challenging for businesses to remain

competitive and maintain financial stability.

➤ **Weak Corporate Governance:** Poor corporate governance practices within borrowing entities, including opaque decision-making, lack of transparency and inadequate risk management/ mitigation systems contribute significantly to increased loan defaults.

➤ **Wilful Defaults:** In some cases, borrowers may deliberately default on loans, driven by factors such as fraudulent activities, misappropriation of funds or a lack of intent to repay with connotations of fraud.

➤ **Credit Appraisal Deficiencies:** Inadequate credit appraisal processes, including insufficient due diligence and risk assessment, play a crucial role. Many a times

banks sanction loans without adequately assessing the borrower's creditworthiness and the viability of the proposed projects, leading to a higher likelihood of default.

MARKET INSIGHTS AND RESEARCH: UNVEILING KEY CHALLENGES

Market surveys and research provides certain valuable insights into the challenges faced by banks in managing NPAs:

➤ **Lack of Transparency and Information Asymmetry:** Limited access to accurate and timely borrower information hampers effective risk assessment and early identification of potential defaults. This information asymmetry can lead to mispricing of risk and increased exposure to credit losses.

➤ **Weak Enforcement Mechanisms:** Delays in judicial proceedings, difficulties in asset valuations and challenges in enforcing court orders hinder effective recovery efforts.

➤ **Skill Gaps:** A lack of skilled professionals in areas such as credit risk management, legal expertise and insolvency resolution within banks exacerbates the NPA challenge further.

➤ **Limited Access to Alternative Debt Resolution Mechanisms:** While the IBC provides a framework for resolution, alternative mechanisms such as pre-packaged insolvency, mediation and conciliation need to be further explored and aggressively pursued.

LEGAL AND REGULATORY

FRAMEWORK: A CRITICAL APPRAISAL

The Indian legal framework for NPA management encompasses a range of measures, each with its own set of strengths and weaknesses:

➤ **The Recovery of Debts and Bankruptcy Act, 1993 (RDB Act):**

This Act established Debt Recovery Tribunals (DRTs) to expedite recovery proceedings. However, DRTs often face challenges such as procedural delays, case backlogs and difficulties in evidence gathering, hindering their effectiveness.

➤ **The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 (SARFAESI Act):**

This Act allows banks and financial institutions to take possession of securities, both movable or immovable properties, sell them to recover loans that too without intervention of the Courts. The Act also provides for the creation of Asset Reconstruction Companies (ARCs) and the enforcement of security interests, making it easier for banks to manage NPAs. While the SARFAESI Act has streamlined recovery processes, concerns have been raised regarding its potential for misuse and limited recourse for borrowers.

➤ **Commercial Courts and Civil Courts:**

Commercial Courts and Civil Courts play a pivotal role in the resolution of disputes related to NPAs. The establishment of Commercial Courts Act, 2015 is aimed to provide speedy and efficient resolution of commercial disputes. These courts have jurisdiction over

matters relating to banking and commercial transactions, making them essential for NPA management. The adjudication process involved under Commercial Courts Act are first mediation and on failure of mediation, a summary trial and disposal in a time bound manner. Civil Courts, on the other hand, handle cases related to recovery suits and other disputes arising out of banking transactions.

➤ **The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016:**

Enacted in 2016, IBC is one of the most significant reforms for NPA management in India. It provides a timebound process for resolving insolvency and bankruptcy cases. The primary objective of the IBC is to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms, and individuals in a time-bound manner. The IBC has brought a paradigm shift in the NPA resolution process by focusing on maximizing the value of assets and promoting entrepreneurship. This comprehensive legislation aims to provide an effective and efficacious framework for insolvency resolution, focusing on maximizing asset value and ensuring equitable distribution among creditors. However, challenges such as delays in NCLT proceedings, complexities in the code, and the need for further clarity in certain areas persist.

➤ **Revenue Recovery Acts:**

Revenue Recovery Acts are state-specific laws that enable banks to recover dues by attaching and selling the defaulter's properties

akin to recovery of revenues. These acts provide a mechanism for the recovery of public dues, including loans given by banks. The provisions under these acts ensure that banks can recover their dues efficiently thus, contributing to the reduction of NPAs.

➤ **Lok Adalats:** Lok Adalats are an alternative dispute resolution mechanism recognized under the Legal Services Authorities Act, 1987. They offer an amicable settlement of disputes, including those related to NPAs, through conciliation and compromise. Lok Adalats play a significant role in the resolution of small-value NPA cases by providing a cost-effective and speedy resolution process. The decisions of Lok Adalats are binding on the parties and have the same effect as a decree of a Civil Court.

However, considering that recovery of Non-Performing Assets (NPAs) vis-a-vis outstanding dues is a crucial metric for assessing the effectiveness of various recovery channels, it is observed that among all the recovery measures through legal means, the IBC has been particularly effective, likely due to its structured and time-bound resolution process. The IBC channel has shown significant recovery rates and also ensures promising returns vis-à-vis value of assets of the borrower with a sizeable amount of bad debts being resolved and recovered through this mechanism. Same is the case for the SARFAESI Act, where the recovery rate is also quite significant and the action is most relevant for individual/ retail borrowers. While Lok Adalats add up

to a good number of low values NPA accounts being wiped off from the books of the Banks, the realization rate is not very significant owing to obvious reasons. The option of Commercial Courts is no doubt a promising one, but yet to pick up on account of lack of infrastructure at the district level. So far as Revenue Recovery Cases are concerned, they have very limited effect that too in certain states only.

THE WAY FORWARD: A MULTI-PRONGED APPROACH

Addressing the NPA challenge requires a multi-pronged approach:

➤ **Strengthening Credit Appraisal and Risk Management:** Banks need to enhance their credit appraisal processes by incorporating robust due diligence, thorough risk assessment, and continuous borrower monitoring.

➤ **Improving the Legal and Regulatory Framework:** Filling of vacancies, providing adequate infrastructure, streamlining legal proceedings, enhancing enforcement mechanisms and addressing loopholes in existing regulations are crucial.

➤ **Promoting Alternative Debt Resolution Mechanisms:** Exploring and promoting alternative mechanisms such as pre-packaged insolvency, mediation, and conciliation can help expedite resolution and minimize costs.

➤ **Developing Human Capital:** Investing in training and development programs to enhance the skills of bank personnel in areas such as credit risk management,

legal expertise, and insolvency resolution is essential.

➤ **Leveraging Technology:** Utilizing technology for data analytics, risk modelling and process automation can improve efficiency, enhance risk assessment and facilitate faster resolution. The Stressed Asset Recovery Automated Solution, otherwise known as the Union SARAS is a novel effort introduced by our Bank in this regard. It is a one of its kind platforms in the entire banking industry in India, providing operational, regulatory and technological leverage for all aspects of NPA Management. In the coming years a lot is expected of the platform in terms of substantive recovery.

➤ **Focus on Financial Literacy and Credit discipline:** Promoting financial literacy among borrowers and ensuring access to credit information bureaus can help improve credit discipline and reduce the incidence of defaults.

CONCLUSION: The NPA challenge necessitates a collaborative effort amongst all stake holders viz. banks, regulators, policymakers and borrowers. By addressing the root causes of NPAs, strengthening the legal and regulatory frameworks and leveraging technological advancements, India can strive to create a more robust and resilient banking sector, fostering sustainable economic growth and development.

Swagat Mohanty
SAMV,
CO, Mumbai



Role of NPA Recovery in Bank's Profitability

The functional relation between economic growth in any country and development of its financial sector has been a subject of great interest to economist and policy-makers though the nature and orientation of this causality remains a matter of debate in academic circles. A prevalent view in this regard that can be inferred from the writings of among others, Shaw (1973), Jung (1986) and King and Levine (1993), suggests that financial development serves as a precursor to economic growth. A diametrically opposite view can be traced back to the writings of the celebrated economist Joan Robinson who famously said, "where enterprise leads, finance follows" suggesting that economic growth necessarily precedes financial development. Some economists consider the causality between these two variables to be bi-directional in nature while others consider the direction of the causality to change over a period of time with changes in the scale of growth; in that during the initial phase of economic expansion it is finance that drives growth while growth transpires as a tool of financial development at later stages. What is uncontested though, is the conceptual position that the deepening of financial markets and penetration of financial institutions across all possible segmentations

of the economy may be considered a reasonable indicator of a nation's economic strength.

Banks serve as financial intermediaries in the economy by mobilising resources from surplus units willing to save part of their current income and accumulated funds and making them available to deficit spenders for purpose of consumption and investment. Banks commit to pay interest to their depositors in accordance with pre-determined terms and conditions and earn interest on loans and advances extended to borrowers. The difference between the interest paid on deposits and interest earned on advances constitutes a major part of the operating profit of a bank. An overview of policies governing the banking industry in India during the post-independence period clearly indicates that the evolution of the structural and operational framework of the sector has been designed to serve larger interests of nation-building and socio-economic transformation rather than remaining limited to a profit-seeking traditional business. However, the introduction of the elements of liberalisation, privatisation and globalisation in the sector during the post-reform period has altered the banking paradigm altogether thereby rendering the general environment in the industry highly competitive.

Enhancing the scale of profits is today as much a short and long-term goal of banks irrespective of their constitution as objectives of social banking like financial inclusion are. Like any other traditional business, in order to increase the margin of profits, banks need to adopt strategies to minimise costs and maximise revenue of which checking leakages in income flow is of central importance. Non-performing assets (NPAs) are arguably the most visible source of leakage of income from a bank's point of view which also implies that recovery of such assets can potentially serve as an important source of enhancing operating profits. In this context it may be useful to begin with a brief discussion of the concept of NPAs and the broad categorisation of such accounts.

According to the guidelines on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) issued by the Reserve Bank of India with a view to align the functioning of Indian banks with global best practices and ensure transparency, the criteria of '90 days overdue' has been made applicable identification of non-performing assets from the end of FY 2004. Here, the phrase 'overdue' refers to a situation where any amount due to a bank under any credit facility is not paid by the due date specified by the bank. Accordingly, with effect from 31st

March 2004 term loans are being classified as NPA if 'interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days. In case of running accounts like overdraft or cash credit facilities the loan would be classified as NPA if the account remains 'out of order' for a period of more than 90 days. Here the phrase 'out of order' refers to any of the following situations-

- The outstanding balance in the account remains in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lesser, for a continuous period of 90 days
- In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit or drawing power but there are either no credits in the account for a continuous period of 90 days or the cumulative credits in the account are not sufficient to cover interest debited to the account during the period under consideration

Similarly, detailed guidelines have been issued by the Reserve Bank of India in case of bills purchased or discounted, agricultural finance and other credit facilities. Once classified as NPA an account is downgraded to what is termed as sub-standard category and remains so for a period of up to 12 months. The basic characteristic of a sub-standard asset as defined by the RBI is that the current net worth of the borrowers / guarantors or the current market value of the security charged is not enough to ensure recovery of the dues to the banks in full. If an account remains NPA for more than 12

months it is categorised as a doubtful asset. Evaluation of the degree of weaknesses inherent in a doubtful asset on the basis of currently available information like relevant facts and market value and conditions indicates that collection of dues or liquidation in full is highly questionable and improbable. Once an account slips into the doubtful category, it is classified as D1 for a period of up to 1 year, as D2 for a period of more than 1 year and up to 3 years and as thereafter classified as a D3 account.

Accounts that have turned NPA are further classified as loss assets if it is identified by the competent authority to be un-collectible and of such little value that its continuance as a bankable asset is not warranted although there may be some salvage or recovery value due to which it may not have been written off wholly or partly. A mention worthy aspect of loss assets is that classification of an account in this category is not subject to criteria of duration for which the account has remained an NPA.

In order to understand how recovery of NPAs can contribute to the profitability of banks, it may be useful to first analyse how NPAs undermine the profitability of a bank.

In accordance with IRAC guidelines, income from standard loan accounts can be recorded on accrual basis while income from accounts classified as NPA can be reported on actual basis only after credit to the account is actually realised. Therefore, the immediate

impact of the classification of an account as NPA is that it ceases to generate interest income for the bank. Since the interest liabilities of the bank towards its depositors is a constant function, independent of the expected income position of the bank, a reduction in income caused by a non-performing account directly reduces the profit margin from the bank's point of view. Banks also incur a significant amount of administrative expenditure on legal procedures in respect of NPA accounts which also serves as a leakage from its income flow.

A direct and perhaps the most visible manner in which NPAs undermine the profit position of banks may be identified as the drastic escalation of provisioning requirements following the down-gradation of an account from standard to NPA category. At the end of every quarter of a given financial year banks need to make provision out of their income for all accounts in their loan's portfolio, including standard and NPA accounts, in accordance with prudential norms specified by the Reserve Bank of India from time to time. In case of standard accounts banks need to keep aside 0.25% of direct advances extended to agriculture and small and micro enterprises, 1% of loans in the nature of commercial real estate and 0.40% of other categories of advances from their income for purpose of provisioning. However, the rate at which provisioning needs to be made increases sharply following classification of an account as NPA, which will be evident from the following table:

Category	Period	Provisioning for secured assets	Provisioning for unsecured assets
Sub-standard	Upto 6 months	15%	25%
Sub-standard	6-12 months	25%	40%
Doubtful assets	Upto 1 year	40%	100%
Doubtful assets	3 years	100%	100%
Doubtful assets	>3 years	100%	100%
Loss assets	Not applicable	100%	100%

PS: Here period refers to the duration for which the account has been classified in the corresponding category

It is evident from the above table that provisioning requirements for NPAs are several times higher than those applicable to standard accounts and also the scale of provisioning requirements increases with escalation in the sub-categorisation of NPA accounts over a period of time. The impact of this will be more conspicuous from the following hypothetical example. Consider the case of a loan of Rs. 10 lacs extended to a micro business enterprise in the nature of an unsecured advance. The provision required for the loan as long as it remains in the standard category would be in the vicinity of Rs. 2500 and will go on reducing over a period of time as the loan is re-paid regularly as a result of which the outstanding amount will go on decreasing. Now consider how the provisioning requirement will change if the loan is downgraded to NPA category when the outstanding amount remaining is Rs. 9 lacs. Since it is an unsecured advance, for the initial period of 6 months the bank needs to make a provision of Rs. 2,25,000 after which the provision

amount will increase to Rs. 3,60,000 for the next 6 months. Thereafter the provision amount will be Rs. 9 lacs till either the loan is fully re-paid and closed by the borrower or is written off by the bank. The adverse impact that NPAs can potentially have on the profitability of banks perhaps does not need any further elaboration.

The above discussion clearly brings out that NPAs are detrimental to the profit position of a bank and undermine its growth prospects. In order to recover dues in these accounts' banks can take recourse to various legal options like sale of securitised assets or by arriving at a compromise with the borrower via media options like one-time settlement. If the bank is able to recover all pending dues from the borrower it will result in upgradation of the account to standard category which is an outcome that perhaps best serves the interests of both, the bank and the borrower. It can also be inferred from the above discussion that recovery of NPAs

can contribute to profitability of the bank by firstly reducing the quantum of provisioning required and secondly by generating income for the bank if upgraded to standard category. Besides, a reduction in the NPA component of a bank's advances portfolio also has a positive bearing on the future outlook for the bank's growth prospects. This is an intangible benefit of NPA recovery which will indirectly contribute to growth of business of the bank and thereby to its profits.

Banking in India continues to be an important tool to engineer social transformation even today besides its obvious role in driving economic progress. A latent implication of this standpoint is that profits may not be the primary objective or priority of banks and are definitely not the exclusive goal. However, in view of the fundamental changes in the banking environment both locally and globally, enhancing profitability has undoubtedly emerged as an important goal of banking operations. This has necessitated the need to re-orient the structure and functioning of banks to remain aligned with the dynamics of the changing paradigm. Recovery of NPAs is one area which alongside efforts towards business expansion can potentially catapult the profitability of banks to the position which their central role in the economy essentially warrants.



Dr Kalyanlakshmi Chitta
R.O., Greater Pune

NPA Management in Banks

Non-Performing Assets pose a significant challenge to the banking sector and the economy. The issue of Non-Performing Assets has been a significant problem for banks for a long time. High levels of NPAs strain the capacity of banks to lend, impacting economic growth and development. A large proportion of the NPAs are concentrated among big corporate borrowers. High concentration of NPAs in large borrowers poses a systemic risk to the banking sector, affecting financial stability.

Initiative taken by RBI:

The Reserve Bank of India (RBI) has implemented a diverse array of measures to address the Non-Performing Asset (NPA) crisis. These measures span regulatory frameworks, technological integration, and sector-specific strategies aimed at both immediate relief and long-term structural reform. Various steps taken by RBI are:

- **Asset Quality Review (AQR):** Launched in 2015, this initiative involved a comprehensive examination of banks' books to accurately identify stressed assets and ensure transparent recognition of NPAs.
- **Prompt Corrective Action (PCA) Framework:** Revised in 2017, the PCA framework monitors banks' financial health and imposes restrictions to ensure corrective actions for those falling below specific thresholds in areas such as capital adequacy, asset quality, and profitability.
- **Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016:** The IBC

provides a streamlined, time-bound resolution process for stressed assets. It helps enhance recovery rates and creditor bargaining power through a more efficient insolvency process.

- **Debt Resolution Schemes:** Various schemes have been introduced, including the Corporate Debt Restructuring (CDR) for loan restructuring, the Strategic Debt Restructuring (SDR) allowing debt-to-equity conversion, and the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A) to segregate large loans into sustainable and unsustainable portions.

- **Formation of Bad Bank (NARCL):** Establishing the National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) to take over large NPAs from banks, manage these assets, and work towards their recovery or sale.

- **Six-Point Action Plan:** Includes initiatives like the Stressed Asset Stabilisation Fund (SASF), Strategic Restructuring Model Agreements (SRMA), Joint Lenders' Forum (JLF) for collaborative resolution, and the 5:25 scheme for flexible structuring of long-term project loans.

- **Strengthening Supervision:** Enhanced monitoring and supervision of banks through regular audits and inspections to ensure compliance with NPA norms and better risk management.

- **Credit Information Infrastructure:** Improved sharing of borrower credit histories among banks through Credit Information Companies (CICs) to enhance credit appraisal processes.

- **Technological Integration:** Utilization of data analytics and Artificial Intelligence (AI) for better monitoring and early detection of potential defaults, as well as developing early warning systems for pre-emptive measures.

- **Framework for Revitalising Distressed Assets:** This includes measures like the Central Repository of Information on Large Credits (CRILC) to collect, store, and disseminate credit data to help banks monitor exposures of high-value borrowers.

- **Resolution of Stressed Assets - Revised Framework (Feb 2018):** This framework replaced previous schemes and introduced stringent timelines for resolution of stressed assets. It mandates banks to identify stress and implement a resolution plan within a specified period.

- **Supervisory Review and Evaluation Process (SREP):** Part of the Basel III framework, SREP involves continuous monitoring of banks' operational performance with a focus on risk management, governance, and capital adequacy to proactively address emerging risks.

- **Wilful Defaulters Norms:** Strengthened norms to identify and act against wilful defaulters. This includes barring them from accessing further banking finance and legal action to recover dues.

- **Implementation of Large Exposure Framework:** This framework limits the exposure that a bank can have to a single borrower or group of connected borrowers. It thereby reduces concentration risk and potential for large NPAs.

- **Strengthening Governance in Banks:** Introduction of guidelines to improve the governance mechanisms within banks. This includes board composition, audit committee functions, and risk management practices to ensure better oversight.

- **Introduction of Base Rate:** Ensured that banks pass on the benefits of reduced policy rates to borrowers. This helps make credit more affordable and reduces the likelihood of defaults.

- **Targeted Long-Term Repo Operations (TLTROs):** Aimed at injecting liquidity into the banking system, these operations ensure that banks have enough funds to support stressed sectors and borrowers.

Special Mention Accounts (SMA): Identification of accounts showing signs of incipient stress, categorized into SMA-0, SMA-1, and SMA-2 based on the duration of overdue payments to facilitate early intervention.

The NPA situation of India has been improving; especially in Mudra loans, it has shown quite promising results. Gross NPAs of public sector banks against Mudra loans have come down drastically from 4.77 per cent in 2020-21 to as low as 3.4 per cent in 2023-24. Even for private sector banks, there is a drop in NPAs due to Mudra loans to 0.95 per cent. The Reserve Bank of India has suggested that banks with net NPAs less than 6% will be permitted to declare dividends.

Banks are increasing the efforts towards recovery of bad loans and resolution of the stressed assets through a host of measures. The government is keeping a close watch about the NPA and at the same time making sure that recovery does not happen at the behest of coercive practices.

While NPAs are a nationwide issue, certain regions with higher industrial and agricultural activities have seen more significant levels of defaults. States like Maharashtra, Uttar Pradesh, and Tamil Nadu have higher NPAs due to their larger economic bases.

Methods to be used for NPA management are:

- Enhanced monitoring and supervision of banks through regular audits and inspections to ensure compliance with NPA norms and better risk management.

- Selection of borrower based on credit history, due diligence, nature of work and periodic supervision will ensure NPA management.

- Reducing political interference and ensuring professional management in PSBs.

- Using data analytics and AI for better monitoring and early detection of stress in loans.

- Making insolvency and debt recovery processes more efficient and quicker.

- Training bank personnel in risk management and loan monitoring.

- Enhanced Credit Assessment through advance technological tools such as Corpository portal used by our Bank, CRILC portal, CERSAI search of collaterals, Early warning signals & others.

- Improving Monitoring of borrowers to identify potential issues and Early Warning Systems for timely intervention.

- Proactive Engagement with borrowers facing difficulties to understand their challenges and negotiate repayment plans and offer options to restructure loans for borrowers in genuine distress to prevent default.

- Avoid over-exposure to any single sector or borrower to mitigate risks associated with economic downturns.

- Work with external legal and recovery firms to enhance the efficiency of the recovery process for defaulted loans.

- Establish robust risk management policies and frameworks to guide lending practices and ensure adherence to regulatory standards.

- Offer programs to educate borrowers about financial management, which can help them meet their repayment obligations.

- Regularly review lending policies and procedures to adapt to changing market conditions and improve risk assessment methodologies.

We can conclude that addressing the NPA issue is critical for the stability and growth of the Indian economy. Effective management of NPAs requires continuous monitoring, robust credit appraisal, appropriate policy frameworks, and strong legal mechanisms. PSBs are taking effective methods and accepting modern technology for reduction of NPAs. As per 29th Financial stability report of RBI Indian scheduled commercial banks' gross NPA ratio was down to a multi-year low of 2.8 per cent while the net NPA ratio fell to 0.6 per cent at end of March 2024. Therefore, stringent steps with financial literacy of borrower is essential for managing NPA of banking system.



Jitendra Sharma
R.O., Raipur

Challenges Faced by Banks in Debt Recovery Through DRTs

Debt recovery remains one of the most pressing challenges for banks and financial institutions in India. While Debt Recovery Tribunals (DRTs) were introduced under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act (RDDBFI Act), 1993 (now renamed as the Recovery of Debt and Bankruptcy Act (RDB Act), 1993) to provide an efficient mechanism for recovering dues, the process is often hindered by strategic evasion tactics employed by borrowers. Let us explore the various ways in which borrowers evade repayment and the role of Recovery Officers in countering these tactics.

Mechanism of Recovery through Debt Recovery Tribunals (DRTs)

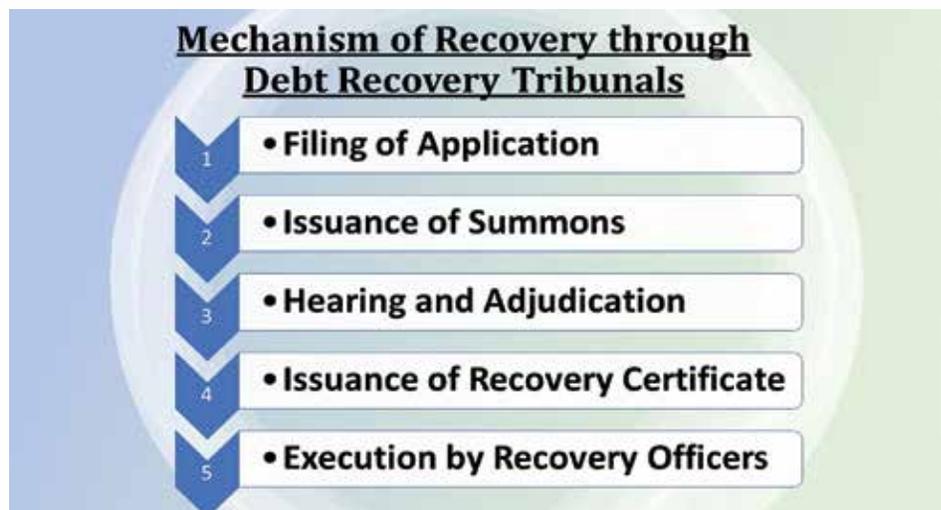
When a bank classifies a loan as a Non-Performing Asset (NPA) due to prolonged default, it approaches the DRT for recovery.

Despite this structured process, banks frequently struggle to recover their dues due to several tactics adopted by borrowers.

Evasion Tactics Used by Borrowers to Delay or Avoid Recovery

1. Stalling Tactics in Legal Proceedings: Borrowers often exploit procedural loopholes to delay the recovery process:

- **Multiple Appeals:** Even after a DRT ruling, borrowers file multiple appeals in the Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) and High Courts, delaying execution.



- **Frivolous Counterclaims:** Borrowers file counterclaims alleging wrongful classification as NPA, procedural lapses, or misrepresentation by the bank, prolonging litigation.

- **Seeking Adjournments:** Frequent requests for adjournments on frivolous grounds slow down proceedings and increase banks' legal expenses.

2. Disposal of Assets and Fraudulent Transactions: To make recovery difficult, borrowers often:

- **Transfer Properties to Family Members:** Borrowers execute sale deeds or gift deeds in favour of relatives to prevent banks from attaching assets.

- **Divert Funds to Shell Companies:** Funds are transferred to multiple accounts, making it difficult for banks to trace recoverable assets.

- **Layering of Transactions:** Borrowers create complex corporate

structures with offshore entities to mask real ownership of assets.

3. Misuse of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016:

- Some borrowers intentionally delay payments to trigger insolvency proceedings, which temporarily protects them from enforcement actions.

- They file for voluntary insolvency to negotiate debt restructuring on more favourable terms.

- Some engage in collusive arrangements with related parties to sabotage genuine bids for asset resolution.

- However, Hon'ble Supreme Court in its judgement has clarified that the mere existence of default does not automatically trigger insolvency, preventing borrowers from abusing IBC provisions (Vidarbha Industries v. Axis Bank (2022)).

4. Preventing Possession of Secured Assets: Under the DRT mechanism, Recovery Officers are empowered to take possession of the borrower's assets. However, borrowers adopt various strategies to obstruct this process:

- **Obstructing Bank Officials:** Borrowers physically resist takeover attempts or use local influence to prevent possession.

- **Filing Police Complaints:** False allegations against bank officials or legal teams create additional hurdles.

- **Destroying or Encumbering Property:** Before possession, borrowers damage the property, rendering it worthless, or lease it to third parties, complicating eviction.

5. Judicial Interventions to Delay Auction Process: Even after attachment, borrowers challenge the auction process in courts, citing:

- **Alleged Undervaluation:** Borrowers claim that their assets have been undervalued to stall auction proceedings.

- **Disputing the Sale Notice:** They challenge technicalities in sale notices or valuation reports to delay the process.

- **Filing Writ Petitions:** Borrowers seek relief from High Courts on constitutional grounds, leading to extended litigation.

6. Political and Social Influence: Some high-profile borrowers leverage political connections or media influence to:

- **Portray Themselves as Victims:** Public campaigns claiming

unfair treatment or highlighting alleged banking sector malpractices.

- **Exert Pressure on Banks:** Political pressure or lobbying to negotiate settlements on favourable terms.

- **Mobilize Public Support:** Borrowers claim persecution, mobilizing employees or unions to protest bank actions.

Role of Recovery Officers in Countering Borrowers' Tactics

The Recovery Officer, attached to the DRT, is responsible for executing recovery orders. Their key functions include:

1. **Issuing Demand Notices:** Directing borrowers to comply with the Recovery Certificate.

2. **Attachment of Property:** Identifying and seizing movable/immovable assets.

3. **Auction of Assets:** Conducting auctions to recover dues.

4. **Issuing Warrants of Arrest:** In extreme cases, ordering the arrest of wilful defaulters.

5. **Other Measures:** These include PAN attachment, recovery through garnishee orders etc.

However, the effectiveness of Recovery Officers is hampered by legal delays, borrower resistance, and logistical challenges.

Conclusion and the Way Forward

Despite the establishment of DRTs and enactment of SARFAESI, borrowers continue to exploit legal loopholes to evade repayment. To enhance debt recovery through DRT there is need for:

- **Strengthening DRT Infrastructure:** More Recovery Officers, digital case management, and strict timelines for execution.

- **Reducing Judicial Delays:** Costs to be imposed on the borrowers for each adjournment and streamlining appellate processes to prevent excessive litigation.

- **Strict Action Against Wilful Defaulters:** Enforcing asset seizures, blacklisting defaulters, and imposing stricter penalties.

The battle between banks and evasive borrowers is an ongoing one. However, banks can counter these challenges by strengthening their role in the recovery process and can significantly improve their debt recovery process through:

- Proactive Compliance with DRT Orders to minimize delays.

- Effective Nodal Officers for swift execution of attachment and auctions.

- Better Coordination with Recovery Officers for asset tracking and enforcement.

With strict implementation of DRT recovery orders and a proactive approach, the debt recovery process can become significantly more efficient, ensuring minimal losses for financial institutions.

Abhijeet Prakash
SAMV,
C.O., Mumbai



अंचल कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 106 वां स्थापना दिवस समारोह



सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पवई



अंचल कार्यालय, वाराणसी



अंचल कार्यालय, रांची



अंचल कार्यालय, भोपाल



अंचल कार्यालय, हैदराबाद



अंचल कार्यालय, गांधीनगर



अंचल कार्यालय, विशाखपट्टणम



क्षेत्रीय कार्यालय, गुंटूर



यूनियन लर्निंग अकादमी, गुरुग्राम



क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा



क्षेत्रीय कार्यालय, आणंद

अंचल कार्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 106 वां स्थापना दिवस समारोह



क्षेत्रीय कार्यालय, कड़पा



क्षेत्रीय कार्यालय, रीवा



क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर



क्षेत्रीय कार्यालय, अनंतपुर



क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम



क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम



क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु



क्षेत्रीय कार्यालय, महबूबनगर



क्षेत्रीय कार्यालय, धनबाद



क्षेत्रीय कार्यालय, अमरावती



क्षेत्रीय कार्यालय, खम्मम

Impact of NPA on Indian Economy

NPNAs are a critical issue for India's banking sector and the broader economy. An asset becomes NPA when it ceases to generate income for the bank. This issue affects the financial stability of banks, restricts credit flow, and hinders overall economic growth.

IMPACT ON THE BANKING SECTOR

- **Decline in profitability:** NPA reduces the profitability of banks due to increase in operating costs and decline in their interest margins. This leads to reduced earnings and hampers their ability to distribute dividends to shareholders.

- **Erosion of capital:** An increase in the level of NPA adds to risk weighted assets which requires the banks to shore up their capital base further. In case of public sector banks, it may put additional burden on the government for recapitalisation of public sector banks.

- **Asset/ credit contraction:** An increasing non-performing asset reduces the banks' ability to lend more which leads to less interest income. It contracts the money stock which may lead to economic slowdown.

IMPACT ON ECONOMIC GROWTH

- **Hindrance to industrial growth:** Industries facing liquidity issues due to restricted credit flow may delay or cancel expansion plans. This reduces industrial output.

- **Slowdown in credit flow to productive sectors:** High NPAs lead to credit crunch and affects

sectors such as agriculture, small and medium enterprises and infrastructure.

- **Stifled job creation:** Job losses in affected sectors and reduced entrepreneurship as limited credit availability discourages new businesses, reducing potential job opportunities and economic activity.

IMPACT ON CORPORATE SECTOR

- Banks burdened by NPAs become risk averse and impose stricter credit norms and reduced working capital making it difficult for corporates to secure loans.

- Banks often raise interest rates, making borrowing more expensive for corporates.

- Stagnation in growth and expansion.

- A high NPA burden creates a negative perception of the financial system, reducing business confidence.

IMPACT ON FISCAL HEALTH

1. Burden on Government Finances

The government, as the principal shareholder in PSBs, often injects capital to maintain their financial stability and ensure compliance with regulatory capital adequacy norms.

Frequent recapitalizations divert public funds from development projects to cover bank losses.

Large-scale capital infusions

to address NPAs contribute to an increase in the fiscal deficit, reducing the government's ability to spend on infrastructure, healthcare, education, and other priority areas.

High NPAs erode the profitability of banks, leading to a decline in the corporate taxes they pay to the government.

A high NPA burden constrains credit flow to businesses, impacting economic activity, reducing corporate profits, and, consequently, lowering tax revenue collection.

2. Increase in Government Borrowing Costs

A stressed banking system, burdened by NPAs, negatively impacts the country's credit ratings.

Lower ratings result in higher borrowing costs for the government in international and domestic markets, increasing the interest outgo in the budget.

3. Impact on Public Debt

Governments often issue recapitalization bonds to inject funds into banks, increasing public debt.

While this is a non-cash outflow initially, it adds to the overall debt burden and future liabilities.

4. Contingent Liabilities

Governments may provide guarantees for loans extended by banks, which can turn into direct liabilities if NPAs increase and banks fail to recover these loans.

5. Opportunity Cost: Opportunity Cost of Funds allocated to tackle NPAs could have been invested in productive sectors such as infrastructure, education, or healthcare, which have long-term benefits for economic growth.

6. Distorted Fiscal Priorities due to Focus on Banking Overhaul : The government may prioritize financial sector reforms over broader fiscal objectives due to the urgency of addressing NPAs, delaying critical structural reforms in other sectors.

7. Multiplier Effects on the Economy

High NPAs constrain credit availability, slowing down industrial output, job creation, and GDP growth, indirectly affecting fiscal health through reduced economic productivity. Limited fiscal space restricts government spending on welfare programs, impacting social equity and long-term development goals.

IMPACT ON EMPLOYMENT

Industries affected by credit shortages due to NPAs often resort to layoffs, increasing unemployment.

High NPAs make bank averse, restricting loan to new ventures. This discourages entrepreneurship and prevents the creation of new job opportunities.

IMPACT ON INVESTMENT CLIMATE

1. Erosion of investor confidence: High NPAs indicate stress in the banking system, reducing trust in its ability to support businesses.

2. To offset NPA losses, banks

may increase interest rates, making borrowing more expensive for businesses and individuals, thereby slowing down capital information.

3. Reduced domestic investment: corporates find it difficult to secure financing for growth and modernization projects, leading to a decline in domestic investments.

4. Decline in foreign investment: High NPAs create uncertainty about the economic and regulatory environment, discouraging foreign investors from entering or expanding in the market.

5. Impact on infrastructure investments: NPAs in infrastructure reduce the ability of private players to participate in public private partnerships slowing down critical projects.

6. Policy uncertainty: High NPAs often trigger regulatory changes and government interventions, creating uncertainty for the investors about the stability of the policy environment.

SOCIAL AND DEVELOPMENTAL IMPACT

1. Inequality and Social Disparities:

Banks with high NPAs often reduce lending to risky segments like small borrowers and rural areas.

This limits access to affordable credit for marginalized communities, exacerbating social inequality.

2. Unemployment and Livelihood Crisis:

Sectors such as infrastructure, power, and real estate, often burdened with

NPAs, face slowdowns, leading to widespread unemployment.

Reduced credit flow to rural areas affects agricultural productivity and rural job creation, widening the economic gap between urban and rural areas.

3. Increased poverty: Financial distress in businesses and reduced rural incomes push vulnerable populations further into poverty.

INVESTOR CONFIDENCE AND FOREIGN INVESTMENT

1. Weakening of Investor Sentiment: High NPAs reduce the attractiveness of Indian banks to both domestic and foreign investors. Weak performance in the banking sector affects stock markets and diminishes foreign portfolio investment (FPI)

2. Impact on Foreign Direct Investment (FDI): A banking system burdened by NPAs sends a signal of inefficiency and financial instability, deterring foreign direct investors. This limits the inflow of capital essential for large-scale projects and industrial growth.

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPACT

1. Stress on Borrowers: For borrowers, especially individual and small-business owners, the inability to repay loans can lead to immense psychological distress.

2. Social Stigma and Isolation: Loan defaults often carry a social stigma in Indian society. Borrowers who fail to repay loans may face alienation from their communities and loss of social standing. This can lead to a cycle of isolation

and reduced support networks, exacerbating mental health challenges.

3. Erosion of Trust in Banking Institutions: As banks face difficulties due to high NPAs, the public confidence in financial institutions diminishes. Borrowers may fear stricter lending practices, while depositors may worry about

the safety of their savings. This erosion of trust can drive individuals and small businesses toward informal credit sources, which often come with higher interest rates and exploitative terms.

4. Increased Crime and Social Instability: Economic distress caused by NPAs can contribute to rising crime rates. Financial

insecurity, job losses, and reduced social mobility may push some individuals toward illegal activities.

Vishnu Vijay Raj
Nedumangad
Branch,
R.O., Trivandrum



हमें गर्व है



दिनांक 03.12.2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में 2024 के राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में सुश्री छोंजिन अंगमों, प्रबंधक को दिव्यांग श्रेणी में सर्व श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



दिनांक 15.12.2024 को दिव्यांग नागरिकों के उत्थान एवं संवर्धन के प्रयासों हेतु "रोटरी बेंगलूरू एबिलिटी" द्वारा श्री राहुल गंभीर, मुख्य प्रबंधक, यूनियन एक्सेस, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अनसंग हीरो (Unsung Hero) पुरस्कार से सम्मानित किया गया।



दिनांक 10 एवं 13.10.2024 तक थाईलैंड में आयोजित एशियन मिनिगोल्फ ओपेन चैंपियनशीप में मास्टर आरव एम. डिसिल्वा सुपुत्र श्रीमती लेटीशिया फर्नांडिस, सहायक प्रबंधक, एडपल्ली शाखा, एर्णाकुलम ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर 19 श्रेणी में स्वर्ण पदक तथा एशियन मेन श्रेणी में इंडिविजुवल नॉकआउट प्ले में रजत पदक जीता।



दिनांक 27.10.2024 को एर्णाकुलम में आयोजित केरल स्टेट तायक्वांडो चैंपियनशीप में मास्टर लिवान दिनेश जॉर्ज सुपुत्र श्री दिनेश जॉर्ज, आरएलपी प्रमुख, क्षे.का., कोल्लम एवं श्रीमती लिन दिनेश, स.प्र., तेवरा शाखा, एर्णाकुलम ने स्वर्ण पदक जीता।



दिनांक 07.12.2024 को मुंबई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय किक बॉक्सिंग (एमएमए) चैंपियनशिप-2024 में श्री शुभम शंकर सुपुत्र श्री शंकर यादव, गौर सिटी शाखा, नोएडा ने स्वर्ण पदक जीता।



12.11.2024 को होली ग्रेस स्कूल माला, एर्णाकुलम में आयोजित राज्य रोलर हॉकी चैंपियनशिप में नीहारिका बिपिन सुपुत्री श्री बिपिन भास्कर, वरिष्ठ प्रबंधक, इडपल्ली, टॉल शाखा, एर्णाकुलम ने कांस्य पदक जीता।



Alternate

DISPUTE

RESOLUTION

Mechanism

The modern judiciary system in India has become much complex and because of these complexities, people seeking justice suffer a lot. The Indian judiciary is heavily burdened with a backlog with approximately 80000 cases in the Supreme court, 5.9 million in various High courts, and approx. 31 million cases in district and subordinate courts as of January 2024, which leads to growing reliance on Alternative Dispute Resolution methodologies. Due to this time lag, a common man is losing confidence in Indian judiciary, so it is important that the faith of people in Indian judiciary must be reinstated. In order to overcome this disadvantage to delayed justice, a new system namely Alternative Dispute Resolution (ADR) came into existence. In this type of system, parties resolve their issues without going to court. Alternative Dispute Resolution bolster up the statement "Justice delayed is justice Denied" as ADR is a fast track system, where

parties get justice very fast. As per the following points explained, it is evident that there is significant difference between Litigation procedures and alternative dispute resolution:

- 1. More flexible:** Under the Indian courts, legal proceedings possess a certain level of rigidity, whereas ADR procedures are much flexible
- 2. Fast track proceedings:** As the ADR process involves lesser formalities and technicalities, parties get decisions at quicker pace
- 3. Confidentiality:** Confidentiality is maintained as proceeding does not happen in court room in front of general public
- 4. Awards:** Award granted under ADR is final and is one need to appeal against award, it can be only sought by opting for litigation
- 5. Choice of mediator or arbitrator:** ADR gives choice to the

parties for selecting the mediator of their own choice

6. Cost effective: ADR is much cost effective as compared to litigation

What is Alternative Dispute Resolution?

It is a technique to resolve dispute and disagreements between the parties by arriving at an amenable settlement through negotiations and discussions. It is an attempt to establish an alternative mechanism other than the traditional methods of dispute resolutions. The ADR mechanism offers to facilitate the resolution of matters of business issues and the others where it has not been possible to initiate any process of negotiation or arrive at a mutually agreeable solution.

Alternative Dispute Resolution comprises of the following different mechanisms:

I. Arbitration: It is a technique

where parties submit their dispute to one or more persons known as arbitrators. The disputes resolution occurs by arbitrator's appointment, who is an independent and impartial third-party entity. It is so referred in form of an agreement and the decision of arbitrator is final and binding upon the disputing parties. The arbitrator decision is also known as award

a. Advantages of arbitration:

- i. Arbitration hearing are held in open courts. No transcripts are taken on public records. This enables in maintaining confidentiality of client agreement.
- ii. Arbitration is less formal, quicker and effective
- iii. Disputes of multiple parties can be resolved easily
- iv. Cases are settled peacefully
- v. Award given is long lasting as it is acceptable to all

b. Various types of Arbitration

- i. Domestic Arbitration
- ii. Adhoc Arbitration
- iii. Statutory Arbitration
- iv. Contractual Arbitration
- v. Fast track Arbitration
- vi. Institutional Arbitration

II. Conciliation: The conciliation process starts when the party opting for it sends a formal invitation to other party. On accepting the invitation, the proceedings start. But, if the party rejects the invitation, proceedings would not start. Conciliator, a neutral third party, is appointed who helps the conflicting parties in resolving their issues in an acceptable manner. Conciliation is a non-binding procedure and a less formal form of arbitration, where there is no requirement of a prior agreement and decision of conciliator is non-binding. Conciliator meets the

disputing parties individually for understanding their issues. The parties are free to reject or accept conciliator's recommendations.

III. Mediation: In mediation, an impartial party called a "mediator" helps two or more disputing parties in resolving their conflicts amicably and reaching a common acceptable agreement. He considers issues of both parties and accordingly advises them. However, the disputing parties controls this mechanism. The role of mediator is restricted to express his opinion and not to impose on the parties. Any person who undergoes 40 hours of required training stipulated by mediation and conciliation project committee of supreme court can be a mediator. Mediator must have at least ten mediations resulting in a settlement and at least 20 eligible mediations to be accredited as a qualified mediator.

Mediation functions in the following steps:

- a. Opening statement
- b. Joint session
- c. Separate session
- d. Closing

IV. Negotiation: When disputed parties come together and try to resolve their conflict through mutual negotiation and understanding, then it is known as negotiation. It is a non-binding process. Here, the decision between the disputed parties is taken without any third-party intervention. The purpose of this method is to achieve a negotiated settlement of disputes between the parties and thus a win-win situation for one another. It is the most common method of alternative dispute resolution.

New guidelines for contracts of domestic procurement

Guidelines on Arbitration:

- a) Arbitration should not be automatically included in procurement contracts or tenders especially in large contracts.
- b) Arbitration can be restricted to disputes with value less than Rs. 10 crores. For higher value disputes, arbitration clauses should be carefully considered and valid as well as reasoned decision approved by senior authorities
- c) Where arbitration is needed, institutional arbitration is preferred where appropriate (considering the cost of the arbitration and the value involved)
- d) Decisions to challenge or appeal should not be taken in a routine manner, but only when the case genuinely merits a challenge or appeal and there are high chances of succeeding.

Guidelines on mediation:

- a) Government agencies are encouraged to opt mediation under the Mediation Act 2023 or negotiated amicable settlements for resolution of disputes, and Government undertakings, may where they consider appropriate e.g., in high value matters, constitute a high-level committee (HLC) for dispute resolution.
- b) Mediation agreement need not be automatically included in procurement contracts. The absence of mediation agreement in the contract does not preclude pre-litigation mediation and such a clause may be incorporated where it is consciously decided not to do so.

For disputes not covered in an arbitration clause and where the alternative methods are unsuccessful, these should be adjudicated by the courts.

Status of Alternative dispute resolution in India:

Statutory Backing: In 1987, the Legal Services Authorities Act was passed to promote out-of-court settlements and the new Arbitration and Conciliation Act was enacted in 1996.

Inclusion of Plea bargaining: Plea bargaining procedure was included in the code of criminal procedure in 2005. Best description of Plea bargaining is as a "Pre-trial negotiation between the accused and the prosecution during which the accused agrees to plead guilty in exchange for certain concessions by the prosecution".

Lok Adalats: Also known as "people's court" comprises an informal setting which helps negotiations in the presence of judge. Where in cases are resolved without undue emphasis on legal technicalities. Lok Adalat award is final and binding on the parties and is not appealable in the court of law

Other Legal Provisions: In 2021, the Arbitration and conciliation (Amendment) bill 2021, was passed in the Lok Sabha to check misuse by "fly-by-night operators" who take benefit of the law for getting favourable awards by fraud. The bill intends to replace the Arbitration and Conciliation (Amendment) Ordinance issued in November 2020

In July 2022, substantial changes to the mediation bill were recommended by the Parliamentary Standing Committee on law and justice

Online Dispute resolution (ODR): NITI Aayog in the recently released report on the future of dispute resolution, discusses the concept of online dispute resolution, its significance, evolution and present status in India. ODR is the usage of

information and communication technology tools to assist parties to resolve their conflicts. In the first phase, ODR shares its fundamentals with ADR mechanism of arbitration, mediation and negotiation. The internet has brought major changes to ADR methods, making them more agile in addition to being time as well as cost-effective. As with regular dispute resolution, ODR allows for filling the gaps of current regulations in international private law to deal with internet cases. In addition, it allows for:

a) Improved early neutral evaluation by enabling involvement of experts regardless of the geographical location

b) Improving negotiation by fostering single or double-blind negotiations, where the liability of the parties is not subject to dispute, however the offer and the demand are kept hidden during the negotiations and are disclosed only if dispute resolution offer by both match

c) Introducing e-mediation, where parties are led through automated choices to achieve consensus before working with a mediator

d) Introducing new forms of arbitration and new rules of procedure (such as the digital submission of evidence and documentation, holding hearings via online platform, etc.)

Alternative Dispute Resolution in Banking sector

Banks and customers of the Banks often have disputes or disagreements over certain specific proceedings, fee and other banking operations. Till now, these conflicts were very difficult to resolve amicably because it could take years in the judiciary. Now, customers and Banks can comfortably resolve

their disputes with the help of ADR. The expenditure on judiciary in terms of GNP is only 0.2% and of this, half of the cases are from banking and financial sector, where compensation has to be claimed. To reduce the burden of cases on the courts, ADR is a huge source of resolving disputes outside the court and not burdening the courts on less expense.

Way Forward : Alternative Dispute Resolution has been successful in minimising the backlog of cases at various levels of judiciary. Only Lok adalats have resolved more than 50 lakh cases every year on average in the last three years i.e. FY 2021-22, FY 2022-23 and FY 2023-24, but still there seems to be very less awareness regarding the availability of these methods. National and State level service authorities should spread more information regarding these facilities, so that they become the first choice of potential explored by potential litigants.

Conclusion: With the formation of various alternative dispute resolution mechanisms, now people can settle their disputes with new possible ways of dispute resolution. But one limitation seen is that there is very less awareness regarding the availability of the alternative dispute resolution techniques. The mechanism of alternative dispute resolution is inexpensive, effective and less time consuming. At last, the mechanisms are only additions to litigation rather than its replacement as some disputes are preferred to be resolved by the court and not through these techniques.

Ankur Narula
CASA & Union
LEAP Vertical,
C.O., Mumbai



Impact of IBC on Resolving Corporate Insolvency

The Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), enacted in 2016, was a watershed reform in India's corporate landscape, aiming to streamline the process of resolving insolvency and bankruptcy. Before the IBC, India struggled with fragmented and inefficient insolvency frameworks under laws such as the Companies Act, 1956, and the Sick Industrial Companies Act, 1985. These frameworks were criticized for their inability to resolve insolvencies promptly, resulting in the erosion of asset value and prolonged creditor distress. The IBC introduced a unified, time-bound, and creditor-driven approach, replacing the debtor-centric model with a framework designed to maximize value.

The IBC introduced a Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) that prioritizes creditors' rights while maintaining the potential for the debtor's revival. It empowers financial and operational creditors to initiate CIRP and assigns resolution professionals to oversee the process, supported by the National Company Law Tribunal (NCLT) as the adjudicating authority.

Impact of the IBC on Resolving Corporate Insolvency:

- **Improvement in Recovery Rates:** One of the significant successes of the IBC has been its positive impact on recovery rates for creditors. According to the World Bank's "Ease of Doing Business

Report 2020", India's recovery rate improved to 71.6 cents on the dollar, compared to 25.7 cents pre-IBC.

- **Reduction in Resolution Time:**

The IBC's focus on time-bound resolution has been a game-changer. Before its enactment, the average time for resolving insolvency cases exceeded four years. The IBC aims to conclude CIRP within 270 days, though practical challenges often lead to delays. Nonetheless, it has substantially reduced the average resolution time compared to earlier frameworks.

- **Creditor Empowerment:**

By prioritizing the Committee of Creditors (CoC) in decision-making, the IBC has shifted the balance of power from debtors to creditors. This creditor-driven model ensures that the resolution plan maximizes value for stakeholders.

- **Boost to Economic Growth:**

The IBC has contributed to a healthier credit environment, attracting domestic and foreign investments. By resolving large-scale insolvency cases such as Essar Steel and Bhushan Steel, the IBC demonstrated its capability to handle complex cases, thereby boosting investor confidence.

- **Reduction in Non-Performing Assets:**

The IBC has been instrumental in reducing NPAs in the banking sector. Banks have recovered substantial amounts through resolution plans, helping improve their financial health.

According to the Reserve Bank of India, recoveries through IBC significantly outpaced recoveries under earlier mechanisms.

Amendments done to strengthen the IBC: The following amendments had been done to IBC to strengthen its effectiveness:

- **Real estate allotments:** The IBC was amended to recognize homebuyers as financial creditors and to allow them to appoint authorized representatives to attend committee of creditors (CoC) meetings.

- **Voting threshold:** The voting threshold for routine CoC decisions was reduced from 75% to 51%. For key decisions, such as approving the resolution plan, the threshold was reduced to 66%.

- **Withdrawal of a resolution application:** The IBC was amended to allow a resolution application to be withdrawn after the resolution process has started, but only with a 90% vote of the CoC.

- **Appointment of the IRP:** The IBC was amended to have the Adjudicating Authority appoint the IRP on the insolvency commencement date, instead of waiting 14 days.

- **Authorized representatives:** The IBC was amended to provide a fee for authorized representatives based on the number of creditors in a class.

Proposed Amendments to Strengthen the IBC: As Honorable Finance Minister, in her Budget speech, hinted at impending changes to the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), industry experts suggest priorities should include extending pre-packaged insolvency to larger firms, codifying group insolvency norms, and clarifying project-wise insolvency processes. She announced plans to reform and strengthen tribunals to expedite insolvency resolution, establish more tribunals, and assign some exclusively to cases under the Companies Act.

The IBC has been amended frequently, including the introduction of the pre-packaged insolvency resolution process (PPIRP) for micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in 2021. However, to address these challenges, several amendments and reforms are necessary:

- **Strengthening the NCLT Infrastructure:** Increasing the capacity of the NCLT by appointing more judges, establishing additional benches, and investing in technology can alleviate the backlog of cases. Introducing specialized insolvency benches could further improve adjudication quality.

- **Imposing Strict Timelines with Penal Consequences:** To ensure adherence to timelines, the IBC should impose penalties for unjustified delays by resolution professionals, creditors, or other stakeholders. Expediting approvals for resolution plans through fast-track mechanisms can also reduce delays.

- **Enhancing Asset Valuation**

Mechanisms: Standardizing valuation practices and adopting global best practices can minimize discrepancies in asset valuation, ensuring fair recoveries for creditors. Establishing a regulatory framework for valuers can improve transparency and reliability.

- **Creditor-led resolution process:** an expert committee of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) had proposed the creditor-led insolvency resolution process framework for out-of-court initiated insolvency.

- **Revising Liquidation Preferences:** Amending the IBC to provide clearer guidelines on liquidation preferences can prevent disputes and ensure equitable treatment of creditors. Priority should be given to secured creditors while balancing the interests of unsecured creditors and operational creditors.

- **Expanding the Scope of Pre-Packaged Insolvency:** The pre-packaged insolvency framework should be extended beyond MSMEs to large corporations. Providing incentives for pre-packaged deals and raising awareness about their benefits can encourage early resolutions.

- **Introducing Mediation Mechanisms:** The IBC can incorporate mediation as an alternative dispute resolution mechanism for operational creditors and small disputes. This can reduce the burden on the NCLT and resolve minor cases swiftly.

- **Capacity Building for Resolution Professionals:** Strengthening the training and accountability of insolvency

professionals is crucial. Introducing certifications, periodic assessments, and a robust grievance redressal mechanism can improve the quality of resolutions.

- **Protecting Stakeholders During Liquidation:** Introducing safeguards for employees, minority creditors, and other stakeholders during liquidation can make the process more inclusive. Creating a framework for social safeguards, such as re-employment support for displaced workers, could be beneficial.

Conclusion: The IBC has transformed India's insolvency resolution landscape, providing a robust framework to tackle corporate insolvency efficiently. It has improved recovery rates, empowered creditors, and fostered a healthier credit culture. However, persistent challenges such as delays, low recoveries in some cases, and inefficiencies in the adjudicatory process demand urgent attention. Misuse of the code by operation creditors and even promoters are also a big concern in the recent years.

By addressing these shortcomings through strategic amendments, the IBC can achieve its full potential and further enhance India's business environment. As India aspires to become a \$5 trillion economy, a resilient insolvency framework like the IBC will play a pivotal role in ensuring sustainable economic growth and financial stability.



Dr. Deepak Kumar
U.L.A., Lucknow

शहीद

नील द्वीप जिसका आधिकारिक नाम शहीद द्वीप है, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का एक द्वीप है।

यह प्रशासनिक रूप से दक्षिण अण्डमान ज़िले के अंतर्गत आता है और पोर्ट ब्लेयर से 36 किमी पूर्वोत्तर में स्थित है और क्षेत्रफल केवल 13.7 वर्ग किलोमीटर है। शहीद द्वीप का नाम पहले ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नील के नाम पर नील द्वीप रखा गया था जिसे दिसंबर 2018 में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। यह द्वीप अपनी समृद्ध जैव विविधता, अप्रयुक्त प्रवाल भित्तियों, सफ़ेद रेतीले समुद्र तटों, प्राकृतिक चट्टान संरचनाओं और उष्णकटिबंधीय वनों के लिए लोकप्रिय है। शहीद द्वीप के खूबसूरत समुद्र तटों जिसमें सफ़ेद रेत और साफ़ नीले आसमान के निर्बाध दृश्य, क्रिस्टल साफ़ पानी, लुभावने सूर्यास्त और सूर्योदय इसे अंडमान

द्वीप

और निकोबार में घूमने के लिए सबसे अच्छे शहरों में से एक बनाता है. शहीद द्वीप पर वाटर स्पोर्ट्स जैसे स्कूबा डाइविंग, स्नोर्कलिंग, ग्लास बॉटम बोट राइड आदि उपलब्ध हैं. शहीद द्वीप में घूमने के लिए भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच, सीतापुर बीच और रामनगर बीच उल्लेखनीय स्थान हैं जिन्हे रामायण के पौराणिक पात्रों के नाम पर रखा गया है, शांत वातावरण में गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए शहीद द्वीप की यात्रा उत्कृष्ट है.



ए. वी. लक्ष्मी
अं. का., विशाखपट्टणम



Tackling Wilful Defaulters

From Default to Public Accountability



Picture this: A customer enters a busy bank branch on a Monday morning. He is there for a routine deposit, but something unusual catches your eye. On a large digital display in the lobby are faces and names of individuals tagged as “Wilful Defaulters,” with a bold headline reading, “Unpaid Loans Exceeding Rs. 1 Crore!” This isn’t just a notice tucked away in some obscure corner- these photographs and details are right in the public eye, underlining one unmistakable message: Banks are done taking Wilful defaults lightly.

In June 2015, readers of a local newspaper were startled to see an unexpected set of photographs splashed across its pages: ten individuals declared “wilful defaulters” by Andhra Bank. Fast-forward to early 2020, and the Bank of India took an even bolder step- designing “Wanted” posters bearing the faces of select borrowers who had deliberately refused to repay their loans, despite demonstrably having the means to do so. These striking tactics were not mere publicity stunts; they revealed a growing willingness by banks to “name and shame” customers who

intentionally try to dodge debt obligations. Yet beyond the drama of such public exposure lies a deeper question: how might publishing the photographs of these defaulters actually benefit the everyday saver, taxpayer, or small business owner?

Very recently, Reserve Bank of India revealed that the top 100 Wilful defaulters collectively owe close to Rs. 1.96 lakh crore, a stark reminder of how pervasive and serious the problem of Wilful defaults has become. For the common man, bank loans gone bad don’t simply vanish- they eventually translate into higher interest rates, decreased lending capacity, or, in dire scenarios, government bailouts funded by public money. By tagging individuals as wilful defaulters and circulating their identities in the public domain, banks hope to deter further misconduct and accelerate debt recovery. When large borrowers are pressured into repaying, financial institutions can stabilize their lending operations, safeguarding depositors’ funds and keeping the cost of credit in check.

Ultimately, “naming and shaming” not only shines a spotlight on irresponsible borrowers but also

helps ensure a healthier banking system - one that protects honest savers, fosters trust, and shores up the economy for everyone. As India strives to further strengthen its financial sector and chase its ambitious economic goals, the RBI’s stance on Wilful default has grown tougher- extending from legal suits to criminal charges to the radical idea of photograph publication.

Let us delve into the exhilarating yet complex domain of Wilful defaulters, illustrate how the publication of photographs can drastically reshape repayment discipline, analyse the synergy between financial regulation and NPA management, and tell real-life cautionary tales of individuals like Vijay Mallya, Mehul Choksi, and Nirav Modi.

Wilful Defaulters: A Persistent Issue in NPA Management: Non-Performing Assets (NPAs) have long been a significant challenge for banks globally. While many arise due to market conditions or genuine operational setbacks, wilful defaulters present a more troubling scenario. These are borrowers who have the capacity to repay their loans but deliberately choose not to. Such defaulters often misuse funds

or siphon them off, exacerbating the financial strain on banks.

Why Wilful Defaults Matter?

- **Scale of Defaults:** Though wilful defaulters account for a smaller portion of NPAs numerically, their financial impact is disproportionately large, often amounting to thousands of crores of rupees.

- **Public Interest:** Bank funds largely come from depositors, ordinary citizens who trust these institutions to safeguard their money. Wilful defaults ripple through society, affecting depositors, shareholders, and taxpayers.

Key Regulatory Measures: Over the years, the Reserve Bank of India (RBI) has developed frameworks to address wilful defaults effectively:

- **Early Guidelines:** Introduced in the 1990s, these guidelines distinguished intentional defaults from genuine business failures. Subsequent refinements in the 2000s detailed acts like fund siphoning and unauthorized asset disposal.

- **Two-Tier Committee System:** The RBI mandates banks to set up Identification and Review Committees to ensure fair classification. These committees evaluate evidence, allow borrowers a fair hearing, and decide on classifications.

- **Public Disclosure:** To deter misconduct, banks are allowed to publish photographs of wilful defaulters in newspapers or on branch notice boards, provided a board-approved, non-discriminatory policy is followed.

- **Master Direction on Wilful Defaulters (2024):** This directive

consolidates earlier guidelines and emphasizes fair procedures and strict enforcement. It also allows for legal actions, including barring further loans and criminal suits.

Defining "Wilful Defaulters": According to the RBI, a wilful defaulter is someone who fails to meet repayment obligations despite having the capacity to do so. Specific criteria include:

- **Non-repayment despite capacity:** Borrowers refuse repayment despite having funds.

- **Diversion of funds:** Loans are used for purposes other than the intended business.

- **Siphoning of funds:** Borrowed funds are misused, leaving no traceable assets.

- **Asset disposal:** Collateralized assets are sold without lender's knowledge.

- **Failure to meet commitments:** Borrowers or promoters fail to inject agreed-upon equity.

Globally, definitions vary, but intent remains the key factor distinguishing wilful defaulters from those who genuinely cannot repay. This classification carries severe consequences, including restricted access to credit, reputational damage, and legal liabilities.

Classification Process: Guidelines and Norms: The process of identifying and classifying wilful defaulters involves a rigorous review:

- **Assessment by Identification Committee:** Banks establish committees to review evidence and issue show-cause notices to the borrower within 21 days.

- **Proposal Submission:** After

reviewing responses, the committee may recommend wilful defaulter classification to the Review Committee.

- **Notification and Representation:** Borrowers are notified of the decision and given an opportunity for a personal hearing.

- **Final Decision:** The Review Committee delivers a final verdict, which is communicated to the borrower. Borrowers cannot be represented by lawyers in these internal proceedings.

RBI imposes many restrictions once the account is classified as wilful defaulter which are as under:

- **Bar on Additional Credit Facilities:**

- Lenders are prohibited from granting any additional credit facilities to wilful defaulters or entities associated with them.

- This restriction remains in effect for one year after the wilful defaulter's name is removed from the list by the lender.

- **Restriction on New Ventures:** Lenders cannot provide credit facilities for floating new ventures to wilful defaulters or associated entities for five years after their name is removed from the list of wilful defaulters.

- **Ineligibility for Credit Restructuring:** Wilful defaulters and entities associated with them are not eligible for the restructuring of credit facilities.

- **Renewal or Enhancement of Credit Facilities:** Banks are prohibited from renewing, enhancing, providing fresh credit facilities, or restructuring existing

facilities as long as the name of the promoter, director, or responsible person remains on the list of wilful defaulters.

Further, long-Term impacts of classification include - wilful defaulters face reputational damage, limited borrowing opportunities, and social ostracism. Their digital footprint often deters future investors and collaborators.

Broader Implications for the Financial Sector: From a regulatory perspective, exposing wilful defaulters protects banks and depositors by deterring misconduct. However, aggressive public shaming can have unintended consequences:

- **Entrepreneurial Risk-Taking:** Fear of misclassification may discourage entrepreneurs from pursuing bold ventures.

- **Trust in the System:** Inconsistent or politically influenced enforcement undermines public trust in financial institutions.

While public shaming acts as a strong deterrent, its implementation must be safeguarded by legal frameworks to prevent misuse. Leveraging technology, enhancing credit scoring, and fostering international collaboration can gradually reduce the need for such measures, paving the way for a fairer financial system. Tackling wilful defaults isn't merely about punishing offenders- it's about protecting the economy and ensuring public trust in financial institutions.

Internationally too, various measures to control wilful defaulters can be witnessed. For example, in China, defaulters are listed on public "blacklists" and face restrictions on travel, luxury purchases, and private school enrolments. While effective

in some cases, such policies spark debates about civil liberties and collective punishment.

One innovative solution to address the menace of wilful defaults could involve linking financial data with the Aadhaar database. Aadhaar's unique identification system can create a centralized framework, allowing authorities to track defaulters, flag fraudulent activities, and prevent multiple identities. Such integration would empower banks to monitor financial activities in real-time, ensuring wilful defaulters are flagged across institutions, restricting their access to new loans or restructuring opportunities. However, this requires robust privacy safeguards and strict data protection laws to prevent misuse. If implemented judiciously, Aadhaar integration could revolutionize accountability and bring transparency to India's banking system.

As India celebrates its 76th Republic Day in 2025, the RBI's bold move to expose wilful defaulters resonates with the values of justice, equality, and accountability that underpin the Constitution. This initiative reflects a commitment to protecting taxpayers and depositors while addressing the ethical challenge of balancing transparency with individual rights. On this Republic Day, the RBI's efforts remind us that economic accountability is integral to a thriving democracy, where bold reforms must be tempered with fairness and respect for constitutional ideals.

Daljeet Singh
Z.L.C., Powai,
Mumbai



नव वर्ष

नव वर्ष नवीन आशा का प्रतीक
करो मेरी वंदना स्वीकार,
विनत शीश कर करूँ अर्चन
खुलें तुममें सत्कर्म के द्वार.

जीवन तमोमय किया मैंने
कर्महीनता से दीप बुझे,
कदम बढ़े लक्ष्य से विपरीत
आज नहीं कोई पथ सूझे.

सूना-सूना सकल मही है
हृदय देश है निर्जन-निर्जन,
तन-मन की कोई सुध नहीं है
नहीं है कोई दिग्निर्देशन.

आशा विश्वास अब तुम्हे समर्पित
होंगे परिवर्तन का सूत्रधार,
मन की अभीप्साओं के फलन का
तुम ही हो एकमात्र आधार.

नव वर्ष नवीन प्रज्ञा दो मुझे
बाधित हो आत्मघाती प्रवृत्ति,
सद्लक्ष्य की ओर करूँ प्रस्थान
दीनता-हीनता से पाऊँ निवृत्ति.

एकमेवाद्वितीय लक्ष्य की ओर
करूँ एकाग्र हो मनोनियोग,
निर्दिष्ट वीथी का अविचल पथिक
मैं पाऊँ वर्षभर तेरा सहयोग.

सुदीप कुमार दास
क्षेत्र प्रमुख, जालंधर



Tools and Techniques for NPA Management and Recovery

Non-Performing Assets (NPAs) have become a major challenge for banks and financial institutions across the globe. An NPA is a loan or advance where the borrower defaults on payment of interest or principal for a specified period. In India, this period is usually 90 days. As NPAs increase, they affect a bank's financial health, erode profitability, and create liquidity problems, making NPA management and recovery vital to sustaining the operations of the institution.

Tools and Techniques for NPA Management and Recovery

The effective management and recovery of NPAs requires a multifaceted approach. Financial institutions utilize a wide array of tools and techniques to address NPAs and recover dues. These range from proactive risk management tools to legal frameworks, technological innovations, and collaboration with external agencies.

1. Early Detection and Monitoring Systems

Early detection of NPAs is a critical component in managing them. Financial institutions use a combination of technology and manual intervention to identify potential problems early in the loan life cycle.

- **Credit Risk Management Systems (CRMS):** CRMS use data analytics to assess the creditworthiness of a borrower. These systems consider the financial history of a borrower, repayment behaviour, and the borrower's sector to predict the risk of default. By monitoring these factors, banks can identify borrowers who are likely to default and take pre-emptive actions to mitigate the risk of NPAs.

- **Portfolio Management Systems (PMS):** PMS is used by banks to track the entire loan portfolio. These systems provide alerts when a loan shows signs of becoming an NPA, allowing banks to take corrective action quickly. A well-functioning PMS helps in early detection and reduces the chances of a loan becoming non-performing.

- **Stress Testing and Scenario Analysis:** Stress testing tools assess how loans would behave under extreme conditions. For instance, how would a loan portfolio react if the economy enters a recession or if the borrower's sector suffers a crisis? By testing various scenarios, banks can predict and prepare for future risks, making it easier to identify troubled loans early and take preventive actions.

2. Loan Restructuring and Rescheduling

When a borrower faces financial stress, restructuring or rescheduling of loans may become necessary. These tools can help restore the borrower's ability to repay the loan and, in turn, protect the lender's interests.

- **One-Time Settlement (OTS):** A popular technique used by banks to recover loans is the One-Time Settlement (OTS), where the borrower and the lender agree on a reduced settlement amount. The borrower typically makes a lump-sum payment which is less than the outstanding dues. In return, the loan account is closed. OTS is an attractive option for both borrowers in distress and lenders, as it provides a quick resolution and avoids long-drawn-out legal processes.

- **Rescheduling of Loans:** When borrowers face temporary repayment issues, rescheduling the loan terms can help provide relief. This could involve extending the repayment period, reducing the interest rate, or offering a grace period before repayments begin. Rescheduling allows borrowers to manage their cash flow better, thus reducing the chances of the loan turning into an NPA.

- **Debt-for-Equity Swap:** In cases where the borrower is a corporate entity, a debt-for-equity swap may be considered. In this scenario,

part of the loan is converted into equity in the borrower's company. The lender becomes a shareholder in the company, which may enable future recovery of the debt if the company recovers and grows. This technique is common for businesses that are unable to repay but still hold significant potential in the long run.

3. Recovery Through Legal Actions

Legal tools play a significant role in the recovery process. These mechanisms allow lenders to take possession of collateral and sell assets to recover dues when all other methods fail.

- **Debt Recovery Tribunals (DRTs):** DRTs were established under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, to expedite the process of recovering NPAs. Banks can approach DRTs for the recovery of loans, and the tribunal issues a verdict on the sale of assets or other recovery measures. The DRT process is typically faster than conventional court procedures.

- **SARFAESI Act:** The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act allows banks to take possession of a borrower's collateral without the intervention of courts. The act also permits banks to sell the borrower's assets through an auction process to recover the dues. This legal tool is highly effective in ensuring faster recovery and reducing the burden of NPAs.

- **Insolvency and Bankruptcy Code (IBC):** For large-scale defaults, the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) provides a framework for debt resolution. The IBC allows banks to take the borrower through a structured insolvency process, either to restructure the business or liquidate it. The introduction of IBC has been a significant step in the recovery of NPAs, as it offers a clear path for resolution with time-bound processes.

4. Technology and Data Analytics

Banks are increasingly leveraging technology to enhance their NPA management processes. The advent of data analytics, artificial intelligence (AI), and machine learning (ML) has transformed how institutions assess and manage loan defaults.

- **Artificial Intelligence and Machine Learning:** AI and ML are used for predictive analytics, identifying potential NPAs long before they become problematic. By analysing historical data and borrower behaviour, AI models can predict which loans are at risk of becoming NPAs, allowing banks to take preventive measures early. ML algorithms also help in credit scoring, identifying patterns of non-performance and offering insights into borrower behaviour.

- **Big Data Analytics:** Big data allows banks to process large volumes of borrower data to detect early signs of financial distress. By mining this data, banks can predict payment defaults and identify systemic risks. It also helps in segmenting customers based

on repayment behaviour, thereby enabling targeted interventions for high-risk borrowers.

- **Blockchain Technology:** Blockchain technology can be used to improve transparency and accountability in the loan origination and monitoring process. The decentralized and tamper-proof nature of blockchain ensures that loan records are accurately maintained, reducing the chances of fraud and improving loan tracking. This can greatly enhance the recovery process.

5. Asset Reconstruction Companies (ARCs)

ARCs are entities that specialize in acquiring distressed assets (NPAs) from banks. They use their expertise to restructure or manage the assets and attempt to recover the dues. ARCs can either sell the assets, restructure the debt, or attempt to recover the loan through legal means. Selling NPAs to ARCs helps banks offload troubled assets focus on quality business and improve their balance sheets.

The role of ARCs in India has been significant in resolving NPAs, especially for large corporate loans, where the involvement of ARCs allows for specialized management of distressed assets.

6. Corporate Debt Restructuring (CDR)

CDR mechanism provides a structured approach to the restructuring of corporate debt. It helps borrowers who face temporary financial difficulties, enabling them to repay loans without defaulting. Under the CDR framework, banks may agree to

extend repayment periods, reduce interest rates, or even grant new loans to support the business. The CDR mechanism helps resolve NPAs in a non-litigation environment and aims to return businesses to profitability.

7. Sale of Non-Performing Assets:

Banks can also choose to sell NPAs to other financial institutions or third parties through public auctions or private placements. Selling NPAs helps in removing these from the bank's balance sheet and provides immediate liquidity. However, the price realized may be lower than the outstanding loan amount, leading to a loss for the bank.

8. **Public-Private Partnerships (PPP)** are formed to address NPAs. Under such arrangements,

the government collaborates with private entities to resolve distressed assets. This could involve setting up specialized agencies to handle NPA recovery or creating a joint venture to manage troubled assets. PPP models are useful in leveraging the expertise and resources of both public and private sectors to address the NPA problem comprehensively.

Conclusion: Non-performing assets (NPAs) pose a significant challenge to banks and financial institutions worldwide. The effective management and recovery of NPAs require a combination of tools, techniques, and proactive strategies. Tools such as early detection systems, loan restructuring, legal mechanisms, technology, and asset

reconstruction companies play vital roles in NPA management. As technology continues to evolve, financial institutions will increasingly rely on data analytics, AI, and machine learning to streamline NPA management and recovery processes. The use of legal frameworks like DRTs, SARFAESI, and IBC further strengthens the recovery process. By utilizing a combination of these tools, financial institutions can mitigate the risks posed by NPAs and ensure their long-term financial health.



Revathy S
R.O., Kollam

In the Eye of the Hurricane

In the eye of the hurricane,
she is always there,
A true hero, she is one of us that dares.
Whatever the situation
with poise in her walk,
Mends not just structures
but births her own work.

Her range may be of thunder
on whose wisdom is peace,
What was once silence equals action
and up she goes like a kite.
Due to the brilliant visions in her mind's plan,
She forces herself to the future
with courageous and frightened hands.

One flame amongst other flames is what she remains,
A peaceful warrior, a soldier for justice without end.
The night is abandoned ashamed of its emptiness,
Filled with laughter as dawn is bright,
so is her embracing smile.

Now warrant for the woman
who knows how valuable she is,
A Woman, a Nature, a Woman, a Land.
And with every new step,
she takes one more step,
Today, she brings light for endless tomorrows.



Chandana Kumari
R.A.V., C.O., Mumbai

Enhancing Loan Portfolio Health with SMA

SMA stands for specially mentioned accounts. In the year 1993 prudential accounting norms has been implemented in the Banks based on the recommendation of the Narsimham Committee on financial sector reforms (1991). The committee has recommended three norms.

1. Income recognition
2. Asset classification
3. Provisioning

Income recognition meaning is that up-to what time the account will be able to generate the income, or the account will be a performing asset. The performing asset will be classified as a performing asset until it is satisfying the norms of the Income recognition and asset classification. If at any point of time the terms and conditions of the IRAC norms did not satisfy the account will be classified as a nonperforming asset and it will be termed as Non-performing asset (NPA).

Is SMA performing asset or non-performing asset? : Performing assets are those assets of the bank which can perform or earn interest income. As per the RBI IRAC norms

any asset will stop earning interest once it turns to non-performing or after 90 days of the due date the principal or interest. Though SMA accounts are performing accounts, these accounts are more prone to become NPA than the standard stress-free account. After doing proper monitoring of the SMA accounts the probable NPAs of the future can be easily avoided.

Any credit facility, be it revolving in nature or non-revolving, does not turn to NPA immediately after due date. but needs to go through the process of specially mentioned account. So, it will be appropriate to say that the specially mentioned accounts (SMA) are standard accounts but stressed in nature. Once the account crosses the timelines of SMA it becomes a non-performing asset or NPA.

SMA Types	Term Loans (overdues Days)	Running A/Cs (Out of Order Days)
SMA-0	0-30	NA
SMA-1	31-60	31-60
SMA-2	61-90	60-90

Irregular accounts: Stock statements are updated in the cash credit accounts for defining the drawing power of the accounts. The updation of account statement should be not older than three months. Else, the account will be treated as irregular account. The Cash credit account will also turn to Non-performing account if the irregularity continues for the next 90 days. Therefore, timely updation of the stock statement is very crucial to maintain the health of the cash credit account.

Asset Classification: The classification of the assets is the borrower wise classification not account wise, Hence, if one credit facility is classified as sub-standard for any reasons, then all the credit facilities linked with same customer identification number will be classified in the same category.

The bills discounted under letter of credit favouring a borrower may not be classified as a non-performing asset (NPA), when any other facility granted to borrowers is classified as NPA except when documents under LC are not accepted on presentation or the payment under the LC is not made on the due date by the LC

issuing bank for any reason.

Special Mentioned Accounts (SMA A/Cs) as credit monitoring tool:

Banks have taken the SMA concept of the Reserve Bank of India positively and using the SMA facility as a robust credit monitoring tool. Banks are churning out the big data and the segregation is being made based on the SMA filtration prefixed machine language criteria. Thereafter a list of account is being generated with classification of the SMA-0, SMA-1 and SMA-2, where, SMA-2 accounts need to be addressed on higher priority and these will turn into NPAs after the 61-90 days of stress period.

SMA account list can be effectively utilized in Bank in follow-up for recovery and monitoring of the loan portfolio of any branch in the following ways:

1. Position of portfolio under stress:

The SMA list of accounts show the stressed portfolio of the bank. Stress free portfolio is always favourable for all the major stakeholders of the bank, be it investors, customers or the management. According to the position of stressed assets various stakeholders take decisions either in favour of the bank or against it.

2. Tenor of stressed account/ Timely Identification of stress accounts:

The SMA data also reflects the period of stressed position of the portfolio. It can reveal account wise data and the period also for which the account is under stressed category. Timely identification of the stressed accounts allows the banker and the borrower both to initiate correctives measures to save these accounts from slipping into Non-performing assets.

3. Scrutinizing the reason for stress:

Loan accounts can appear in the SMA list for financial reasons and also for non-financial reasons.

The list of SMA categorized accounts provides the reason for the stress of the account. Based on the information corrective actions can be taken.

4. Formulating corrective action plan:

Once the reasons for SMA are identified, then to address the SMA account required corrective action plans can be taken. These action plans may be taken at bank level or at borrower's level also. The accounts appearing in the SMA category may be fixed after a prompt action plan. Once the action plan is identified proper measures it needs to be taken and the stressed portfolio of the bank can be converted into a stress-free loan portfolio.

Action Plan for Bank:

- A. Timely review and renewal of the account
- B. Updating the stock statement received from borrowers
- C. Follow-up with the borrower for recovery of overdue
- D. To increase margin, security and guarantee, if any is required
- E. To route all transactions through bank
- F. To maintain sole banking arrangements etc.

Action Plan for Borrower:

- A. Maintaining balance in operative account
- B. Timely paying the EMIs
- C. Providing required financials for timely renewal of the account
- D. Submitting stock statements on regular basis

5. Monitoring action plan: Once the action plan has been decided and implemented it is required to monitor the action plan on regular basis until the account smoothly sustain under stress-free category.

6. A Signal for probable NPA accounts: Some accounts regularly

appears in the SMA list due to non-repayment of overdues in time. These accounts that are being treated stressed account can turn to NPA at any point of time. This indicates that the firms or company's business operation are not running smoothly or that it has major liquidity issue.

7. Overdue Position of account:

The SMA list shows the overdue position of the account based on the duration of overdue status. After scrutinizing the SMA accounts one can easily find out how much amount is required to satisfy the overdue demand of any overdue loan account. Further after contacting the borrower a banker can request for the overdue position of the account that need to be deposited so that the account can come out from the stressed category due to non-repayment of the principal or interest.

8. Timeline for Improvement of the health of the portfolio:

A prudent banker is someone, who is very much concerned about the stressed portfolio of the loan. After giving proper attention a banker can make the loan portfolio less risky. Proper monitoring and support, if required can help the business firm to rejuvenate its business. Through proper monitoring of SMA account probable NPA can be deferred or better still prevented.

Conclusion: Based on the above discussions we can easily conclude that SMA is a very important credit monitoring tool that is used by the bank to monitor the performance of the account from turning to Non-performing account.



Md. Shahid Kabeer
Z.L.C., Bhubaneswar

यूनियन धारा एवं यूनियन सृजन संवाददाता समीक्षा बैठक सह सम्मेलन - 2024



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की गृह पत्रिका 'यूनियन धारा' तथा 'यूनियन सृजन' के संवाददाताओं की समीक्षा बैठक सह सम्मेलन का आयोजन दिनांक 24.10.2025 को श्री पंकज द्विवेदी, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में जेडएलसी, हैदराबाद में किया गया। श्री चन्द्र मोहन मिनोचा, मुख्य महाप्रबंधक (मासं), श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद, श्री गिरीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (मासं एवं राभा), श्री अम्बरीष कुमार सिंह, उप महाप्रबंधक (मासं), श्री विवेकानंद, सहायक महाप्रबंधक (रा.भा.), श्रीमती गायत्री रवि किरण, संपादक सहित यूनियन धारा के स्टाफ सदस्य, संवाददाता और प्रूफ रीडर्स इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अतिथि वक्ता के रूप में डॉ ऋषभ देव शर्मा, संस्थापक महासचिव, साहित्य मंथन ने 'साहित्य की उभरती प्रवृत्तियों' विषय पर संवाददाताओं का मार्गदर्शन किया। कार्यपालक निदेशक महोदय के कर कमलों से 'यूनियन धारा' तथा 'यूनियन सृजन' के जून 2024 अंक का विमोचन किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए 6 यूनियन स्टार संवाददाता, 25 स्वर्ण स्टार संवाददाता तथा 20 रजत स्टार संवाददाता पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री पंकज द्विवेदी, कार्यपालक निदेशक महोदय ने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि यूनियन धारा के प्रकाशन का सुदीर्घ इतिहास है और इस गौरवशाली यात्रा का एक हिस्सा बनना गौरव का विषय है। उन्होंने सभी संवाददाताओं से आग्रह किया कि वे गृह पत्रिकाओं की धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण योगदान करें। कार्यक्रम के आयोजन हेतु यूएलए तथा जेडएलसी के स्टाफ सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। सुश्री जागृति उपाध्याय, सहायक प्रबंधक (रा.भा.) द्वारा मंच संचालन किया गया और श्री एम.एस.ठाकुर, सहायक प्रबंधक (रा.भा.) द्वारा कार्यक्रम का समन्वयन किया गया। श्रीमती गायत्री रवि किरण, संपादक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के बाद कार्यक्रम संपन्न हुआ।





SARFAESI Act:

A Panacea for Recovery

The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002, emerged as a watershed moment in India's financial landscape, conceived to address the burgeoning problem of Non-Performing Assets (NPAs), this legislation empowers banks and financial institutions to recover dues effectively without court intervention. With the Indian banking sector grappling with stressed assets amounting to ₹5.8 lakh crore as of June 2024, the SARFAESI Act has become a vital tool for recovery.

Key Features of the SARFAESI Act:

1. Securitisation of Financial Assets: Banks and financial institutions can sell their non-performing assets (NPAs) to Asset Reconstruction Companies (ARCs). These ARCs then manage and recover the dues.

2. Asset Reconstruction: ARCs are empowered to reconstruct or manage these financial assets, which may include altering the repayment schedule, taking over the management of the borrower's business, or liquidating assets.

3. Enforcement of Security Interest: Banks can directly take possession of secured assets from borrowers who default on loans, after serving a notice period of 60 days.

4. Creation of Security Receipts:

ARCs can issue security receipts to banks or lenders in exchange for the assets acquired. These receipts represent the lenders' stake in the recovery of the dues.

5. Scope of Application: The Act applies only to secured loans where assets are pledged as collateral. Unsecured loans are not covered under SARFAESI Act 2002.

6. Eligible Institutions: Scheduled banks, financial institutions, and certain notified NBFCs (Non-Banking Financial Companies) are allowed to use the provisions of the SARFAESI Act.

Amendments:

Over the years, the Act has been amended to broaden its scope. For instance:

- In 2016, NBFCs with assets over ₹500 crore were permitted to use the Act.
- In 2020, the threshold for NBFCs was reduced to ₹100 crore.

How SARFAESI Act, 2002 Works?

The SARFAESI Act, 2002, provides a structured process for banks and financial institutions to recover loans from defaulting borrowers without court intervention. Here is a step-by-step guide to the detailed process under the Act:

1. Identification of Default : A borrower is classified as a Non-Performing Asset (NPA) when they fail to repay their loan as per the

agreed terms. Under SARFAESI Act 2002, the secured loans (loans backed by collateral) are eligible for recovery action.

2. Issuance of Demand Notice: The lender (bank/financial institution) issues a demand notice to the borrower under Section 13(2) of the SARFAESI Act. Specifying the amount due. It gives the borrower 60 days timeline to repay or raise objections.

3. Borrower's Representation: The borrower has the right to submit a representation or objection to the notice within the 60-day period. The lender is required to consider the objection and provide a reply & If the objection is rejected, the lender proceeds with recovery actions.

4. Possession of Secured Assets: If the borrower fails to repay or comply, the lender can act under Section 13(4): Take possession of the secured asset: This includes physical possession of movable or immovable property. Manage the secured asset: Lenders can lease, sell, or otherwise deal with the asset. Take over the management of the business: Applicable in cases where the collateral includes an entire business.

The lender must publish a notice of possession in newspapers to inform the public.

5. Valuation and Sale of Assets: The lender appoints a valuer to determine the fair market value of the asset. A public notice for auction

is published, detailing:

- The description of the asset.
- Reserve price.
- Auction date, time, and terms.
- Auction Process:

E-auctions are the preferred method to ensure transparency. Bidders register, pay the earnest money deposit, and participate. The highest bid that meets or exceeds the reserve price is accepted.

6. Recovery of Dues: The proceeds from the sale of assets are utilized to recover the outstanding loan amount. Any surplus after recovery is returned to the borrower.

7. Role of Debt Recovery Tribunals (DRTs): If the borrower disputes the recovery process, they can approach the DRT under Section 17 of the Act within 45 days of possession notice. Borrowers must deposit 50% of the dues (subject to DRT discretion) to file an appeal. The DRT adjudicates the matter, and the lender's recovery process is halted during this time.

8. Involvement of Asset Reconstruction Companies (ARCs) : If the lender decides to sell the NPA, the secured asset can be transferred to an ARC. The ARC manages and recovers dues from the borrower using strategies like restructuring, taking over management, or selling the asset.

9. Grievances and Appeals: Borrowers can appeal DRT decisions to the Appellate Tribunal (DRAT) within 30 days. DRAT requires the borrower to deposit 50% of the dues before the appeal is entertained.

10. Concluding Recovery Actions: Once the dues are recovered, the

lender closes the case. If partial recovery is achieved, the lender may explore further legal remedies for the remaining amount.

Summary of Key Timelines under SARFAESI Act, 2002:

60 Days: Borrower's notice period to repay or raise objections.

45 Days: Borrower's timeline to appeal at DRT.

30 Days: Timeline to appeal a DRT decision at DRAT.

Benefits of the SARFAESI Process:

- **Swift Recovery:** No need for lengthy court proceedings.
- **Lender Empowerment:** Financial Institutions such as Banks & NBFCs can enforce their rights effectively.
- **Transparency:** Use of e-auctions ensures fair price discovery.
- **Flexibility:** Allows restructuring or transferring assets to ARCs.

Key Achievements of SARFAESI

- **Efficient Asset Recovery:** SARFAESI has facilitated swift asset recovery for lenders. Data from the Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) suggests that banks recover up to 40% of loan value under SARFAESI, compared to 24-30% under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC).
- **Strengthening Credit Discipline:** The Act has instilled credit discipline among borrowers, as the fear of losing assets discourages defaults.
- **Support to NBFCs:** The 2020 amendment allowed Non-Banking Financial Companies (NBFCs) with

over ₹100 crore in assets to invoke SARFAESI, widening its scope and application.

Way Forward

- **Strengthening DRTs:** Augmenting the capacity of DRTs by appointing more members and adopting digital case management systems can accelerate SARFAESI resolutions.
- **Focus on Unsecured Assets:** Amending the Act to include certain unsecured loans, especially in the MSME sector, can broaden its recovery scope.
- **Enhanced Collaboration:** Greater synergy between banks, ARCs, and NARCL can optimize recoveries. Shared databases and AI-driven analytics can help identify and address stressed assets early.

Conclusion: The SARFAESI Act has fundamentally transformed the financial recovery landscape in India, offering a swift, transparent, and effective mechanism for resolving NPAs. While it is not without its limitations such as overburdened DRTs and borrower resistance it remains a cornerstone in India's battle against bad loans. By empowering lenders, deterring defaults, and ensuring financial discipline, SARFAESI continues to be a powerful and indispensable tool for recovery, earning its reputation as a panacea for India's banking sector.



Dr Ravindra Deshmukh
U.L.A., Bhopal

Data Integrity & Adequacy in Prevention & Recovery of NPAs

We all are well aware that NPAs i.e. Non-performing assets for any bank or financial institution have been a big drain on its financial and non-financial resources. Therefore, it remains the top-most endeavor of every bank and Financial institution to prevent any likelihood of NPAs at the first place and recover the same as soon as possible if the account at all has slipped to NPA category.

Data and its importance for NPA recovery: Banks while considering a credit proposal, as per the laid down guidelines are required to carry out comprehensive due diligence about the borrower, his business or activity for which the banks are to extend finance, environment-present & future within which the business or the activity is to operate and finally the proper assessment of the income generation by the proposed activity with an objective of profit generation for the entrepreneur and income for the bank by way of timely & completely repayments of principal and interest thereon out of profit generated by the entrepreneur.

Therefore, in order to have proper & thorough assessment of the borrower, activity etc, it is utmost important & imperative that the concerned bank officials engaged in the process of lending, gather maximum possible and accurate information about the borrower, his family, KYC details, financial & social dealings, qualifications, hobbies etc- just to name a few. The information gathered provides the credit

officials with the valuable resources to comprehensively assess the risk inherent in a credit proposal and to take prudent credit decision with risk mitigation factors accordingly.

Lapses in important data build up: It has been a common observation that in many accounts adequate, consistent and accurate details are not held on the records, which can be understood from following examples.

Loan Application form: it is observed that the very basic and highly important document i.e. Loan application is held either blank or scantily filled. Sometimes the loan application form is filled in such a way, making it difficult to comprehend the exact detail/s. Signature and photographs of all the applicants/Co-applicants/Guarantors are not held in some accounts. Sometimes, the rubber stamp, in case of non-individual accounts is not affixed upon the signatures and at times, improper rubber stamp is affixed, like Applicant, co-applicant and guarantor - all sign with rubber stamp as proprietor. In some cases, despite the applicant, co-applicant and guarantors having different demographic profiles like residential addresses, mobile no and email IDs, same details of one person are filled for all the applicants and updated in the system, making the task difficult for the subsequent branch incumbents as well as the monitoring officials whenever a need warrants to establish contact with other co-applicants or guarantors.

Confidential Credit information: Similarly, another highly important document, Confidential Credit information is filled partially and/or with vague details. This as we know is the very important document, based on which the credit reports of the applicant/co-applicant and guarantors are prepared, and their means are arrived at which reflect their financial strength and thereby capacity to withstand any adverse situation during the course of business or activity as well as for the sanctioning authority to take credit decision accordingly. However, many a times, in order to show a rosy picture for the applicants, assets like household goods and gold ornaments etc for good amount are shown as means for which there hardly exist any documentary evidence or any other supporting document to substantiate such means. Whereas as per the laid down guidelines of the Bank, it has been mandated that the means reflected in the credit report should be supported by documentary evidence and the same should be held on record. For, once an account turns NPA, the process of recovery also requires to compare the present means with the means available at the initial stage of sanction so as to find out the transition of means and their availability for realisation of dues.

Periodical inspections of securities: Yet another area of concern pertains to the periodical inspection of the securities- Primary as well as Collateral. Bank's policy on

collateral management clearly spells out the periodicity of the inspection of the securities charged to the Bank but there have been various instances wherein the concerned officials either do not undertake the inspections or even if the inspections have been done, details of the same are not updated in the system like in Finacle and through M-6/Q-4 & MCMR reporting. The details of inspection of securities properly & accurately updated not only helps the concerned officials in proper monitoring of the advances but also provides an opportunity to assess the latest position of assets financed by the Bank and its likely impact towards NPA.

Periodical valuation of securities:

Similar to inspection, it is also incumbent upon the branch officials to ensure that the primary/collateral securities charged to the Bank are periodically re-valued as per the applicability and the details of the same are updated in the system. Re-valuation of the securities on one hand provides the concerned officials with the assessment of latest position of the asset for its sufficiency & enforceability to the loan against which it has been held, while on the other hand, it also prevents the concerned loan getting classified as NPA when the revaluation details are updated in the system.

Periodical obtention of DBCs:

Security documents executed by the borrower, acknowledging his debt to the Bank and enforceable in the court of law in the case of recovery proceedings against the borrower, gets time barred as per the application of limitation act. Accordingly, as per the guidelines, it is incumbent upon the concerned branch officials to periodically

obtain acknowledgment of debt in the form of prescribed DBCs (Debit balance confirmation) from the borrower/s as well as the guarantors and updating of the date in the system. The obtention of DBCs on one hand keeps the security documents valid and legally enforceable, if there is no deficiency otherwise but on the other hand also provides the branch officials an opportunity to get an insight of the borrower and guarantor's intentions towards the loan availed as many a times, guarantors specifically have been found expressing their reluctance in owning the liability and this provides the branch official as a warning signal, remediation of which becomes necessary & immediate before the account gains signs of sickness and may warrant the invocation of guarantor's liability.

The above-mentioned areas of concern are just indicative in nature, every endeavour has to be made to keep the loan records, physical as well as in the soft form absolutely sacrosanct. One handling the credit portfolio needs to sincerely realise that every document related to a borrower's credit facility may become redundant upon proper liquidation of the credit facility but the same set of documents act as a saviour to the bank when produced in a court of law for the recovery of bank dues. Hence, it is utmost responsibility of the concerned official to ensure that all the relevant documents related to credit dispensation of a borrower are completely & accurately filled in and the documents are maintained with utmost sanctity.

The finance provided by the banks for credit facilities is also praya dhan as the money being lent does

not belong to the bank but to others.

Many of us at branches while seeking the details from the prospective borrowers as per the fields in the forms to be filled and to assess the overall risk in the credit proposal, at times feel shy & reluctant lest the loan applicant may get annoyed and refuse to take the loan. So, many a times, in order to appear more obliged to the loan applicant, we just get him scribble minimum details & signatures with the aim to make him feel pleasant with our 'prompt services'. But this is also a well experienced fact that any amount of information can be collected from a loan applicant till the loan is sanctioned & disbursed and it becomes too difficult to get any more information or detail once the loan has been disbursed.

Besides, at the time of recovery of overdues in such accounts, the branch officials may have to approach the predecessors with whom the borrower had good liaison. This does occur notwithstanding the fact that we are professional people, working for an organisation, complying with laid down set guidelines. Any lapse in approach may cause more harm than good for the organisation as a whole.

Conclusively, let's not undermine the great importance of data that should be properly obtained and maintained as it is a very crucial for prevention and recovery of NPAs thereby keeping the bank healthier, progressive and prosperous.



Sandeep Gupta
C.B.C., Ahmedabad



Bad Bank and NARCL

Bad banks, formally called Asset Reconstruction Companies (ARC), are specialized financial institutions that purchase the stressed and non-performing assets (NPA) of the bank. It is not involved in lending and taking deposits but helps commercial banks clean up their balance sheets and resolve bad loans. The takeover of bad loans is normally below the book value of the loan and the bank tries to recover as much as possible subsequently. It has often been touted as a magic bullet for reducing NPAs, improving Banks' Balance sheets, unlocking banks' capital, increasing the Credit creation and consequently, a way out of the vicious economic cycle created due to the Twin Balance Sheet (TBS) problem. Bad banks are asset reconstruction companies that buy, manage, and recover bad loans and manage NPAs from commercial banks to liquidate the transferred assets. It provides a

safety net for banks, allowing them to offload bad loans and focus on healthier lending activities.

Asset Resolution

The Economic Survey 2016-17 had recommended setting up Centralised Public Sector Asset Rehabilitation Agency (PARA) as Bad Bank to address the growing problem of NPAs. The budget 2021 proposed an Asset Reconstruction Company (ARC)-Asset Management Company (AMC) structure, wherein the ARC will aggregate the debt, while the AMC will act as a resolution manager.

NARCL has been set up with a strategic initiative to clean up the legacy stressed assets with an exposure of Rs 500 crore and above in the Indian Banking system. NARCL will offer adaptable acquisition structures comprising of an optimal mix of

Cash and Security Receipts (SRs) to the Selling Banks and Financial Institutions, across sectors and geographies. NARCL's acquisition processes will be administered by their Financial Asset Acquisition Policy framed under the extant guidelines for Asset Reconstruction Companies. NARCL's investment strategy focuses on aggregating the stressed assets under one roof to ensure efficient resolution of such assets.

NARCL's offer shall have a notable feature where the SRs issued by NARCL for acquiring stressed loan assets will be backed by guarantee from the Government of India. The Guarantee shall provide NARCL a unique strategic advantage, thereby enabling easier aggregation, which is very important for value preservation and driving any resolution process.

NARCL shall have an exclusive

arrangement with IDRCL (India Debt Resolution Company Ltd) wherein IDRCL shall provide end-to-end assistance to NARCL for the optimal resolution outcome for acquired assets. This shall include determination of appropriate resolution strategy as per the RBI framework, Corporate Insolvency Resolution Process proceedings under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, Enforcement of security / liquidation, sale of assets / slump sale, sale to Stressed Funds, Alternate Investment Funds, Strategic Investors etc.

Need for Bad Bank in India:

- ♦ **Rising NPA:** The K.V. Kamath Committee noted that corporate sector debt worth ₹15.52 lakh crore has come under stress after COVID-19 hit India, while another ₹22.20 lakh crore was already under stress before the pandemic. This staggering number of NPAs has led to the Twin Balance Sheet Problem in India.
- ♦ **Quicker resolution:** The aggregation of bad assets at one place will make it easy for the buyer to deal with one unified ARC rather than dealing with multiple lenders, improving the chances of resolution.
- ♦ **Financial Stability:** Government backing of bad banks can enhance confidence in the originating banks, thereby improving their overall capital buffers and financial stability.
- ♦ **Economic Recovery:** Due to COVID 19 pandemic hitting the banking sector, RBI feared a spike in bad loans in the wake of a six-month moratorium it has announced to tackle the economic

slowdown.

- ♦ **Government Support:** Such institutions funded by the private market lenders and backed by the support of the government, it can be an effective mechanism to deal with Non-Performing Assets (NPAs). The presence of the government is visualised as a means to speed up the clean-up process.

- ♦ **International Precedents:** Many other countries have already set up institutional mechanisms to deal with a problem of stress in the financial system.

- ♦ **Multiplier impact:** With the existing undercapitalized ARCs reluctant to take up NPAs, the New Bad Bank aims to fill this void, entailing several economy wide benefits such as improved banks' liquidity, free up management bandwidth to focus on core business etc.

- ♦ It will accelerate bank's recovery and enhance lending to productive sectors to 'jump start' economy & employment.

- ♦ Bad banks centralize the management of NPAs, which can streamline efforts and increase efficiency in asset resolution.

- ♦ By transferring NPAs to a bad bank, originating banks can free up capital currently held as provisions against these assets. This can potentially lead to an increase in lending to more creditworthy customers.

Advantages of Bad Bank:

- ♦ From a governmental and regulatory perspective, a bad bank is a useful tool to clean up excessive NPA volumes, thereby

reducing systemic risk in the economy and avoiding the need for the government to step in and potentially recapitalize banks, ultimately at the cost of the taxpayer.

- ♦ It frees up resources for fresh origination and reduces the need to hold capital against risk weighted assets.

- ♦ Improvement in the balance sheet of the Banks due to decrease in the level of NPAs.

- ♦ Unlocking of the capital that was earlier locked up as provisioning requirements. This would lead to increase in the credit creation.

Enable the Bank to focus on their core areas of accepting deposits and lending loans.

- ♦ Address the problem of coordination and delays in the recovery of NPAs by multiple Banks.

✓The operation of NARCL in the NPA market has increased the competitiveness of pricing offered by other private asset reconstruction companies in India.

Current Challenges for Bad Banks:

- ♦ **Dual Structure Issues:** The duality of NARCL and IDRCL has led to operational inefficiencies. NARCL retains decision-making authority, but IDRCL handles resolution, creating a complex and costly structure.

- ♦ **Pricing Discrepancies:** Significant differences in pricing expectations between NARCL and banks have deterred transactions, as banks find NARCL's offers inadequate.

♦ **High Operational Costs:** The need for both NARCL and IDRCL has resulted in higher operational costs, which are exacerbated by NARCL's reliance on external consultants and a slower due diligence process.

♦ **Price Discovery:** Bad banks often face difficulties in pricing bad loans and determining future liabilities.

♦ **Finding Buyers:** Selling portfolios of distressed assets can be challenging, especially without established market mechanisms or precedents.

♦ Weak economic conditions can further depress asset values and reduce the pool of potential buyers.

Potential Solutions for NARCL's Challenges:

♦ Combining IDRCL and NARCL could streamline operations, reduce costs, and enhance efficiency by eliminating duplicative functions.

♦ Implementing performance-linked incentives could attract skilled professionals and improve the effectiveness of asset resolution.

♦ Investor-friendly policies to facilitate domestic and foreign investor participation in asset resolution.

♦ Foster a secondary market for distressed assets to improve liquidity and price discovery.

The RBI allowed banks to use Swiss Challenge technique for the selling of NPA accounts in September 2016. The Swiss challenge method is a public procurement process that allows private companies to bid on government contracts.

Conclusion: The long-term prospect of India building a vibrant secondary market in asset sales is certainly still possible. India has vast potential and large volumes of bad debt. Government policy is clearly committed towards cleaning up these distressed assets. Whilst NARCL's infancy has been perhaps more eventful than expected, it is not surprising that some variations are required over time in terms of leadership, procedures or pricing strategy.

The Bad Bank is a significant step towards addressing the long-standing problem of NPAs. While challenges remain, its successful implementation can have a positive impact on the overall health of the banking system and the economy. The government's continued support and the ability to overcome hurdles will be key to their success. Establishing a bad bank can help reduce NPAs and strengthen the banking sector, but public sector banks need comprehensive governance and lending reforms. A bad bank and other measures can reduce NPAs and ensure a resilient banking system that supports economic growth. It's a challenge that requires a response on multiple fronts. A bad bank cannot be the sole response. The most efficient approach would be to design solutions tailor-made for different parts of India's bad loan problem and use Bad Bank only as a last resort once all other methods fail.

Archana
R. O., Jaipur



A beautiful life, a secret life

In quiet moments, find your bliss,
A secret garden, a hidden kiss.
Live happily, your heart at ease,
Share joy within, but keep it. please.

A true love story, pure and deep,
A treasure to cherish, a secret to keep.
Let love blossom, in silent grace,
A sanctuary of peace, a sacred space.

If travelling, explore the unknown,
A journey of self, a path alone.
Share your adventures, when you return,
But keep the magic, where it first did burn.

Your eyes, a mirror to my soul,
Where love's reflection makes me whole.
In my heart, a flame you ignite,
A passion burning ever bright.

People ruin, what's pure and bright,
so, guard your secrets, with all you might.
Live happily, love deeply, free from strife,
A beautiful life, a secret life.

Padma
Kurthaur Branch,
R.O., Patna



शीर्षक लिखें

क्या यह तस्वीर आपके मन में किसी पुरानी याद, किसी गहन भावना या सृजनात्मकता अंकुरित कर रही है? हर तस्वीर एक दास्तां बयां करती है. तथापि, यदि आप अपने भावों को शीर्षक के रूप में व्यक्त करना चाहें तो तुरंत अपनी कलम का जादू दिखाते हुए इस चित्र के लिए 06 शब्द का एक शीर्षक लिखें और अपने कार्यालय/क्षेत्र के संवाददाता के माध्यम से हमें प्रेषित करें.

अपनी प्रविष्टि भेजते समय निम्नलिखित का ज़रूर ध्यान रखें:

- शीर्षक अधिकतम 06 शब्द की ही हो.
- प्रविष्टि हिंदी या अंग्रेजी में भेजी जा सकती है. परिपत्र सं. 8303-2024 दि: 12.06.2024 के अनुसार दोनों श्रेणियों में अलग-अलग पुरस्कार दिए जाएंगे.
- एक स्टाफ सदस्य एक ही प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकते हैं, या तो हिंदी या अंग्रेजी में.
- प्रतियोगिता केवल बैंक के सेवारत कार्मिकों के लिए ही है.
- सभी संवाददाता से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र से प्राप्त प्रविष्टियों को भाषावार सारणी में समेकित कर अंतिम तिथि तक uniondhara@unionbankofindia.bank पर प्रेषित करें. सारणी में प्रविष्टि के साथ स्टाफ का नाम, पदनाम, शाखा/कार्यालय का नाम, सोल आईडी की सूचना अवश्य दें.
- प्रविष्टियां भेजने कि अंतिम तिथि 05 अप्रैल, 2025 है.
- शब्द संख्या का ध्यान रखते हुए अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रविष्टियों को ही प्रतियोगिता में सम्मिलित किया जाएगा.

Coin a Caption

Is this picture evoking some old memory, some deep emotion or sparking creativity? Every picture is worth a thousand words, however if you want to express your feelings in a few words, then let your pen create magic. Write a caption of 06 words on this picture and send it to us through the correspondent of your office/Region.

Please ensure the following while submitting your entry:

- caption should be of maximum 06 words only.
- The entry may be sent in Hindi or English. In terms of circular no. 8303-2024 dt. 12.06.2024 separate prizes shall be awarded under each language category.
- A staff member may submit only one entry, either in Hindi or in English.
- This contest is open only for the staff members presently in service of the Bank.
- All correspondents are requested to consolidate the entries of their Region, language wise, in a tabular form, by the last date and send them to uniondhara@unionbankofindia.bank. Invariably give details of Staff name, designation, branch/Office name, SOL ID along with the entries.
- The last date for sending entries is 05th April, 2025.
- Entries, duly, adhering to the specified word limit, received by the last date, shall only be included in the competition.

यूनियन धारा प्रतियोगिता क्रमांक 171 - 'ट्वीट लिखें'

पुरस्कार	हिंदी श्रेणी
प्रथम	श्री अंशुल जैन, सयाजीगंज शाखा, क्षे.का., बड़ौदा
द्वितीय	श्री अभिनय कुमार, एन.पी.सी., पटना
तृतीय	सुश्री अन्न उरांव, एमएलपी, भुवनेश्वर
प्रोत्साहन	श्री नितेश कुमार, समता कॉलोनी शाखा, क्षे.का., रायपुर
पुरस्कार	अंग्रेजी श्रेणी
प्रथम	सुश्री ऋचा जैन, निजामपुरा शाखा, क्षे.का. बड़ौदा
द्वितीय	श्री सचिन वर्मा, डीआईटी, पवई
तृतीय	श्री रजत कुमार, क्षे.का., सिकंदराबाद
प्रोत्साहन	श्री विकास तिवारी, अं.का., पुणे

फोटो - गायत्री दाणी
क्षे.का., पंजागुट्टा-हैदराबाद



उद्घाटन



दिनांक 09.11.2024 को बेंगलूरु में आयोजित राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों को ऋण वितरण करते हुए माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन तथा सुश्री ए. मणिमेल्लै, एमडी एवं सीईओ. इस कार्यक्रम के दौरान माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा यूनियन बैंक की पांच नारी शक्ति शाखाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया.



दिनांक 09.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, चंदौली के सकलडीहा शाखा का उद्घाटन चंदौली जनपद के जिलाधिकारी श्री निखिल टी. फुंडे जी के द्वारा किया गया. इस अवसर पर श्री धीरेन्द्र जैन, अंचल प्रमुख तथा श्री संजीव कुमार, क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य कार्यपालकगण उपस्थित रहे.



दिनांक 25.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, राजमंडी के केशवदासपालेम शाखा के नए परिसर का उद्घाटन श्री वी सत्यनारायण, सहायक आयुक्त एवं कार्यकारी अधिकारी, श्री लक्ष्मी नरसिंह स्वामी देवस्थानम, अंतर्वेदी द्वारा किया गया. साथ हैं श्री ए. विश्वेश्वर राव, क्षेत्र प्रमुख.



दिनांक 09.11.2024 को अंचल कार्यालय, विशाखपट्टणम में नारी शक्ति शाखा का उद्घाटन श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक के द्वारा किया गया. इस अवसर पर स्वागत करते हुए श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख सहित अन्य महिला स्टाफ.



दिनांक 12.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के नौबतपुर शाखा के नए परिसर का उद्घाटन श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक द्वारा किया गया. इस अवसर पर श्री बैजनाथ सिंह, अंचल प्रमुख उपस्थित रहे.



दिनांक 19.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, चंदौली के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक द्वारा किया गया. इस अवसर पर श्री धीरेन्द्र जैन, अंचल प्रमुख तथा श्री संजीव कुमार, क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य कार्यपालकगण उपस्थित रहे.



दिनांक 14.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, अयोध्या के रामपथ, अयोध्या शाखा का उद्घाटन श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक द्वारा किया गया। साथ हैं श्री राजेश कुमार, अंचल प्रमुख, लखनऊ, श्री प्यारे लाल, उप अंचल प्रमुख, लखनऊ, श्री हिमांशु मिश्रा, क्षेत्र प्रमुख, अयोध्या, श्री मनीष श्रीवास्तव, सहायक महाप्रबंधक, अंचल कार्यालय, श्री विनोद कुमार रजक, मुख्य प्रबंधक, अयोध्या।



दिनांक 27.11.2024 को अंचलीय ज्ञानार्जन केंद्र, गुरुग्राम के कॉर्पोरेट एवं ट्रेजरी तथा स्ट्रेटेजी एवं फाइनेंस के नए संकाय कमरे का उद्घाटन डॉ चेतना पाण्डेय, महाप्रबंधक, ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री मनोज कुमार, अंचल प्रमुख, चंडीगढ़, श्री विट्ठल बनशंकर, महाप्रबंधक, श्री नीरज सिंह, उप महाप्रबंधक, श्री सचिन गुप्ता, केंद्र प्रभारी एवं यूएलए प्रमुख तथा श्री सतीश कुमार पाठक, प्रमुख, जेड. एल.सी, गुरुग्राम उपस्थित रहे।



दिनांक 17.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में भोजीपुरा शाखा का उद्घाटन श्री राजेश कुमार, अंचल प्रमुख, लखनऊ तथा श्री देव मूर्ति, चेयरमैन, श्री राम मूर्ति स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री बृजेश कुमार तिवारी, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री गौरव सिंह, शाखा प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।



दिनांक 25.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, खम्मम के सूर्यपेट शाखा के नए परिसर का उद्घाटन श्री मीला महादेव, चेयरमैन, सुधाकर ग्रुप द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री ए हन्मंत रेड्डी, क्षेत्र प्रमुख, श्री सर्वेश तेजावत, उप क्षेत्र प्रमुख, श्री एन सुधाकर राव, शाखा प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।



दिनांक 11.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर के गोता, गांधीनगर में बैंक की नई शाखा का उद्घाटन श्री अखिलेश कुमार, अंचल प्रमुख द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री संतोष साहू, क्षेत्र प्रमुख, गांधीनगर तथा श्री तुषारकान्त, क्षेत्र प्रमुख, अहमदाबाद सहित अन्य कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।



दिनांक 17.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बरेली में विजय लक्ष्मी मार्ग शाखा के नवीन परिसर का उद्घाटन श्री राजेश कुमार, अंचल प्रमुख, लखनऊ तथा श्री बृजेश कुमार तिवारी, क्षेत्र प्रमुख, बरेली द्वारा किया गया।

उद्घाटन



दिनांक 21.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, करनाल के नए परिसर का उद्घाटन श्री मनोज कुमार, अंचल प्रमुख, चंडीगढ़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री परमजीत सिंह, क्षेत्र प्रमुख, करनाल, श्री अमर शर्मा तथा श्री जितेंद्र शर्मा, उप क्षेत्र प्रमुख, चंडीगढ़ उपस्थित रहे।



दिनांक 11.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के अर्बन स्टेट शाखा का उद्घाटन श्री मनोज कुमार, अंचल प्रमुख, चंडीगढ़ द्वारा किया गया। साथ हैं श्री गुरदीप सिंह, क्षेत्र प्रमुख, जालंधर।



दिनांक 20.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बठिंडा के एमएलपी एवं आरएलपी के नए परिसर का उद्घाटन श्री मनोज कुमार, अंचल प्रमुख, चंडीगढ़ द्वारा किया गया। इस अवसर पर श्री आशीष सुवालका, क्षेत्र प्रमुख, बठिंडा सहित अन्य कार्यपालकगण तथा स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।



दिनांक 28.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर कोलकाता के बसिरहाट शाखा के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन करते हुए श्री लोकनाथ साहू, अंचल प्रमुख, कोलकाता, श्रीमती प्रतिभा पाण्डेय, क्षेत्र प्रमुख, ग्रेटर कोलकाता, श्री टंकेश्वर खां तथा श्री मनीर अंसारी, उप क्षेत्र प्रमुख।



दिनांक 28.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, विजयनगरम के अंतर्गत चितलवलसा शाखा का उद्घाटन श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख, विशाखपट्टणम द्वारा किया गया। साथ हैं श्री पी. नरेश, क्षेत्र प्रमुख, विजयनगरम।



दिनांक 05.12.2024 क्षेत्रीय कार्यालय, तृशूर में अय्यंथोले शाखा के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्ज्वलन करते हुए श्रीमती रेणु के नायर, अंचल प्रमुख, मंगलूरु। साथ हैं श्री सतीश कुमार एम, क्षेत्र प्रमुख, तृशूर, श्रीमती प्रीति रामचंद्रन तथा श्री कृष्णादास ए., उप क्षेत्र प्रमुख और अन्य स्टाफ सदस्य।

समय प्रबंधन: सफलता का मूलमंत्र

समय प्रबंधन का अर्थ है समय का सही और प्रभावी उपयोग करना ताकि सभी कार्य समय से किए जा सकें। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता सुनिश्चित करने में मदद करता है। समय प्रबंधन के तहत प्राथमिकताओं को तय करना, कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करना, और उपलब्ध समय का अधिकतम उपयोग करना शामिल है। यह हमें अनावश्यक तनाव से बचाने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। समय प्रबंधन से हम अपने काम, परिवार और व्यक्तिगत जरूरतों के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनते हैं।

इसके लिए योजनाबद्ध ढंग से कार्य करना आवश्यक है। जैसे कि दैनिक, साप्ताहिक या मासिक कार्यों की सूची बनाना, समय सीमा तय करना, और समय व्यर्थ करने वाले कार्यों से बचना। इसके अलावा, मल्टीटास्किंग से बचते हुए एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करना भी समय प्रबंधन का हिस्सा है।

समय प्रबंधन न केवल हमें काम के प्रति अनुशासित बनाता है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। यह सफलता और संतुलित जीवन की कुंजी है। प्रसिद्ध प्रबंधन विशेषज्ञ पीटर एफ. ड्रुकर ने कहा है, "Time is the scarcest resource; and unless it is managed, nothing else can be managed." अर्थात् समय सबसे दुर्लभ संसाधन है, और यदि इसे प्रबंधित नहीं किया गया, तो अन्य किसी भी चीज का प्रबंधन संभव नहीं है।

समय प्रबंधन के फायदे:

1. उत्पादकता में वृद्धि: समय का सही उपयोग करने से कम समय में अधिक काम पूरे किए जा सकते हैं।

2. तनाव में कमी: व्यवस्थित तरीके से काम करने से समय की कमी का तनाव नहीं होता।

3. कार्य में गुणवत्ता: समय पर कार्य पूरा करने से काम की गुणवत्ता बेहतर होती है एवं निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलती है।

4. जीवन में संतुलन: समय प्रबंधन से कार्य, परिवार और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आसान होता है।

5. सफलता की ओर कदम: समय का सही उपयोग व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है।

6. निर्णय लेने की क्षमता में सुधार: समय प्रबंधन से प्राथमिकताएं तय करना और बेहतर निर्णय लेना आसान होता है।

7. स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव: तनाव कम होने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

8. समय की बर्बादी से बचाव: अनावश्यक कार्यों पर समय बर्बाद नहीं होता, जिससे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

9. आत्मविश्वास में वृद्धि: समय पर कार्य पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है।

10. दीर्घकालिक सफलता: समय प्रबंधन आदतों से जीवन में दीर्घकालिक लाभ और सफलता प्राप्त होती है।

पीटर ड्रुकर कहते हैं, "Efficiency is doing things right; effectiveness is doing the right things." समय प्रबंधन के माध्यम से आप न केवल चीजें सही तरीके से करेंगे, बल्कि सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

कुशल समय प्रबंधन उत्पादकता बढ़ाता है, काम की गुणवत्ता सुधारता है और आवश्यक तनाव कम करने में मदद करता है।

समय प्रबंधन में बाधाएं

1. स्पष्ट लक्ष्य का अभाव: बिना स्पष्ट लक्ष्य के व्यक्ति अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग नहीं कर पाता।

2. प्राथमिकताओं की अनदेखी: प्राथमिकताओं को तय न करना समय की बर्बादी का बड़ा कारण है।

3. स्थगित करने/लंबित रखने : काम को बार-बार टालने से न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि तनाव भी बढ़ता है।

4. अनियोजित दिनचर्या: बिना योजना के दिनचर्या अपनाने से महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे नहीं हो पाते।

5. डिजिटल विकर्षण: सोशल मीडिया, मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म ध्यान भंग करते हैं और समय की बर्बादी का कारण बनते हैं।

6. मल्टीटास्किंग की प्रवृत्ति: एक समय में कई कार्य करने की कोशिश से न तो कोई काम सही ढंग से होता है और न ही समय का सदुपयोग।

7. अनुशासन की कमी: समय प्रबंधन के लिए अनुशासन जरूरी है, जिसकी कमी बाधा बनती है।

8. अनपेक्षित रुकावटें: अचानक आने वाले कार्य, कॉल या आपात स्थितियां समय प्रबंधन को प्रभावित करती हैं।

9. अतिरिक्त कार्यभार: क्षमता से अधिक काम लेने पर समय प्रबंधन मुश्किल हो जाता है।

10. थकान और मानसिक तनाव: शारीरिक और मानसिक थकान से कार्य क्षमता और समय प्रबंधन पर नकारात्मक असर पड़ता है।

समय प्रबंधन की इन बाधाओं को पहचानकर उन्हें दूर करना सफलता की दिशा में पहला कदम है।

समय प्रबंधन मैट्रिक्स: समय प्रबंधन मैट्रिक्स, एक प्रभावी उपकरण है जो समय को प्राथमिकता देने और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। इसे चार खंडों में विभाजित किया गया है, जो कार्यों की तात्कालिकता और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। स्टीफन कोवी द्वारा इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है।

1. महत्वपूर्ण और तात्कालिक (करें) : यह खंड उन कार्यों को दर्शाता है जो तुरंत किए जाने चाहिए, जैसे संकट या डेडलाइन वाले कार्य।

2. महत्वपूर्ण लेकिन गैर-तात्कालिक (योजना बनाएं) : यहां वे कार्य आते हैं जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं, लेकिन तुरंत नहीं करने पड़ते। इन्हें योजना बनाकर समय पर पूरा करना चाहिए।

3. गैर-महत्वपूर्ण लेकिन तात्कालिक (प्रत्यायोजित करें) : ऐसे कार्य जिन्हें किया जाना जरूरी लगता है लेकिन उन्हें दूसरों को सौंपा जा सकता है।

4. गैर-महत्वपूर्ण और गैर-तात्कालिक (हटाएं) : यह खंड उन गतिविधियों को दर्शाता है जो समय बर्बाद करती हैं, जैसे सोशल मीडिया पर समय बिताना।

इस मैट्रिक्स का उपयोग कर हम अपने कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं और अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं।

समय प्रबंधन और टाइम वेस्टर : समय प्रबंधन एक ऐसी कला है जो हमारी दिनचर्या को प्रभावी और उत्पादक बनाती है। यह न केवल हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित करता है, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं को भी स्पष्ट करता है। लेकिन समय प्रबंधन में सबसे बड़ी चुनौती टाइम वेस्टर (समय बर्बाद करने वाले तत्व) होते हैं।

टाइम वेस्टर वे गतिविधियां, आदतें या परिस्थितियां हैं, जो हमारे कीमती समय को अनावश्यक रूप से बर्बाद करती हैं। इनमें सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, अनियोजित बैठकें, लंबित रखने की आदत और लक्ष्यहीन बातचीत शामिल हैं। इनकी वजह से न केवल हमारा समय खराब होता है, बल्कि

कार्यों की गुणवत्ता और हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।

समय प्रबंधन में इन टाइम वेस्टर्स से बचने के लिए जागरूकता और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सबसे पहले, हमें अपने दिन का एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए, जिसमें प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाए। टेक्नोलॉजी का उपयोग सीमित करें और समय-समय पर अपने कार्यों की समीक्षा करें। इसके अलावा, काम के दौरान अनावश्यक रुकावटों से बचने के लिए 'डू नॉट डिस्टर्ब' मोड का उपयोग करें।

टाइम वेस्टर से बचने का सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और समय की अहमियत को समझें। यदि हम हर मिनट का सही उपयोग करना सीख लें, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन और सफलता को भी महसूस करेंगे। समय एक ऐसा संसाधन है जिसे एक बार खो देने पर वापस पाना संभव नहीं है। इसलिए, इसे संरक्षित और सही दिशा में निवेश करना ही बुद्धिमानी है।

पीटर ड्रकर ने कहा है, "Until we can manage time, we can manage nothing else." इसलिए, समय बर्बाद करने वाले कारकों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना अनिवार्य है।

समय प्रबंधन और टाइम सेवर : समय प्रबंधन जीवन की वह कला है जो हमें सीमित समय में अधिकतम उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करती है। इसे प्रभावी बनाने के लिए "टाइम सेवर" (समय बचाने वाले उपाय) का उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम सेवर वे तकनीकें, उपकरण और आदतें हैं जो हमारे कार्यों को तेज़ और अधिक कुशल बनाती हैं।

टाइम सेवर का पहला नियम है प्राथमिकताओं को समझना। जब हम अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण और तात्कालिक कार्यों को पहले स्थान देते हैं, तो समय की बर्बादी से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, 'टू-डू लिस्ट' बनाना और उसे प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करना एक प्रभावी टाइम सेवर है।

दूसरा, तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग

करना। जैसे कैलेंडर, रिमाइंडर, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप्स का इस्तेमाल समय बचाने में मदद करता है। ये न केवल कार्यों को व्यवस्थित रखते हैं, बल्कि समय पर उन्हें पूरा करने में भी मददगार होते हैं।

तीसरा, मल्टीटास्किंग से बचें और एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। यह कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ समय की बर्बादी को भी रोकता है। ईमेल और सोशल मीडिया चेक करने के लिए निर्धारित समय तय करना भी समय बचाने का एक प्रभावी उपाय है।

इसके अलावा, "80/20 नियम" का पालन करें, जिसमें 20% प्रयासों से 80% परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। गैर-जरूरी कार्यों और आदतों को खत्म करके अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं।

टाइम सेवर का सबसे बड़ा मंत्र है अनुशासन। समय की बचत तभी संभव है जब हम अपने तय लक्ष्यों के प्रति ईमानदार और अनुशासित रहें। समय एक अमूल्य संसाधन है, और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करना ही सच्चे समय प्रबंधन की पहचान है।

समय प्रबंधन और टाइम स्टीलर : समय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य हमारे समय का सही और उत्पादक उपयोग करना है। लेकिन इसे सफल बनाने में सबसे बड़ी बाधा "टाइम स्टीलर" (समय चुराने वाले तत्व) होते हैं। टाइम स्टीलर वे गतिविधियां, आदतें और स्थितियां हैं जो हमारी अनदेखी में हमारे कीमती समय को चुरा लेती हैं।

टाइम स्टीलर का सबसे बड़ा उदाहरण है बिना योजना बनाए काम करना। जब हम अपने दिन के कार्यों को बिना किसी प्राथमिकता के पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर जरूरी कार्य पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा, सोशल मीडिया, बार-बार ईमेल चेक करना, और अनावश्यक बातचीत भी समय चुराने वाले सामान्य कारण हैं।

टाइम स्टीलर को पहचानना और उनसे बचना समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले, हमें अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हमारा समय

किन कार्यों में बर्बाद हो रहा है। इसके बाद, हमें उन गतिविधियों को खत्म करने या कम करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे लक्ष्यों में बाधा डालती हैं।

इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अपने कार्यों की योजना पहले से बनाएं और एक समय-सारिणी बनाएं। काम के दौरान रुकावटों से बचने के लिए 'फोकस मोड' का इस्तेमाल करें। साथ ही, तकनीकी उपकरणों का सही उपयोग करके समय चुराने वाले तत्वों को नियंत्रित किया जा सकता है।

टाइम स्टीलर से निपटने के लिए अनुशासन और आत्म-नियंत्रण सबसे प्रभावी उपाय हैं। यदि हम अपने समय का मूल्य समझें और इसे सटीकता से प्रबंधित करें, तो न केवल हमारी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि हम अपनी निजी और पेशेवर सफलता की ओर भी तेजी से बढ़ेंगे। समय को चुराने वालों से बचकर ही हम इसे सच्चे अर्थों में उपयोग कर सकते हैं।

समय प्रबंधन: सफलता की कुंजी : समय प्रबंधन एक ऐसी कला है, जो न केवल हमारी उत्पादकता को बढ़ाती है, बल्कि जीवन को संतुलित और सुखद बनाती है। यह हमारी प्राथमिकताओं को सही ढंग से समझने और उपलब्ध समय का सर्वोत्तम उपयोग करने में मदद करता है। यहाँ समय प्रबंधन बढ़ाने के मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

1. लक्ष्य निर्धारण: स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य तय करें। दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। इससे आपके कार्यों को दिशा और उद्देश्य मिलेगा।

2. प्राथमिकता तय करना: अपने कार्यों को महत्व के अनुसार क्रमबद्ध करें। "महत्वपूर्ण और तात्कालिक" कार्यों को पहले करें। कम जरूरी कामों को बाद में रखें।

3. समय सीमा तय करें: हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा तय करें। इससे आप अनावश्यक विलंब से बच सकेंगे और समय का सही उपयोग कर सकेंगे।

4. योजना बनाएं: प्रतिदिन की शुरुआत में दिनभर के कार्यों की सूची (To-Do List) बनाएं। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल करें।

5. ध्यान भंग करने वाले तत्वों से बचें: मोबाइल, सोशल मीडिया, और अन्य ध्यान भटकाने वाले तत्वों से बचें। कार्य के समय केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें।

6. ब्रेक लेना: लगातार काम करने से मानसिक और शारीरिक थकान हो सकती है। नियमित ब्रेक लें, ताकि आप ऊर्जावान बने रहें।

7. "न" कहना सीखें: हर कार्य को स्वीकार करना समय प्रबंधन में बाधा बन सकता है। केवल उन्हीं कार्यों को स्वीकारें, जो आपकी प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

8. आत्म-विश्लेषण करें: समय-समय पर अपने समय प्रबंधन की समीक्षा करें। जो गलतियां हो रही हैं, उन्हें सुधारें।

पीटर ड्रकर का मानना है, "The best way to predict the future is to create it." समय प्रबंधन के द्वारा आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं।

निष्कर्ष: समय प्रबंधन एक कला है, जिसे अभ्यास और अनुशासन से सीखा जा सकता है। यह न केवल आपको उत्पादक बनाता है, बल्कि आपके जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। समय प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है, जो अनुशासन, जागरूकता और निरंतर अभ्यास से बेहतर होती है। इसे अपनाकर आप न केवल अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि जीवन को संतुलित और खुशहाल भी बना सकते हैं। अंततः, समय प्रबंधन न केवल आपके काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, बल्कि आपको अपने जीवन में शांति और संतुष्टि का अनुभव भी कराता है।

समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न गंवाएं!

संजय कुमार सिन्हा
क्षेत्र प्रमुख, गाजीपुर



एनपीए : एक छिपा हुआ दर्द

जब कर्ज के सपने बोए जाते,
विकास की राहें खोले जाते।
हर आशा के पंख लगाए,
भविष्य सुनहरे पल दिखाए।

पर वक्त की आँधी जब चलती,
सपनों की नौका पल में ढहती।
वादा जो था, निभा न पाए,
एनपीए के साए में छिप जाए।

कर्ज था उम्मीदों का आधार,
बने अब यह बैंक का भार।
चमकते खातों के पत्रों में,
एक काला दाग बन जाए।

फसलों का संग, बिजनेस का खेल,
कभी न लौटे, बन जाए झमेल।
बैंक की बैलेंस शीट को रोता छोड़े,
हर नई योजना का सपना तोड़े।

पर क्या यह केवल उधारियों का दोष?
या तंत्र में भी कहीं है खोखलापन और रोष?
सतर्कता, प्रबंधन का हो अभाव,
तो एनपीए के घाव फिर कौन मिटाए?

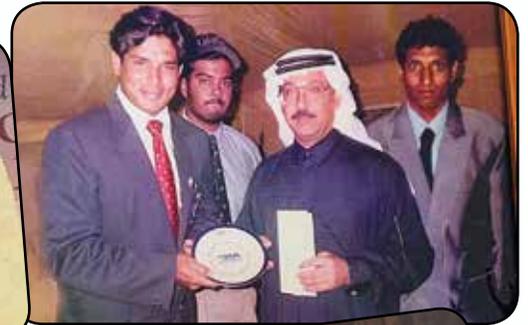
समाधान की राहें तलाशनी होंगी,
ईमानदारी की नींव जमानी होगी।
पुनर्संरचना से संजीवनी लाना,
कर्जदार को सही मार्ग दिखाना।

बैंकों का यह दर्द हल्का हो,
एनपीए का साया फीका हो।
आर्थिक विकास की लौ जलाएँ
नई उम्मीद फिए से लाएँ

मोहम्मद रिज़वान आलम
क्षे. का., भुवनेश्वर



सेलिंग चैंपियन - अनिरुद्ध



आपने सेलिंग कब से शुरू की?

मैंने सेलिंग की शुरुआत 1979 में की थी. 10 वर्ष की आयु में पहली बार खड़कवासला लेक में मैंने सेलिंग की थी. जब मैं 11 वर्ष का था मैंने हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता पहली बार जीती थी. सेलिंग में मुख्य रूप से दो वर्गों में प्रतियोगिता होती है. नाव विथ जूनियर कैटगरी और नाव विथ सीनियर वर्ग में सेलिंग की स्पर्धा होती है. जूनियर कैटगरी में मैंने तीन राष्ट्रीय जीते हैं. 1986 में सिओल एशियन गेम्स में मैंने इसी वर्ग में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया था.

आपने सेलिंग को ही क्यों चुना?

हमारे देश में सेलिंग बहुत ज्यादा प्रचलित खेल नहीं रहा है. इसके पीछे कारण यह है कि नौका विद्या को छत्रपति शिवाजी महाराज के अतिरिक्त और किसी शासक ने उतना प्रश्रय नहीं दिया. ब्रिटिश जब भारत आए तो वे अपने साथ सेलिंग भी लाए. ब्रिटिश युग में भारत भर में अनेक सेलिंग क्लबों की स्थापना हुई. जब ब्रिटिश भारत छोड़कर चले गए तो इस खेल

को भारतीय सेनाओं ने अपनाया. चूंकि मेरे पिताजी एयरफोर्स में पायलट थे इसलिए मुझे नाव पर चढ़ने का अवसर मिला. मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं काफी कम आयु में अच्छे परिणाम लेकर आया.

आपने प्रारंभ में किन-किन प्रतियोगिताओं में भाग लिया और इसका आगे चलकर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा?

मैंने अब तक सात बार राष्ट्रीय पदक जीता है. दो बार एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और तीन बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया है. खेल यह सिखाता है कि जीत या हार में मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें. खेल में भाग लेनेवाले बच्चे बड़े होकर सकारात्मक और धैर्यशाली होते हैं. जहां तक सेलिंग का प्रश्न है, इस खेल के लिए मुंबई में काफी सुविधाएं हैं. हैदराबाद भी सेलिंग के मामले में प्रसिद्ध है. जब मैं युवा अवस्था में था तो बैंक में भर्ती हुआ. मैं ई-आन्ध्रा बैंक में लिपिक के रूप में शामिल हुआ था. जब मैंने एशियन गेम्स में भाग लिया तो मुझे अधिकारी के पद पर

पदोन्नति मिली. इसके उपरांत जब मैं तीसरी बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया तो प्रबंधक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर बैंक ने मुझे प्रोत्साहित किया. बैंक ने मुझे अपने खेल को जारी रखने में काफी प्रोत्साहित किया. सेलिंग का खेल आम जनता में बहुप्रचलित नहीं होने के बावजूद मुझे बैंक ने इस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

कृपया सेलिंग के बारे में हमारे पाठकों को बताएं

सेलिंग का खेल हवा से चलनेवाला खेल है. नाव में बड़े-बड़े परदे लगते हैं. एक खिलाड़ी से लेकर 20 खिलाड़ियों तक की प्रतिभागिता होती है. खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर नाव का आकार होता है. हवा के बहाव का सही तरह से पहचान कर अपनी कुशलता से नाव को सबसे तेज़ चलाकर लक्ष्य तक पहुंचना होता है. हवा के बहाव को उपयोग करके नाव के लिए ऊर्जा उत्पन्न की जाती है. कभी हवा के बहाव के साथ तो कभी हवा के बहाव के विपरीत नाव को ले जाना होता

है. सेलिंग प्रतियोगिता में त्रिकोणाकार मार्ग पर नाव को ले जाना होता है. इनको तीन लेग भी कहा जाता है. पहला लेग, जिसे बीत लेग भी कहा जाता है, में हवा के बहाव के 45 डिग्री में नाव को चलाया जाता है. उसके बाद दूसरे और तीसरे लेग में फिर से 45 डिग्री और 45 डिग्री में नाव को चलाया जाता है. हवा को जितनी कुशलता से उपयोग किया जाता है उतनी तेज़ गति से आप जाते हैं. सेलिंग की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप वर्ष में केवल दो बार होती है. एक समुद्र में होती है जो मुंबई में होती है उसे सी-चैम्पियनशिप कहते हैं. दूसरी प्रकार की चैम्पियनशिप होती है जो झील में होती है उसे इनलैंड चैम्पियनशिप कहते हैं. इसमें मुख्य रूप से अंतर यह होता है कि समुद्र में होनेवाले खेल में हवा और लहरों का वेग ज्यादा तीव्र होता है. समुद्र के खेल में चुनौतियाँ और साथ

ही जोखिम अधिक होता है.

आपको मिले विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के बारे में बताएं

मुझे वर्ष 2000 में राज्य सरकार से “सबसे युवा खिलाड़ी” का सम्मान प्राप्त हुआ. मेरी यादगार उपलब्धियों में नैनीताल में आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप थी जब हमने प्रतिष्ठित और सबसे पुराने याच क्लब में से एक नैनीताल याच क्लब द्वारा नैनीताल झील में आयोजित प्रतियोगिता में ब्रिटिश जमाने के नाव जिन्हें ‘ओपरेटर्स’ कहा जाता है ऐसे नाव पर हमारा टीम चैम्पियनशिप हुआ और इस स्पर्धा में हमें कांस्य पदक मिला. वो मेरा आखरी चैम्पियनशिप था.

इस खेल में इच्छुक युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

नए खिलाड़ियों के लिए अब भारत में काफी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं. हैदराबाद में टैंक बंड में स्थित दो याच क्लब काफी अच्छे हैं. सेलिंग में भाग लेनेवाले बच्चों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वे अच्छी तरह से तैरना पहले सीख लें. मुंबई में कोलाबा में नेवल सेलिंग क्लब है जो कि बहुत ही अच्छा क्लब है जहां बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं. यहाँ सेलिंग के साथ-साथ नौसेना के ड्रिल भी सिखाये जाते हैं.



देवकान्त पवार
अं.का., हैदराबाद

कुछ बातें...

अपने दिल के ज़ज्बातों से, कुछ शब्द चुरा कर लाया हूँ
इस प्रेम निवेदन को लेकर, तेरे सम्मुख मैं आया हूँ
अपने उदर का प्रेम प्रिय, मेरे अंदर भी घोलो न
कुछ बातें मैंने कह दी हैं, कुछ बातें तुम भी बोलो न.!

जो बातें मैंने कही नहीं, जो बातें तुमने सुनी नहीं
वो बातें तुम कह दो शायद, वो बातें हम सुन लें शायद
गर शब्द तुम्हारे पास न हो, मेरे शब्दों से खेलो न
कुछ बातें मैंने कह दी हैं, कुछ बातें तुम भी बोलो न.!

मैं निपट निरा ही झूठा था, जाने क्यों खुद से रुठा था
बस तुम संग मेरी आस बन्धी, वरना तो सब कुछ टूटा था
मैंने तो कहानी कह दी है, तुम झूठ ही सही पर बोलो न
कुछ बातें मैंने कह दी हैं, कुछ बातें तुम भी बोलो न.!

तुम कहो रुको मैं रुक जाऊ, तुम कहो निरंतर भागू मैं
तुम कहो अगर मैं सो जाऊ, तुम कहो निरंतर जागू मैं
गर प्रेम तुम्हारे हृदय में है, शब्दों को वाणी दे दो न
कुछ बातें मैंने कह दी हैं, कुछ बातें तुम भी बोलो न.!

तुमसे मेरी हैं दो आंखें, मेरी अगली जातक तुमसे है
तुम प्रणता मेरी हस्ति की, मेरा नाम अभी बस तुमसे है
मुझको जो प्रेम दे न सको, इनको ही तुम स्नेह दे दो न
कुछ बातें मैंने कह दी हैं, कुछ बातें तुम भी बोलो न.!



विवेक वर्मा
क्षे. का., कलबुरगी

Impact of Technology in Banking

The footprint of Technology in banks is found way back in the year 1980. Technology and automation could only be introduced in stages on account of fear of unemployment unemployment. Technology has over the period of time certainly decreased scope for more of employment especially at the branch levels. Technology adoption has made it possible to centralise the working at the controlling offices thereby reducing staff at the branch levels.

Trends in Technology Developments: As described above the banks were able to develop and adopt technology in stages. The size of nationalised banks being very large made it nearly impossible to adopt technology in one go. The other private banks and foreign banks with very less branches were able to adopt technology fast and easily.

However, with the passage of time and in order to meet the intense competition poised by other private banks, big nationalised banks have also been able to develop technology of a much higher level. The banks have hired IT professionals and have also engaged the services of other IT companies like TISCO, Infosys, WIPRO etc. The Banking sector is at the cusp of transformative change driven by disruptive technologies such as AI, digital banking, regulatory compliance management, shifting to cloud computing among others.

At present, the technologies being used are cloud banking, wearables, chat bots, biometrics, block chain technology, open banking among other. Banks are increasingly using

mobile applications as the same are cost effective and user friendly.

Role and Uses of Technology Upgradation: Introduction of technology in banks like in any other sector of the economy has immense benefits. Technology has increased efficiency, accuracy and speed of work. It has certainly enabled the banks to work faster and with lesser staff. The staff at the branches has been reduced to much extent. It is observed that the branches are even being run with 25% of the previous staff strength. Many of the jobs like Interest application, writing of main cash book, balancing of books etc. have really been made much easier. These jobs were much tedious and time consuming as well. Technology has made banking more reliable. Maintenance and retrieval of records of documents and records have become much faster and easier. Computerised banking improves the core banking system. As we all know with the introduction of Core Banking Solution (CBS) all branches have access to common centralised data and are interconnected. It has made better customer service possible. One who was known to be a customer of a branch has now become a customer of the bank.

IT has made it possible for the banks to provide a variety of digital banking services such as digital wallets, internet banking and mobile banking. Customers have been enabled to use these services to conduct transactions, check account balances and quickly access other banking services from their devices. The customers now need not visit the branches and are able to perform banking transactions

sitting at home or from their work places. Bank staff can perform few tasks from home also.

The holding of clearing houses is now a thing of the past. The physical movement of the cheques has come to an end. The cheques are passed, honoured and the accounts of the drawers are debited by the transmission of images from one bank to another. All this has resulted in significant of time saving.

ATMs have made cash withdrawals and deposits much easier. The services of making deposits and withdrawals are available 24 x 7. The long queues at the cash counters of the banks are now things of the past. People can withdraw cash from ATMs at any time of the day.

Thus, to say in a nutshell, introduction of technology has helped automate manual processes, reduce costs and increase the overall efficiency of banking operations. It has also helped to reduce errors, speed up tasks and free up employees to focus on higher value work.

The Technology in banking being of financial nature has rightly been called as "Financial Technology", better known as Fin-tech has three pivotal pillars which constitute the backbone of financial revolution. We may explain the same as under:

1. Innovation: it forms the main driving force. It propels the industry forward at unprecedented pace. The innovative solutions help in enhancing speed, efficiency and accuracy. It focuses on redefining traditional financial processes.

2. Accessibility: It implies

breaking down barriers. It ensures user friendly interfaces and mobile applications. It ensures that the financial tools are readily available to individuals worldwide. It brings the people sitting at different parts of the world together.

3. Security: Security and transparency are important to gain the faith and confidence of the customers. Advance encryption, biometric authentication and robust cybersecurity measures fortify the integrity of transactions. The user data must be well secured and safe guarded.

At present following main applications viz. UPI and Digital rupee are prevailing.

1. UPI (Unified Payments Interface): It forms advanced mobile application led payments system. It is widely used and has given a very good fillip to fintech.

2. Digital Rupee: It is an electronic version of cash. Certain amounts of cash are loaded in a card for using as a currency. It saves counting of cash at different points. It also ensures safety and security apart from saving the time taken to count and keep the cash safely.

Global Trends in Banking Systems: Globalisation has become order of the day. Every sector of the economy is getting effected. Banking sector is no exception. Basel accords are adopted by nearly all the countries of the world. NPA norms, Capital Adequacy Ratio (CAR) is also applicable to all the banks all over the world. The concepts of Cash Reserve Ratio, Statutory Liquidity Ratio, Credit Rating, Credit Worthiness and marginal interest are applicable in the similar way to all the banks all over the world.

Globalisation has made international trade easy. It has

also made sharing of technological developments easier. It has led to an overall economic, political and technological integration of the world. It has made the competition among the banks possible on international level. The exposure of banks has increased tremendously and banks are able to adopt latest technologies like phone banking, and voice mails.

International fund transfers on large scale have been made possible. The much-needed capital, expertise and new technologies, which make domestic financial system more robust and competitive, have been made possible with globalisation.



N.P.S. Sohal
AGM (Retd.)

समुद्र को प्याले में भर कर लाया आप के लिए

समुद्र को प्याली में भर कर लाया,
यह कैसे संभव है, यह सवाल आया।

समुद्र की गहराई, प्याली की सीमा से परे,
फिर भी मैंने इसे भरने की कोशिश की।

मैंने अपने हाथों से समुद्र का पानी भरा,
और प्याली में डाला, जैसे एक छोटी सी बूंद।

लेकिन जब मैंने प्याली को देखा, तो मुझे आश्चर्य हुआ,
समुद्र का पानी प्याली में नहीं आया, बल्कि मेरे हाथों में आया।
मैंने समझा कि समुद्र को प्याली में भरने की कोशिश करना,

व्यर्थ है, क्योंकि समुद्र की गहराई
और विशालता को हम कभी नहीं समझ सकते।

लेकिन मैंने यह भी समझा कि समुद्र का पानी मेरे हाथों में आया,
क्योंकि मैंने इसे अपने हाथों से भरने की कोशिश की।

इसलिए मैंने सीखा कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए,
और हमें हमेशा अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।



सुनील मिश्र
वरिष्ठ प्रबंधक
सेवानिवृत्त

समाचार केंद्र से



दिनांक 28.10.2024 को केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर शपथ ग्रहण लेते हुए बैंक के उच्च कार्यालयपालक गण.



दिनांक 12.11.2024 को कासा एवं यूनियन लीप वर्टिकल, केंका द्वारा श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक, की अध्यक्षता में इनविन्सिबल कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साथ ही इस अवसर पर श्री कबीर भट्टाचार्य, मुख्य महाप्रबंधक और श्री सुमित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक द्वारा बैंक के स्टाफ सदस्यों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई.

दिनांक 08.12.2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रायोजित डबल्यूएनसी नेवी मैरेथॉन में यूनियन बैंक के स्टाफ सदस्यों ने भी भाग लिया.

समाचार (उत्तर)



दिनांक 20.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर में सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में महिला उद्यमिता कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया.



दिनांक 19.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, गाजीपुर द्वारा “मेरा बैंक, मेरा गौरव” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक द्वारा सम्मानित किया गया। साथ ही श्री धीरेन्द्र जैन, अंचल प्रमुख वाराणसी। साथ ही श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक द्वारा बैंक के उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए एक विशेष वाहन का शुभारंभ भी किया गया।



दिनांक 12.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री बैजनाथ सिंह, अंचल प्रमुख सहित अन्य कार्यपालकगण उपस्थित रहे।

दिनांक 18.11.2024 को अंचल कार्यालय, लखनऊ में श्री अजय कुमार सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने दौरे के अवसर पर चिकित्सा जांच शिविर का शुभारंभ किया। साथ ही श्री राजेश कुमार, अंचल प्रमुख, श्री मार्कण्डेय यादव, क्षेत्र प्रमुख, श्री प्यारेलाल एवं श्री प्रदीप कुमार अवस्थी, उप अंचल प्रमुख सहित अन्य कार्यपालकगण।



दिनांक 01.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जालंधर यू जीनियस 3.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजेता छात्रों के साथ हैं श्री मनोज कुमार, अंचल प्रमुख, चंडीगढ़ तथा श्री गुरदीप सिंह, क्षेत्र प्रमुख, डॉ एस.एस. मारवाह, पूर्व अध्यक्ष पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं चांसलर सलाहकार, चंडीगढ़, विश्वविद्यालय, डॉ सौरभ लखनपाल, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष, छात्र कल्याण विंग, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी।

दिनांक 04.10.2024 को अंचल कार्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ द्वारा यू- जीनियस 3.0 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विजेता छात्रों के साथ श्री अंशज सिंह, आईपीएस, निदेशक- आयुष तथा विदेश सहयोग विभाग सहित श्री मनोज कुमार, अंचल प्रमुख, श्री संसारचंद तथा श्री अनिथ थॉमस, उप अंचल प्रमुख सहित अन्य कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।



दिनांक 27.11.2024 को श्री प्रवीण शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक तथा श्री कबीर भट्टाचार्य, मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अंचल कार्यालय, लखनऊ का दौरा किया गया। इस अवसर पर उनके द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही श्री राजेश कुमार, अंचल प्रमुख, उपस्थित रहे।



दिनांक 11.12.2024 एवं 12.12.2024 को श्री कबीर भट्टाचार्य, मुख्य महाप्रबंधक, केंका द्वारा अंचल कार्यालय, भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल सेंट्रल तथा क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर का दौरा किया गया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु स्टाफ सदस्यों को सम्मानित किया गया।



दिनांक 13.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, धनबाद द्वारा मेगा ऋण शिविर (खुदरा, एमएसएमई एवं कृषि) का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहक को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए श्री जी.एन. दास, महाप्रबंधक, कें.का., मुंबई. साथ ही श्रीमती दीपमाला लकड़ा, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री शशि कांत, उप अंचल प्रमुख, रांची.



दिनांक 19.10.2024 को अंचल कार्यालय, जयपुर द्वारा श्री विपिन कुमार शुक्ला, अंचल प्रमुख, जयपुर की अध्यक्षता में शाखा प्रबंधक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जयपुर अंचल के सभी क्षेत्र प्रमुख और शाखा प्रमुख उपस्थित रहे।



दिनांक 11.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के नकोदर तथा शाहकोट शाखा द्वारा श्री संसार चंद, उप अंचल प्रमुख, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में ओटीएस शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य और ग्राहक उपस्थित रहे।



दिनांक 19.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, धनबाद में श्रीमती दीपमाला लकड़ा, क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए श्री उमेश चन्द्र तथा श्री ब्रजेन्द्र कुमार सिंह, उप क्षेत्र प्रमुख.



दिनांक 20.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के यूएमएफबी शाखा द्वारा एमएसएमई शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहक को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान हुए श्री परमजीत सिंह, सहायक महाप्रबंधक तथा शाखा प्रमुख, यूएमएफबी शाखा।



दिनांक 23.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, पटना द्वारा बिहार शरीफ, नालंदा में मेगा ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ग्राहकों को संबोधित करते हुए श्री रणजीत सिंह, क्षेत्र प्रमुख।



दिनांक 27.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के फगवाड़ा शाखा द्वारा श्री टी.पी.एस दिवाकर, उप क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में खुदरा ऋण शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शाखा प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।

समाचार (पूर्व)



दिनांक 15.10.2024 को विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस (World White Cane day) के अवसर पर श्री निरंजन बारिक, क्षेत्र प्रमुख, भुवनेश्वर तथा श्री जीतेंद्र कुमार सामल, उप क्षेत्र प्रमुख द्वारा श्री घनश्याम मोहंता, प्रबंधक को व्हाइट केन प्रदान किया।

समाचार (पश्चिम)



दिनांक 21.11.2024 को अंचल कार्यालय, मुंबई द्वारा यू-जीनियस अंतिम चरण के आयोजन में सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ का स्वागत करते हुए श्री अभिजीत बसाक, अंचल प्रमुख, मुंबई. इस अवसर पर बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री नितेश रंजन, श्री रामसुब्रमणियन एस. श्री संजय रुद्र सहित अन्य कार्यपालक उपस्थित रहे.



दिनांक 19.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बड़ौदा द्वारा श्री पंकज द्विवेदी, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में "मेरा बैंक, मेरा गौरव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री अखिलेश कुमार, अंचल प्रमुख, सुश्री श्वेता सावे, क्षेत्र प्रमुख, सूरत, सुश्री ऋचा जाजोरिया, क्षेत्र प्रमुख, आणंद तथा श्री अंकुर सराफ, क्षेत्र प्रमुख, बड़ौदा सहित अन्य कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.



दिनांक 13.10.2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा आरजी हास्पिटल, गोवा के संयुक्त उद्यम से गोवा में आरजी मैराथन 5.0 का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि, श्री मिलिंद सोमन के साथ हैं श्री आशीष मालवीया, क्षेत्र प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य.



दिनांक 21.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा में श्री आशीष मालवीया, क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री अजय कुमार तथा श्री प्रेमशंकर वर्मा, उप क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे.

समाचार (दक्षिण)



दिनांक 22.10.2024 को श्री के. भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद तेलंगाना राज्य के माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मल्लू भट्टि विक्रमार्का से मिले और बैंक की विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की. साथ हैं श्री वी. विजय कुमार, शाखा प्रमुख.



दिनांक 29.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, ओंगोल में सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ से वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कारोबार मापदंडों की उपलब्धि हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए श्री जे नागेंद्र नाइक, शाखा प्रमुख, मेदर मेटला साथ हैं श्री सी.वी.एन. भास्कर राव, अंचल प्रमुख, विजयवाडा और श्री वी. रवि कुमार, क्षेत्र प्रमुख, ओंगोल.



दिनांक 07.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूर में सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री नवनीत कुमार, अंचल कार्यालय, बेंगलूर, श्री सुनिल वी पाटिल, क्षेत्र प्रमुख, मैसूर, श्री विशुकुमार यू., क्षेत्र प्रमुख शिवमोगगा, श्री अरुण कुलकर्णी, क्षेत्र प्रमुख हासन सहित अन्य कार्यपालक तथा स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.



दिनांक 27.11.2024 को अंचल कार्यालय, मंगलूरु द्वारा "मेरा बैंक, मेरा गौरव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ करती हुई सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ. साथ हैं श्रीमती रेणु के. नायर, अंचल प्रमुख तथा अन्य कार्यपालकगण.



दिनांक 08.11.2024 को अंचल कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी एवं सीईओ की अध्यक्षता में "मेरा बैंक, मेरा गौरव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख तथा क्षेत्र के सभी क्षेत्र प्रमुख, प्रभारी, यूबीकेसी सहित अन्य स्टाफ एवं ग्राहक उपस्थित रहे.



दिनांक 08.11.2024 को सुश्री ए. मणिमेखलै, एमडी और सीईओ की अध्यक्षता में नारी शक्ति शाखा, राजाजीनगर शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु उत्तर की महिला ग्राहकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया. साथ हैं श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख, श्री राजेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख तथा अन्य स्टाफ सदस्य.



दिनांक 09.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मछलीपट्टनम द्वारा श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साथ हैं श्री सी.वी.एन. भास्कर राव, अंचल प्रमुख, विजयवाडा, श्री के. वेकट राव, क्षेत्र प्रमुख तथा अन्य कार्यपालकगण एवं स्टाफ सदस्य. साथ ही श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक द्वारा फाउंडर्स शाखा (ई-एबी) का दौरा किया गया.



दिनांक 20.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम द्वारा श्री संजय रुद्र, कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में "मेरा बैंक, मेरा गौरव" कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साथ ही इस अवसर पर एसएचजी लोन मेला का भी आयोजन किया गया और उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित भी किया गया. इस अवसर पर श्रीमती रेणु के नायर, अंचल प्रमुख, मंगलुरु, श्री सुजित एस तारीवाळ, क्षेत्र प्रमुख, तिरुवनंतपुरम, श्री दीप्ति आनंदन, क्षेत्र प्रमुख, कोल्लम तथा सुश्री रंजिता सुरेश, क्षेत्र प्रमुख, कोट्टयम सहित स्थानीय शाखा प्रमुख उपस्थित रहे.



दिनांक 03.12.2024 को श्री अरुण कुमार, मुख्य महाप्रबंधक तथा श्री के. भास्कर राव, अंचल प्रमुख, हैदराबाद श्री के रामकृष्ण राव, आईएस, सचिव, वित्त विभाग, तेलंगाना से मिले और बैंक की विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा की.



दिनांक 09.10.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूर में सुश्री शिल्पी अगरवाल, आई.आर.ए.एस, डीआरएम, दक्षिण -पश्चिम रेलवे और श्री सी. वी. सुधीर, उप अंचल प्रमुख, अंचल कार्यालय, बेंगलूरु द्वारा रेल कार्मिकों के वेतन खातों के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए. साथ हैं श्री सुनिल वी पाटिल, क्षेत्र प्रमुख मैसूर तथा अन्य कार्यपालकगण.



दिनांक 08.11.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, राजमंडी द्वारा श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में “मेरा बैंक, मेरा गौरव” कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साथ ही उत्कृष्ट कार्य निष्पादन हेतु शाखा प्रमुखों को सम्मानित किया गया. इस अवसर पर श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख, विशाखपट्टणम सहित अन्य कार्यपालकगण तथा स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे.



दिनांक 09.11.2024 को अंचल कार्यालय, विशाखपट्टणम में श्री रामसुब्रमणियन एस., कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में “मेरा बैंक, मेरा गौरव” कार्यक्रम का आयोजन किया गया. साथ ही श्रीमती शालिनी मेनन, अंचल प्रमुख.



दिनांक 26.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद-सैफाबाद में श्री कारे भास्कर राव अंचल प्रमुख, हैदराबाद की अध्यक्षता में एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया. साथ ही श्रीमती सोनालिका, क्षेत्र प्रमुख, श्री जगदीश लेपाक्षि तथा श्री रवि मारेम, उप क्षेत्र प्रमुख, तथा श्री सुब्रमण्या सी जी, एमएलपी प्रमुख.



दिनांक 12.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, मैसूरु में श्री सुनिल वी पाटिल, क्षेत्र प्रमुख, मैसूरु एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री सुदर्शन भट्ट, मुख्य महाप्रबंधक, केंका, श्री नवनीत कुमार, अंचल कार्यालय बेंगलूरु, उपस्थित रहे.



दिनांक 12.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (उत्तर) के नारी शक्ति शाखा, राजाजीनगर में महिला उद्यमियों के साथ श्री सुदर्शन भट्ट, मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख, श्री राजेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख, बेंगलूरु उत्तर उपस्थित रहे.



दिनांक 13.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूरु (उत्तर) के पीण्या शाखा में एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर ग्राहक को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान करते हुए श्री सुदर्शन भट्ट, मुख्य महाप्रबंधक, केंका. साथ ही श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख, श्री राजेंद्र कुमार, क्षेत्र प्रमुख, बेंगलूरु (उत्तर) एवं अन्य स्टाफ सदस्य.



दिनांक 30.11.2024 को अंचल कार्यालय, बेंगलुरु में श्री सुमित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर, आरसीएलओ, जेडसीएलओ के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई. साथ ही श्री नवनीत कुमार, अंचल प्रमुख.



दिनांक 21.12.2024 को अंचल कार्यालय, हैदराबाद द्वारा 'प्रवासी हमारा गौरव' के तहत बैंक के स्थानीय एन.आर.आई ग्राहकों हेतु ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में श्री कारे भास्कर राव, अंचल प्रमुख, श्री सुमित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, श्री एम. अरुण कुमार, उप अंचल प्रमुख, श्री यु.वि.रजनिकांता राव, क्षेत्र प्रमुख, पंजागुट्टा, श्री कल्याण वर्मा, क्षेत्र प्रमुख, कोटी, श्री राजेश सिन्हा, सहायक महाप्रबंधक उपस्थित रहे.



दिनांक 10.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्लम में श्रीमती रेणु के नायर, अंचल प्रमुख, मंगलूरु की अध्यक्षता में शाखा प्रमुखों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस अवसर पर श्री सत्यनारायण रेड्डी तथा श्री जे. सुब्रमणियम, उप क्षेत्र प्रमुख सहित स्थानीय शाखा प्रमुख उपस्थित रहे.



दिनांक 18.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम के नीरपारा में मेगा एसएचजी मेला का आयोजन किया गया. इस अवसर पर सुश्री सुकन्या सुकुमारन, अध्यक्ष, चेंबु पंचायत, श्री बिरु थॉमस, अध्यक्ष, आमेबलूर पंचायत, श्रीमती रेणु के नायर, अंचल प्रमुख, मंगलूरु, श्री टी एस श्याम सुंदर, क्षेत्र प्रमुख तथा श्री महालिंग देवाडिग, उप क्षेत्र प्रमुख उपस्थित रहे.



दिनांक 19.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, एर्णाकुलम में "प्लांट फॉर मदर अर्थ" अभियान के तहत केंद्रीय विद्यालय के छात्रों को पौधे वितरित करती हुई श्रीमती रेणु के नायर, अंचल प्रमुख, मंगलूरु. साथ ही श्री टी एस श्याम सुंदर, क्षेत्र प्रमुख, श्री सुनिल कुमार वी एस, प्रचार्य, श्री ए बालसुब्रमणियन, उप क्षेत्र प्रमुख, एर्णाकुलम तथा अन्य.



दिनांक 20.12.2024 को अंचल कार्यालय, मंगलूरु में श्री सुमित श्रीवास्तव, महाप्रबंधक, केंका द्वारा रिलेशनशिप मैनेजर, आरसीएलओ, ज़ेडसीएलओ के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की गई।



दिनांक 03.12.2024 को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर पलुकु मूक-बधिर विद्यालय के बच्चों को श्री ए. विश्वेश्वर राव, क्षेत्र प्रमुख, राजमंडी द्वारा तौलिया एवं मिठाई वितरित की गई।



दिनांक 14.12.2024 से 16.12.2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय, हासन द्वारा श्री अरुण कुलकर्णी, क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में सर एम. विश्वेश्वरय्या कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर एसोसिएशन के सहयोग से ड्रीम-2024, गृह ऋण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय आरएलपी और ऋण विभाग प्रमुख सहित अन्य स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।



दिनांक 20.12.2024 से 22.12.2024 तक क्षेत्रीय कार्यालय, हासन द्वारा श्री अरुण कुलकर्णी, क्षेत्र प्रमुख की अध्यक्षता में हासन जिला कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट एसोसिएशन के सहयोग से बिल्ड टेक-2024 में रिटेल आउटरीच कैम्पेन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय शाखा/ कार्यालय स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे।



दिनांक 24.12.2024 को क्षेत्रीय कार्यालय, विशाखपट्टणम द्वारा 'प्रवासी हमारा गौरव' के तहत बैंक के स्थानीय एन.आर.आई ग्राहकों हेतु ग्राहक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए श्री आर नरसिंह कुमार, क्षेत्र प्रमुख, श्री बी.जी. आर. नायडू, उप क्षेत्र प्रमुख।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'यूनियन धारा' का जुलाई-सितंबर 2024 अंक एक समृद्ध और विविध विषयवस्तु से परिपूर्ण एक उत्कृष्ट अंक है। यह अंक न केवल बैंक की गतिविधियों और उपलब्धियों का दस्तावेज है, बल्कि यह बैंकिंग, वित्त, सामाजिक सरोकार, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और कर्मचारी विकास जैसे विषयों पर भी जानकारीपूर्ण लेख प्रस्तुत करता है। इस अंक की विशेषता इसका संतुलित संपादकीय दृष्टिकोण है, जिसमें प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती ए. मणिमेखलाई का प्रेरणादायक संदेश शामिल है। संपादकीय में देश के विकास हेतु बैंकिंग प्रणाली की भूमिका पर गहन विचार किया गया है। 'हेडलाइन' से लेकर 'अनप्लग्ड' तक के खंडों में प्रकाशित लेख पाठकों के ज्ञानवर्धन के साथ-साथ प्रेरणा देने वाले हैं। विशेष रूप से "Redefining Role of CSAs", "AI and its effects on India", "Decentralized Finance" Deewj "Risk Associated with Investing" जैसे विषयों पर आधारित लेख अत्यंत प्रासंगिक और समसामयिक हैं। साथ ही, स्वतंत्रता दिवस पर विशेष प्रस्तुति, महिलाओं के लिए बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, पर्यावरण हितैषी उत्पादों और आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रकाश डालने वाले लेख इस अंक की विविधता को समृद्ध बनाते हैं। इस अंक का कला निर्देशन, भाषा शैली और मुद्रण गुणवत्ता भी अत्यंत सराहनीय है। संपादकीय टीम विशेष रूप से श्रीमती गायत्री रविकिरण और श्री ए. के. विनोद के नेतृत्व में एक उत्कृष्ट अंक प्रस्तुत करने हेतु बधाई की पात्र है। कुल मिलाकर, 'यूनियन धारा' का यह अंक न केवल कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायी है, बल्कि समग्र रूप से बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक दिशादर्शक प्रकाशन के रूप में सामने आता है। इस सफल पड़ाव के लिए प्रधान संपादक श्री चंद्र मोहन मिनोचा जी और सभी संपादकीय सलाहकारों सहित संपादक महोदया बधाई एवं साधुवाद की पात्र हैं।

शैलेश शुक्ला

सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पन्ना (मध्य प्रदेश)
एवं उप प्रबंधक (राजभाषा), एनएमडीसी लिमिटेड, हीरा खनन परियोजना

द्विभाषी गृह पत्रिका यूनियन धारा का सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर अप्रैल - जून, 2024 अंक हमें प्राप्त हुआ। पत्रिका में सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर विभिन्न लेख पढ़कर जानकारी बढ़ी। आदरणीय कार्यपालक निदेशक श्री पंकज द्विवेदी का लेख "धोखाधड़ी निवारण में प्रौद्योगिकी" अत्यंत ज्ञानवर्धक है। साथ ही श्री राजेश कुमार अंचल प्रमुख लखनऊ का लेख, "डेटा का लोकतंत्रीकरण" भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश में जानकारी के उद्देश्य से विशेष महत्व रखता है। जानकारी की दृष्टि से निश्चित ही यह पत्रिका सटीक है। मैं व्यक्तिगत रूप से संपादक मण्डल को बधाई देता हूँ। पत्रिका के आगामी अंकों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

मनोज कुमार

अंचल प्रमुख, चंडीगढ़

यूनियन धारा का अप्रैल-जून 2024 अंक पढ़ा। "सूचना प्रौद्योगिकी" पर केंद्रित यह अंक अत्यंत प्रासंगिक और भविष्यगामी है, जो बैंकिंग संचालन और ग्राहक सेवा में आईटी की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करता है। इस अंक में रियल-टाइम अनुप्रयोगों, ग्राहक अंतर्दृष्टि, और आधुनिक बैंकिंग की चुनौतियों जैसे विषयों पर जो जानकारी दी गई है, वह पाठकों के लिए बेहद उपयोगी और व्यावहारिक है। यह अंक बैंकिंग और आईटी के संगम को समझने के इच्छुक लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें बहुत ही सरल शब्दों में दिखाया गया है कि कैसे तकनीक पारंपरिक तरीकों को बदल रही है और बैंकिंग उद्योग को अधिक कुशल और ग्राहक-केंद्रित बना रही है। कुल मिलाकर यह एक संग्रहणीय अंक बन पड़ा है। संपादक समूह को ऐसे सुंदर-व्यवस्थित एवं संग्रहणीय अंक प्रकाशित करने के लिए विशेष साधुवाद।

राकेश चौरसिया

राजभाषा, भारतीय स्टेट बैंक, एर्णाकुलम



यूनियन धारा के अप्रैल-जून अंक की सॉफ्ट प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका को पढ़ना प्रारम्भ किया तो पढ़ता ही चला गया। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित इस अंक में समाहित हर सामग्री संपादन की कुशलता की पुष्टि करती है। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर सुरक्षा के साथ-साथ फिनटेक बैंकिंग और ए-आई के प्रयोग और प्रभाव जैसे ज्वलंत विषयों पर आधारित उत्कृष्ट आलेख पत्रिका की श्रेष्ठता को सिद्ध करते हैं। आज शाखा रहित बैंकिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विषय के बारे में हर व्यक्ति को जानना आवश्यक है जिनपर रोचक जानकारी दी गई है। वर्तमान समय डिजिटल युग के साथ तीव्र गति से विकास की सीढियाँ चढ़ रहा है परन्तु इसके साथ ही जोखिम भी बढ़ गया है। इन अप्रत्याशित खतरों से बचने के लिए हमारी जानकारी और ज्ञान की परिधि का विस्तार भी आवश्यक है जो इस अंक के माध्यम से संभव है। कविताओं का समावेश इसकी विविधता और रोचकता को द्विगुणित कर देता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह अंक पाठकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। हमेशा की भांति यह अंक भी संग्रहणीय है। कुशल संपादन हेतु मैं यूनियन धारा के संपादक मंडल को बधाई प्रेषित करता हूँ।

ज्ञानचंद मर्मज्ञ

बेंगलूरु वरिष्ठ साहित्यकार

पूर्व सदस्य: टेलीफोन सलाहकार समिति, बेंगलूरु, भारत सरकार

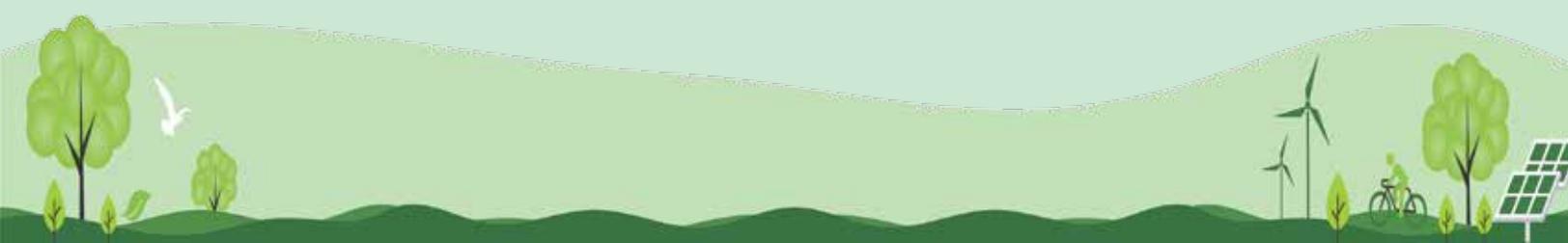
आज यूनियन धारा के सितंबर 2024 अंक को देखने एवं पढ़ने का मौका मिला। पत्रिका का मुख्य पृष्ठ काफी सुंदर है जिसे देखते ही मन में सकारात्मकता का संचार होता है पत्रिका में सम्मिलित लेख अद्यतन एवं ज्ञानवर्धक है। हमें गर्व है कॉलम में स्टाफ की उपलब्धि निश्चय ही अन्य स्टाफ सदस्यों को आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करेगा। पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न गतिविधियों के चित्र हमारे बैंक के विशाल रूप को प्रदर्शित करता है साथ ही "मेरा बैंक मेरा गर्व" के टेग लाइन को सार्थक बनाता है। इस सुंदर पत्रिका के प्रकाशन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाईयाँ। आशा है कि अगला अंक और कुछ विशेष लेकर आएगा। प्रतीक्षा के साथ।

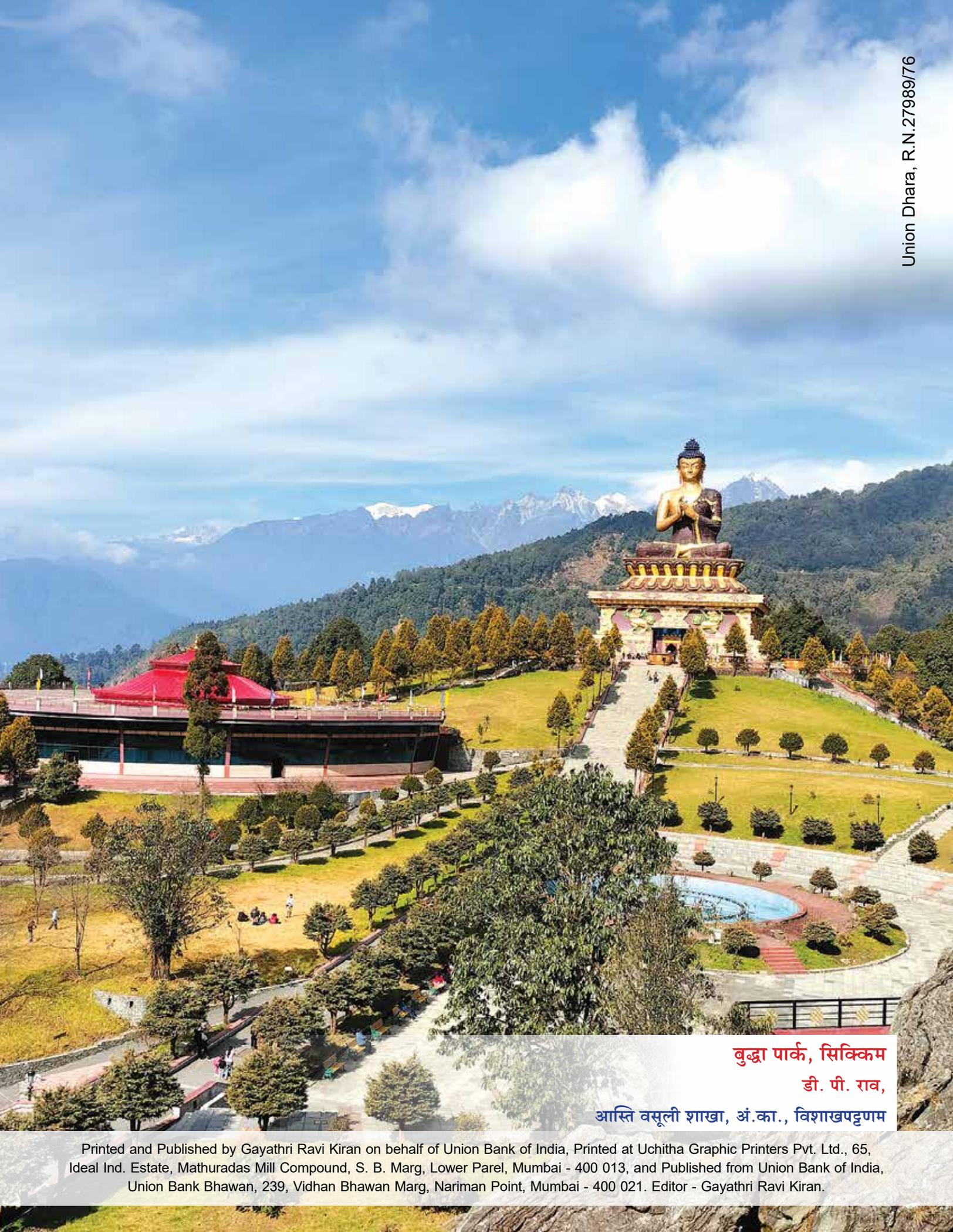
सुजित एस तारीवाळ

क्षेत्र प्रमुख

क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 106 वां स्थापना दिवस समारोह





बुद्धा पार्क, सिक्किम

डी. पी. राव,

आस्ति वसूली शाखा, अं.का., विशाखपट्टणम